खण्ड-193, अंक-2
शनिवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(15 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १५ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३१९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री

ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुट बिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलालसहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लुत्फ अली खां, श्री

लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल, रावत श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, (राहत मौलाही) श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

कतिपय कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। उनमें कुछ दस मिनट पहले आये या बीस मिनट पहले आये और कुछ अभी दो मिनट पहले आये। तो दो मिनट पहले जो आये हैं उनको मैं पढ़ भी नहीं सका हूं। उनको तो मैं देख कर उन पर सोमवार को फैसला दूंगा। दो जो पहले आये हैं जिनमें एक राजनारायण जी का और एक श्री बंशीधर शुक्ल का है उनको मैं लिये लेता हूं।

नदी के गन्दे पानी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---बंशीधर शुक्ल जी का इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पहले भी आ चुका था कि किसी नदी का पानी गन्दा हो गया है, जिसकी वजह से जानवर मर रहे हैं। अब फिर से दोबारा उन्होंने दे दिया है। दोबारा कोई कामरोको प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता, जबकि एक बार नामंजूर हो चुका हो।

सोशलिस्ट पार्टी के कार्य कर्ताओं की जमका ग्राम में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है...

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष---सुनाता हूं, लेकिन उसमें उस भाग को, जिसमें खामख्वाह किसी के ऊपर आक्षेप लगाया गया है, मैं छोड़ दूंगा। पूरा पढ़ना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि उसमें आक्षेप है। किसी प्रस्ताव में किसी के ऊपर चार्जेज लगाना या मोटिव इम्प्यूट करना---यह चीज नहीं होना चाहिये। नियम ७९ के इस सम्बन्ध के निम्न शब्द हैं---

"It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements."

तो कोई प्रस्ताव इस किस्म का नहीं हो सकता जिसमें ये बातें मौजूद हों। अगर कहीं कोई वाकया हुआ तो उसके कारण बताते हुए नतीजे भी उसमें लाये जायं, ऐसी बात भी प्रस्ताव में नहीं आ सकती। ऐसा कामरोको प्रस्ताव भी अवैध है। तो मैं उस भाग को नहीं सुनाता हूं। लेकिन चूंकि विषय ऐसा है जिस पर अगर माननीय मंत्री जी को सूचना हो तो उसे देना उचित होगा इसलिये वह विषय मैं सदन में पढ़ देता हूं।

"सोशलिस्ट पार्टी के सर्वश्री करुणाशंकर दीक्षित, नन्दकिशोर नाई, रामभरोसे यादव, देवेन्द्रप्रसाद व सेंगर आफिस, मंत्री, अपरान्ह में प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के आगामी ३०, ३१ मार्च के अधिवेशन के सम्बन्ध में एक मोटरगाड़ी द्वारा प्रचार कर रहे थे। जब ये लोग जमका ग्राम में पहुंचे और वहां पर प्रचार करने लगे तो वहां पर काफी जनता एकत्र हो गयी। किन्तु वहां पर उपस्थित अचलगंज थाने के एस० ओ० ने उपरोक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और रस्से से बांध कर थाने ले गये तथा मोटरगाड़ी को मय ड्राइवर के शाम तक जमका ही में रखा।

इसके बाद का जो वाकया है उसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अन्त में ये शब्द है "जिसके कारण जनता में भीषण क्षोभ व रोष का वातावरण छा गया है।

अतः सदन इस आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्यस्थगित करता है।"

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि अगर उनको कोई सूचना सदन को देनी हो तो दे दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---श्रीमन्, वह घटना इस प्रकार है। कल २ बजे उन्नाव से ८ मील दूर जमका गांव में जो अचलगंज थाना है उसमें एक मीटिंग होने वाली थी। जिस समय माननीय माल मंत्री चकबन्दी पर भाषण करने वाले थे और चकबन्दी के सिलसिले में ही वह मीटिंग आयोजित को गयी थी, वहां कुछ लोग एकत्र हुए। माल मंत्री पहुंचे नहीं थे कि इतने में ५ समाजवादी दल के कार्यकर्ता श्री करुणाशंकर दीक्षित के साथ, अपने लाउड स्पीकर के साथ पहुंचे और मीटिंग में उन्होंने बोलना शुरू किया और नारे भी लगाने लगे और कोशिश की

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कि मीटिंग डिस्टर्ब हो। वहां के थानेदार मौजूद थे, उन्होंने उनसे कहा कि मीटिंग होने जा रही है, किसी मीटिंग को इस तरह से डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया। जो अध्यक्ष थे मीटिंग के, उन्होंने लिखित एक कम्पलेंट सब-इंस-पेक्टर को दी कि ये हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसमें डर इस बात का है कि झगड़ा हो जायगा। एस० आई० के कहने पर जब उन लोगों ने न माना तो उनको जाब्ता फौजदारी की धारा १५१ में एस० आई० ने गिरफ्तार किया। उसके बाद साढ़े तीन बजे के करीब माल मंत्री जी भी पहुंचे, कलेक्टर और एस० पी० भी पहुंचे और जब एस० पी० और कलेक्टर को मालूम हुआ कि इस तरह से गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि उनको उन्नाव ले जाओ और उन्नाव भेज दिया गया। यह घटना हुई।

श्री अध्यक्ष---उन्नाव में क्या किया? छोड़ दिया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उन्नाव में उनको ले गये, उन पर मुकदमा चल रहा है १५१ के मातहत।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा हो तो अपनी जानकारी के लिए कुछ गृह मंत्री जी से पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह---गृहमंत्री जी ने कहा कि शान्ति भंग होने का अन्देशा था और यह भी कहा कि १५१ जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार किया गया। शान्ति भंग होने के लिए दफा १०७ और ११७ हैं। अगर कोई जुर्म शदीद, किसी काग्निजेबिल आफेंस का अन्देशा है तब दफा १५१ लगायी जाती है। तो महज शान्ति भंग होने की सूचना है या उसमें काग्निजेबिल आफेंस के कमिट होने का अन्देशा था?

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री को सूचना हो तो बताएं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना इतनी है कि जो मीटिंग के चेयरमैन थे उनकी एक लिखित शिकायत पर और जो स्थिति वहां थी उसको देख कर एस० आई० ने जाब्ता फौजदारी की धारा १५१ में उनको गिरफ्तार किया, यह सूचना है। उनके ऊपर अब केस चल रहा है।

श्री राजनारायण---मैं कुछ निवेदन करूं?

श्री अध्यक्ष---मैं निवेद न करने की इजाजत नहीं देता, अगर उस सम्बन्ध में आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---हमारा कहना यह है कि सोशलिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता गये थे लाउड स्पीकर भी उनके पास था, मोटरगाड़ी भी उनके पास थी। यह तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग की चर्चा माननीय गृह मंत्री ने की तो उनकी मीटिंग नहीं हो रही थी, हमारे लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपका कथन है। १५१ दफा के मातहत उन पर मुकदमा चल रहा है, यह उन्होंने बताया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस तरह तो असेम्बली को आते हुए हमको १५१ में गिरफ्तार कर सकते हैं। वह १५१ दफा तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव है, वह कोई ऐसा अपराध नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अगर मुकदमा चलेगा तो उस वक्त देखा जायगा।

श्री राजनारायण---इस तरह से तो सारे सूबे की शान्ति को भंग कर सकते हैं। हमारी मोटर थी, लाउड स्पीकर था वह सब बन्द है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कुछ तो उनसे आप पूछ लें।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो पूछ लिया और वह काफी है।

श्री राजनारायण---हमारी मोटर वहां क्यों है, हमारा लाउड स्पीकर वहां क्यों है, वह पांच आदमी.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, जब उनके पास सिर्फ मोटर और लाउडस्पीकर था, लाठी, डंडा, बन्दूक, तमन्चा, तलवार कोई चीज नहीं थी तो....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये। यहां सदन की पद्धति के अनुसार ही बात होनी चाहिये। दो दलों में अगर कोई झगड़ा होता है तो कानून के हिसाब से अदालत में जो उनका मामला जाता है उसकी बहस यहां नहीं की जाती क्योंकि सबूत में ये सब चीजें आ सकती हैं। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि इस तरह की बहस यहां पैदा हो जिसका असर अदालत में मुकदमे पर पड़े।

श्री राजनारायण---जवाब तो दे दें, कोई मर्डर का केस नहीं है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, जब मामला सब-जुडिस होता है तो वह चाहे छोटा हो या बड़ा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें।

श्री राजनारायण---मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप अपने स्थान को ग्रहण करें।

अब माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री अपने अनुदान पेश करेंगे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश स प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१---सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं.....

श्री राजनारायण---मेरा एक प्रश्न है, इस पर आपकी कोई व्यवस्था हो कि जब तक कोर्ट काग्निजेन्स न ले तब तक वह सब-जुडिस नहीं होता।

(श्री गिरधारी लाल और श्री राजनारायण एक साथ बोल रहे थे।)

श्री अध्यक्ष---यह सब मुझको मालूम है। यह मामला कोर्ट में आ सकता है इसलिये मैं यहां बहस नहीं करने दूंगा।

श्री राजनारायण---फिर हमको तो लाचारी है अगर हम अपने जज्बात को भी व्यक्त न कर पायें।

श्री अध्यक्ष -आप कृपा कर बैठें।

श्री राजनारायण---मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप कृपा कर बैठें।

श्री राजनारायण---मेरा निवेदन तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठें।

(इस समय सर्वश्री राजनारायण, रामस्वरूप वर्मा तथा उग्रसेन, तीनों एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री राजनारायण--मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये नहीं तो मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा।

श्री राजनारायण---मेरे प्रश्न का गृह मंत्री उत्तर तो दें।

श्री अध्यक्ष---मैं फिर कहता हूं कि आप कृपा कर बैठिये नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा।

श्री राजनारायण---तो ऐसी अवस्था में मेरा इस सदन में रहना बेकार है जब हम अपने अधिकार का भी उपयोग नहीं कर सकते।

(इसके पश्चात् श्री राजनारायण और उनके साथी सदन का त्याग करके चले गये।)

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष महोदय से अगर यह कहे कि मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं तो क्या सदस्य की बातों को बिना जाने बूझे ही अध्यक्ष महोदय यह रूलिंग दे सकते हैं कि आप अपनी जगह पर बैठें ?

श्री अध्यक्ष---बगैर मेरे नाम पुकारे हुये कोई सदस्य बोल ही नहीं सकते। जबतक प्वाइंट आफ आर्डर न हो तब तक मैं किसी के आग्रह से उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। 'मैं निवेदन करना चाहता हूं' ऐसी यदि कोई इच्छा प्रकट करे तो यह समय ऐसे निवेदन का नहीं है। निवेदन वह मेरे कमरे में कर सकते हैं। प्वाइंट आफ आर्डर या व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया तब वह मैंने सुन लिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह था कि कोई माननीय सदस्य सरकार के पास बार-बार उस सम्बन्ध में निवेदन करते हैं और आपके पास कामरोको प्रस्ताव भेजते हैं, वह एलाउ नहीं होता और सरकार उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कोई उत्तर नहीं देती तो फिर उस हालत में कैसे क्या किया जाय ?

श्री अध्यक्ष---यहां पर नियम के अनुसार काम होता है। किसी सदस्य को इस बात का अधिकार नहीं है कि हर प्रस्ताव में दूसरे को बेईमान लिखे, दूसरे को लिखे कि दूसरे ने इस नीयत से काम किया। अगर यह बात किसी प्रस्ताव में आती है तो वह प्रस्ताव अवैध हो जाता है। मैंने उसको अवैध करार दिया था। लेकिन बाकी भाग मैंने पढ़ कर भी सुना दिया था। मैंने यह सोचा कि चूंकि महत्व का विषय है इसलिये अवैध होते हुये भी मैंने उक्त विषय पर प्रश्न पूछने की इजाजत दी। उसके ऊपर अगर बहस शुरू हो जाती है तो मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तकलीफ है और मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन नहीं करना चाहता था। मैं तो दूसरे विषय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था। बार-बार हमारे आग्रह को आपने ठुकरा दिया। उसके लिये तो राजनारायण सिंह जी ही काफी थे। हमारा तो दूसरा विषय था।

श्री अध्यक्ष--वह दूसरा विषय था लेकिन उस समय बार-बार राजनारायण जी खड़े हो रहे थे और मुझे इस प्रकार आठ दस आदमियों का डिस्टरबेंस करना पसन्द नहीं हो सकता है। आपके दिल में क्या चीज है, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन वह बार-बार गृह मंत्री, मंत्री जी कह रहे थे। मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को पुकारा था कि वे अपने अनुदान पेश करें तब उन्होंने अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पढ़ना शुरू कर दिया और वह अपना भाषण जारी रख रहे थे। जब यह सब बातें एक साथ हो रही थीं तो पहले जो डिसआर्डर हो रहा था उसे खत्म करना आवश्यक था। पहले मैंने उसे खत्म किया और जब श्री राजनारायण जी तथा अन्य सदस्य सदन छोड़कर चले गये तब मैंने आपको मौका दिया जबकि शान्ति कायम हो गई थी।

श्री शिवप्रसाद नागर--अध्यक्ष महोदय, दफा १५१ पुलिस की दफा है, कोर्ट की नहीं है। आपने कहा कि यह मामला सबजुडिस है दफा १५१ तो पुलिस गिरफ्तारी के लिये इस्तेमाल करती है और कोर्ट में सवाल नहीं आता है। जब कोर्ट में मामला ले जाया जाता है तो दफा १०७ लगती है तो यह मामला सबजुडिस कैसे हुआ जैसा कि आपने फरमाया। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा कि यह मामला अदालत में जायगा और जो मामला अदालत में जाने वाला है उस पर यहां बहस नहीं हो सकती है क्योंकि उस पर असर पड़ सकता है, चाहे मामला सबजुडिस हो या न हो। मैं निश्चित कानूनी ढंग से नहीं कह सकता कि वह इस समय सबजुडिस हो ही गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जाइये, आप बहस करना चाहते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा उनके कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पढ़ने की प्रार्थना

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--हमने जो प्रस्ताव रखा है उसे आप पढ़ तो दीजिये। आप पढ़ने से क्यों इन्कार करते हैं? नदियां खराब हो रही हैं, तमाम आदमी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। हम विनय करते हैं आप सुनते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठ जाइये।

श्री बंशीधर शुक्ल--नहीं श्रीमन्, दो नदियां खराब हो गई हैं और हजारों आदमी तथा जानवर मरे जा रहे हैं। हमने प्रस्ताव रखा वह फेल हो गया। हम कहते हैं कि आप पढ़कर तो सुना दें।

श्री अध्यक्ष--आपकी बात सुन ली गई।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों पर भाषणों के लिये समय निर्धारण

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि आज जो चारों ग्रांटस ३१,३२,३३, और ४७ हैं वह एक साथ प्रस्तुत की जांय और जो कट-मोशन पेश करते हैं उनको २० मिनट का समय और जो लोग विवाद करते हैं उनको १० मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह सबको स्वीकार है।

श्री झारखंडेराय द्वारा अपने विषेशाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने आपके पास भेजा था, उसके बारे में क्या हुआ ? वह लिया जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---मैंने आपको सूचना दे दी थी कि आपके प्रश्न को मैंने नामंजूर कर दिया है और यह सूचना आपके पास पहुंच गई थी । इसके बाद आपने और भी कागजात भेजे जो आज ही भेजे और जब शायद आप दे रहे थे इतने में ११ बज गये । आपको तो मालूम है कि वह नामंजूर हो चुका है ।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३१---लेखा शीर्षक ५०---सार्वजनिक निर्माण-कार्य---निर्माण-कार्यों पर लागत, अनुदान संख्या ३२---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य---केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक-निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य---निर्माण कार्यों पर लागत के अंतर्गत ५,७०,९८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क-निधि के लेखे से वित्त पोषित)---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १३,०४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ७६,९१,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी लेखा के अन्तर्गत ८,४३,६५,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में इस वक्त सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा । इस विभाग का जो यह अनुदान है यह नया अनुदान नहीं है । यह अनुदान हमेशा आता है हां, संख्याओं में जरूर अन्तर है । इतना मैं जरूर बताऊंगा कि इस वक्त जो हमारी दूसरी योजना है हम उसके तीसरे वर्ष में इस समय चल रहे हैं । उसी का अनुदान खास तौर से यह हमारे सामने रखा गया है । इसकी कुछ संख्यायें हैं, मैं उनके संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

जहां तक सड़कों या पुलों का संबंध है उनका किसी भी राष्ट्र के अन्दर वैसा ही स्थान है जैसा कि शरीर के अन्दर नाड़ी का स्थान होता है । शक्ति के संचार के लिये जिस तरह से नाड़ियों का स्वस्थ और मजबूत रहना आवश्यक है उसी तरह से आधुनिक युग के अन्दर किसी भी राष्ट्र में सड़कों और पुलों का होना आवश्यक है जिससे हर एक व्यक्ति के आने जाने और अपनी उपज को लाने ले जाने की पूर्ण व्यवस्था हो । उससे हमारी माली हालत और हमारी सभ्यता भी ऊंचे उठती है । यह योजना का युग है और इन योजनाओं के अन्दर से हमारा पूरा राष्ट्र गुजर रहा है । हमारा सूबा भी उसमें चल रहा है । इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुये सड़कों को बहुत ऊंचा स्थान इस योजना के अन्दर दिया गया है । अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था । उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय ने यह कहा था कि सिर्फ यही नहीं कि इन सड़कों पर नागरिक चलते हैं बल्कि इन सड़कों पर हमारी तरक्की भी चलती है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी योजना में सड़कों और पुलों का बहुत ऊंचा स्थान है । इस बात को देखते हुये हमारी सरकार हमेशा इस बात पर सजग रही और उसने हमेशा इस बात की कोशिश की जितने भी अपने पास साधन हैं, शक्ति हैं उनके मुताबिक उचितरूप से सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाय और सड़कों के निर्माण के लिये पूरी-पूरी कोशिश की गई । हमारे प्रान्त के अन्दर सन् १९४६ में जिस वक्त कांग्रेस ने हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ली सब मिलाकर ९३८७ मील सड़कें थी । जिसमें कुछ सड़कें करीब ४,९०० मील निर्माण विभाग के पास थीं । उस वक्त फर्स्ट फेज के जरिये से कुछ प्रोग्राम बना और उसके मुताबिक एक काम हमारे प्रान्त में सड़कों पर चालू हुआ । उसी तरीके से वह काम चल रहा है । मैं इस वक्त उसके इतिहास के डिटेल में जाना नहीं चाहता लेकिन सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि उसी तरीके से बराबर वह काम चल रहा है और हमारे प्रदेश के अन्दर इस वक्त १२१८५ मील पक्की सड़कें हैं । जिसमें से १०५५५ मील सड़कें यू० पी०, पी० डब्ल्यू० डी० की देख-रेख के अन्दर हैं जिनके रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी यू० पी०, पी० डब्ल्यू० डी० के पास है । इस बात को अगर देखा जाय तो दुगुने मील सड़कों की जिम्मेदारी हमारे प्रान्त की सरकार के हाथ में है जिसको वह ठीक तरीके से निभा रही है ।

जहां तक इस योजना का संबंध है मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त हम उस योजना के तीसरे वर्ष में चल रहे हैं । इसलिये इन २ वर्षों के अन्दर हमारे प्रदेश में ६ करोड़ १० लाख रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च हुआ । पांच साल की पूरी योजना जो इस वक्त चल रही है वह १६ करोड़ १४ लाख की है । इसके अन्दर कुछ काम वह भी शामिल है जो पहली पंचवर्षीय योजना का अधूरा काम रह गया था । यह स्वाभाविक है कि इस तरह का काम हमेशा चलता रहता है । तो जो काम पहले अधूरा था उसको भी पूरा किया गया और उस काम को पूरा कर रहे हैं ; कुछ नया काम भी हाथ में लिया है । कुछ काम अभी भी अधूरा है और कुछ नया काम शुरू करने की योजना पर हम विचार कर रहे हैं, इस तरीके से इन पिछले दो वर्षों के अन्दर ६ करोड़ १० लाख रुपया खर्च हुआ है जिसमें ज्यादातर वह काम है जो पहली पंचवर्षीय योजना का अधूरा रह गया था । उस तमाम काम को पूरा करने की कोशिश की गई । इन कामों को पूरा करने में हमारा अनुमान ६ करोड़ ५० लाख रुपया खर्च करने का था, लेकिन अभी तक हमारा ६ करोड़ १० लाख रुपया खर्च हुआ है ।

[श्री गिरधारी लाल]

मैं इन बातों के अलावा इतना और बतलाना चाहता हूं कि १९५६-५७ में जो काम हुआ है उसमें ३७३ मील पक्की सड़कें लेकर उनको पूरा किया गया है और २४९ मील वह सड़कें थी जो चालू थी, उनका सुधार और पुनर्निर्माण किया गया है और साथ ही ६ खास और बड़े पुल हमारे प्रान्त में बनाये गये। १९५७-५८ में २९० मील नयी सड़कें बना कर जनता के सुपुर्द की गयीं अर्थात् उन पर लोगों का आना जाना चालू हो गया और २३१ मील सड़कों का सुधार और पुनर्निर्माण किया गया और १८ पुल हमारे प्रान्त में अब तक बनाये गये। सन् १९४६ से लेकर आज तक हमारे प्रान्त में सब मिला कर ४७ पुल बनाये गये हैं। मैं १९५८-५९ का जो कार्यक्रम है उसके बारे में यह बतलाना चाहता हूं कि १ करोड़ २ लाख ८ हजार रुपया इन सड़कों पर व्यय करने का विचार किया जा रहा है जिससे कि अधूरी सड़कों का निर्माण होगा। नई सड़कों में खास हैं अल्मोड़ा-रामेश्वर सड़क, बलिया-बैरिया-रावर्टसगंज सड़क, देहरादून में कालसी-लखबार सड़क, फैजाबाद में अकबरपुर-दोस्तपुर सड़क और एटा जिले में एटा-अमनपुर-सहाबर सड़क। इनकी पूरी लम्बाई ३३६ मील है और इन पर १९५९ तक करीब १० लाख रुपया खर्च होगा। मैंने जैसा कहा, हम हर वर्ष कुछ नये कामों को लेते हैं और पुराने कामों को पूरा करते हैं। इसी तरह से हम इस वर्ष इन सड़कों को लेंगे और १९५८-५९ में इन सड़कों पर १० लाख के करीब खर्च होगा।

इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आज के युग में जब हमारे भाव, हमारा रहन-सहन और हमारे विचार, सभी माडर्नाइज हो रहा है, ऐसे समय में यदि सड़कें माडर्नाइज न हों तो उन से न जनता का ही लाभ होगा और न राज्य का ही। लाभ के बजाय स्टेट का तो उन से नुक्सान होगा। पुरानी सड़कें जिनको वाटर बाउन्ड सड़कें कहते हैं और जो पत्थर की बनी होती हैं, आज आउट आफ डेट हो गयी हैं। ऐसी सड़कें न तो हमारे विचारों के माफिक हैं और न हमारे काम के लायक हैं। आज हम ६० और ७० मील की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। उनकी गर्द और धूल हमारे स्वास्थ्य को नुक्सान पहुंचाती है और इसके साथ ही वह इकनामिकल भी नहीं है। बहुत जल्द खराब हो जाती हैं। इसके अलावा जो आज डिजिल की गाड़ियां चल रही हैं उन में तीन-चार सौ मन का बोझ रहता है वे इन सड़कों को उधेड़ डालती हैं। तो इस लिये जरूरी है कि हम सड़कों को भी माडर्नाइज, कर दें। इस बजट में इस काम के लिये ३० लाख रुपये रखे गये हैं जिसमें १०८ मील सड़कें माडर्नाइज होंगी। मैं सदन की जानकारी के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि १९४६ में हमारे प्रदेश में करीब १८४७ मील सड़कें थीं, जो कि बेटेड सड़कें कहलाती थीं, लेकिन आज जिस समय १०८ मील सड़कें पूरी हो जायंगीं, उस वक्त पूरे प्रान्त में ५,४०० मील सड़कें माडर्नाइज हो जायंगी जिन पर तारकोल बिछ जायगा वह कारपेटेड रोड्स हो जायंगी।

मैंने सड़कों के बारे में दो एक बातें कहीं। अब मैं कुछ पुलों के बारे में कहना चाहता हूं? मैं समझता हूं कि हम सभी इस बात को अनुभव करते हैं कि पुलों की बहुत आवश्यकता है। खासतौर से उन जगहों में जो बरसात में दूसरी जगहों से कट जाती हैं। यानी बरसात के पानी के कारण वहां नहीं आ जा सकते हैं। बदकिस्मती से हमें ऐसे स्थान भी मिले जहां बरसात में लोगों के खाने का सामान नहीं रहा और क़हत पड़ गया। फिर भी हवाई जहाजों से अनाज वगैरह गिराया गया। मेरा मतलब है कि पुल बहुत ही जरूरी चीज है। मैंने स्वयं बरसात में एक क्षेत्र को देखा है और उस समय मैंने खासतौर से इस बात का विचार किया था कि law and order (ला ऐण्ड आर्डर) सुरक्षा का सवाल भी आ कर पड़ जाता है। दूसरे मौसमों में लोग बोट या पौन्टून ब्रिज से पहुंच सकते हैं अगर रायट हो जाय तो या आग लग जाय या कोई ऐसी बात हो जाय। लेकिन बरसात में हम लोग इधर पड़े हैं और उधर हमारी आंखों के सामने आग लग रही है या रायट हो रहा है, और हम बिना पुल के नहीं पहुंच सकते हैं। पता नहीं सन् ४६ से पहले क्यों नहीं पुलों की ओर खासतौर से ध्यान दिया गया। खैर, इस वक्त हमारा ध्यान इतनी दूर तक गया है कि हमारे पास साधन न होते हुये भी यह तय करना पड़ा कि हम पुल बनावेंगे और उस पर से

यात्री मोटरों से या बैलगाड़ी वगैरह से जावें वे कुछ कन्ट्रीब्यूट करें जिससे कुछ पुल की क़ीमत वसूल हो जावे। इससे जाहिर है कि जो कुछ भी हो, हम पुल जरूर बनाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में सन् १९४६ से ले कर आज तक करीब ४७ पुल बने हैं और पिछले २ वर्षों में करीब १९ पुल बनाये गये हैं जिनमें दो एक तो बड़े खास खास हैं। बेतवा का पुल है जो माननीय अध्यक्ष महोदय के जिले में है। माननीय अध्यक्ष वहां उस समय मौजूद थे। उसकी कितनी क़ीमत वहां है! केवल यही नहीं कि हमारे प्रदेश के और मध्य प्रदेश के लोग ही उस की क़ीमत अनुभव करें, वहां के रहने वाले भी उसे खासतौर से अनुभव करते हैं। बस्ती की बांसी तहसील में १४ लाख कुछ हजार रुपये की लागत का पुल बनाया गया। गढ़वाल में बद्रीनाथ रोड पर कीर्तिनगर का पुल बनाया गया जो मामूली नहीं है। यह पूरे सदन के लिये गौरव की बात है कि आज गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारे इंजीनियरों को और जगहों पर काम कराने के लिये चाहती है। आगरे में उटंगन का पुल बना जो प्रीस्ट्रेस्ड का पुल कहलाता है। इसमें बहुत रिस्क लिया गया था। हिन्दुस्तान के और दुनिया के और देशों के इंजीनियर्स ने आकर इसे देखा। करीब ३१ पुल इस विभाग ने हाथ में लिये हैं जो मैं समझता हूं कि करीब ३ करोड़ ९१ लाख रुपये की लागत के होंगे। बरेली-मथुरा रोड पर एक खास पुल है जो, आशा है, सन् ५९ के जून तक बन कर तैयार हो जायगा। पिछले दिनों हमारे नेता मुख्य मंत्री जी ने उसका शिल्यान्यास भी किया था यानी उसकी बुनियाद डाली थी। उस पुल की लागत करीब ६० लाख रुपया है। वह भी एक बहुत बड़ा पुल है। करीब १०० फुट गहरे कुओं पर पूरा पुल खड़ा किया जायगा। १४ दर हैं जिसमें से एक-एक की चौड़ाई १५० फीट है।

यह विभाग नेशनल हाईवे की सड़कों की देखभाल और निर्माण भी करता है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार पोषित करती है। क़रीब १५०० मील की ये सड़कें हैं और इसकी हालत अब सुधर रही है। मैं समझता हूं कि सन् ५९ तक सभी सड़कें पेन्टेड हो जावेंगी। जहां खास-खास रास्ते पड़ते हैं, जैसे लखनऊ से कानपुर है या लखनऊ से फैजाबाद है और और जगह हैं, वहां २२ फीट चौड़ी सड़क बनायी जा रही है। इन सड़कों पर भी पुलों की जरूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पर, दिल्ली से लखनऊ आने के लिये गढ़मुक्तेश्वर पर बड़ी दिक्क़त पड़ती थी और दिनों में तो हम फ़ेरी वगैरह से काम चला लेते थे लेकिन बरसात के दिनों में वहां कभी कभी ६, ६ घंटे और ८, ८ घंटे इन्तजार करना पड़ता था। केन्द्रीय सरकार ने उसकी इजाजत दे दी है और उसका काम भी शुरू हो गया है। उसके एप्रोचेज का काम १४ लाख रुपये का था जो हो गया है। ७५ लाख रुपये का उसका सुपरइस्ट्रक्चर का काम है जो अब शुरू होने जा रहा है। दो पुल इस नैशनल हाईवेज के ऊपर और हैं जिनकी केन्द्रीय सरकार ने पूरी स्वीकृति दे दी है और उनका काम शुरू होने जा रहा है। एक पुल तो सरजू का अयोध्या में है। वहां यात्रियों को जितनी तकलीफ होती होगी उनका दिल ही जानता होगा। वहां अब एक पुल १ करोड़ ८० लाख रुपये की लागत का बनने जा रहा है। ८० लाख रुपये उसकी ट्रेनिंग और एप्रोचेज के काम के लिये हैं। इसी तरह से राप्ती का पुल गोरख-पुर जिले में नेशनल हाई वे पर बनने जा रहा है। उसकी क़ीमत क़रीब ४० लाख रुपया होगी।

जहां तक भवनों की बात है, इस वर्ष में करीब ५ करोड़ ३ लाख २१ हजार रुपया रखा गया है और अभी तक इस विभाग के द्वारा अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण हुआ है। और दूसरे महकमों के भी भवन हैं, कुछ मेडिकल और हेल्थ विभाग के हैं, शिक्षा के हैं या जिसे भी जरूरत होती है वह अपने लिये भवन का निर्माण पी० डब्ल्यू० डी० से कराता है। इनमें सबसे बड़ा

[श्री गिरधारी लाल]

काम कानपुर के मेडिकल कालेज का है। यह काम अभी बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। वह इमारत ३ स्टोरी की है। उसके अलावा रीडर्स, प्रोफ़ेसर्स, लैक्चरर्स वगैरह के लिये करीब ४१ बंगले या मकान बनाये गये, १ होस्टल लड़कियों का और २ लड़कों के बनाये गये। साथ ही, क्लर्कों या दूसरे और निम्न कर्मचारियों के लिये, जैसे वार्ड ब्याय, टेक्नीशियन्स आदि होते हैं, उनके लिये क्वार्टर्स बनाये गये। जिला सहारनपुर में बलदेवदास बजौरिया नाम का अस्पताल है जो कि क़रीब २१ लाख की लागत से बनाया जा रहा है। लखनऊ में सेक्रेटरियेट के कर्मचारियों के लिये भी, मैं समझता हूं, महानगर में कुछ काम किया जा रहा है और इलाहाबाद में मोतीलाल मैमोरियल अस्पताल, आगरे में सरोजनी नाइडू मेडिकल कालेज के विस्तार का काम भी इस विभाग के जरिये से हो रहा है।

जैसा सदन के सदस्यों को मालूम है, हमारे प्रदेश में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। शायद ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे देश में कहीं नहीं है। यह रुद्रपुर में किछा के इलाके में होगी। करीब १ करोड़ २५ लाख रुपये की इसकी इमारत होगी जिसका डिजाईनिंग हो रहा है। केन्द्रीय सरकार इसे मंजूर करेगी और उसके बाद उसका काम चालू होगा।

इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, यानी स्लम्स की सफ़ाई, भी बहुत जरूरी है। आज हम उन बातों को सोच भी नहीं सकते हैं और हमें जल्द से जल्द अपने प्रदेश से मजदूरों को गन्दी जगहों को निकालना है। हमारे देश के रहनुमां पंडित जवाहर लाल नेहरू का जैसा खयाल है। हमारे सूबे की सरकार के और सूबे की चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि उसके लिये बहुत काफी काम किया जाय। अभी तक ९६७६ क्वार्टर्स बनाये गये हैं, अलहदा अलहदा इन्डस्ट्रियल सेंटर्स में ५७१४ क्वार्टर्स ऐसे हैं, जिनका काम हाथ में लिया गया है। इसके अलावा पांचवें चरण में १४०४ सिंगिल मेम्बर क्वार्टर्स बनाये जायेंगे तथा ६१२ डबल मेम्बर रूम्स वहां के वर्क्स के लिये बनाये जायेंगे।

मैं इस वक्त ज्यादा समय न ले कर केवल दो एक बातें और कहना चाहता हूं। फ्लड प्रोटेक्शन का काम भी बहुत जरूरी है। हमारे प्रान्त में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में कुछ वर्षों से काफी फ्लड्स आ रहे हैं और उनसे बहुत सा नुकसान हुआ है। बहुत से स्थानों पर यह अनुभव किया गया कि कहीं से पानी आ रहा है और बीच में सड़क आ गयी और पानी रुक गया। इसको दूर करने के लिये कहीं पर पानी की निकासी के लिये पुलिया बनायी गयीं, कहीं पर कम चौड़ी पुलियाओं को चौड़ा किया गया।

इसके अलावा बहुत से प्रोटेक्शन के काम भी किये गये। मिर्जापुर, बलिया, बद्रीनाथ आदि स्थानों पर गंगा दिन पर दिन सड़कों को काटती जा रही है। वहां पर प्रोटेक्शन के लिये घाटों का निर्माण किया गया। आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, बुलन्दशहर और बनारस में बांधों का काम खासतौर से बड़ी प्रगति से चल रहा है।

इसके अलावा इस विभाग द्वारा टेस्ट वर्क का काम भी कराया गया और उनके द्वारा २१ हजार व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया। अभी दो वर्ष हुए पश्चिम के जिले, जो फ्लड्स से बचे रहते थे, वहां भी बाढ़, और पानी से बहुत नुकसान हुआ है। इसलिये सरकार ने इस पर विचार किया कि इसका इलाज क्या हो सकता है और किस तरह से इन चीजों को काबू में लाया जा सकता है? इसके लिये जिस जिस विभाग को जिस जिस काम के करने की जरूरत थी, उन कामों को किया गया। बहुत से स्थानों पर नयी सड़कें बनायी गयीं, बहुत से स्थानों पर नये पुलों का निर्माण किया गया।

आजकल ट्रान्जीशन का पीरियड चल रहा है। आज एक-एक पैसे की बड़ी भारी जरूरत है। इस बात के लिय भी यह विभाग सदैव सजग और सतर्क रहा है कि किस प्रकार से एक एक पैसे का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सकता है और किस प्रकार से और कहां से पैसे को बचाया जा सकता है। इस प्रकार के इकानामिक मेजर्स में एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट

को एबालिश किया गया। इस प्रकार से १,८५ हजार रुपये की बचत की गयी। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग का कुछ रिजर्व फंड भी रहता है, उसको ५ प्रतिशत कम किया गया। इसी प्रकार कांटिंजेंसी में ५ प्रतिशत से ३ प्रतिशत और अब २ प्रतिशत कर दिया गया है।

मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य इस बात को भलीभांति समझ गये होंगे कि यह विभाग किस गति के साथ काम करता चला जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए, जितने भी अनुदान मैंने रखे हैं, उन सबको माननीय सदस्य अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्माण मंत्री ने सदन के सम्मुख अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५० के लिये ५,७०,९८,३०० रुपया, अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५० के लिये १३,०४,६०० रुपया, अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५० के लिये ७६,९१,६०० रुपया, और अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१ के अन्तर्गत ८,४३,६५,२०० रुपया की जो मांग प्रस्तुत की है, मैं उन सब मांगों में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने विभाग की चर्चा करते समय पुलों की चर्चा में काफी समय व्यतीत किया और अपने विभाग की तारीफों का पुल बांध दिया। मैं समझता हूं कि माननीय निर्माण मंत्री ने अपने विभाग द्वारा बनाये जाने वाले पुलों की जितनी तारीफ की है, वास्तव में जनता के लिये उतने पुलों का निर्माण नहीं किया गया है। पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में जहां निर्माण मंत्री महोदय ने चित्र का एक पहलू प्रस्तुत किया है, मैं उसके दूसरे पहलू को प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आगरा जिले से आ रहा हूं। आगरा वह जिला है जहां मुगलकालीन युग में निर्माण कार्य बहुत उच्च कोटि पर हुआ था और जहां आज भी भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग उस निर्माण कला के दर्शन के लिये आते हैं और उन महान् कारीगरों की निर्माण कला को देख कर नतमस्तक हो जाते हैं। भारत सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपये बाहर के लोगों को भारतीय कारीगरों की मुगलकालीन निर्माण कला दिखलाने के लिये बर्बाद करती है। जिस मुगलकालीन निर्माण कला को देखने के लिये इतने लोग आते हैं और फतेहपुर सीकरी का विशाल बांध, जो तेरहमोरी बांध के नाम से प्रसिद्ध है, क्या निर्माण मंत्री जी को यह मालूम है कि ४०० वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वह कितनी अच्छी हालत में है? श्रीमन्, आपका विभाग जो कि भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है और जहां एक, तीन के बजाय एक-बारह के हिसाब से सीमेंट मिलाया जाता है, क्या वह कहीं उसके चौथाई वर्ष तक भी कायम रह सकता है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि वे अपने को मुगल बादशाह बनाने के लिये आपसे प्रार्थना करें और फिर बेगम मुमताज महल की जरूरत पड़े।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, चूंकि उन्होंने अपने विभाग की तारीफ का पुल बांधा इसलिये मैंने उस कड़ी को जोड़ने का प्रयत्न किया था। श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि उटंगनपुल, जो रेलवे का पुराना पुल था और जिससे कुछ विशेष ढंग से बनाने में सरकार ने काफी रुपया खर्च किया, उसको देखने के लिये भारत के बड़े बड़े इंजीनियर आये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

में उनसे कहता हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, जौनपुर के अकबरी पुल को ही देख लीजिये जो आज भी ४०० वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी किस मजबूती के साथ गोमती पर खड़ा हुआ है । श्रीमन्, आगरे में यमुना पर पुल बना है, एक नया पुल और एक पुराना पुल बना है और आगरे में तीसरे पुल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें ७० लाख रुपया खर्च हो रहा है । निर्माण के नाम पर और विकास के नाम पर जो आज अरबों रुपया व्यय हो रहा है प्रतिवर्ष उसके विषय में जनता में आम चर्चा है कि उस का दुरुपयोग हमारे द्वारा हो रहा है और वास्तव में यह निर्माण कार्य जनता के लाभ के नहीं होते । उदाहरण के लिये मैं बताऊंगा कि आगरा जिले में कुल मिलाकर २८० मील कच्ची और पक्की सड़कें हैं, अगर उन सब सड़कों को १२ फुट चौड़ाई को लेकर कोलतार से बनाया जाय तो इन २८० मील सड़कों के द्वारा हम वहां के गांव गांव में पहुंच सकते हैं । तो उनके बनाने में २५ हजार रुपया प्रतिमील के हिसाब से ७० लाख रुपया व्यय होगा, लेकिन हमारे निर्माण मंत्री जी को सड़कों की क्या जरूरत ? वह तो वहां पर २ पुलों के होते हुये भी एक और तीसरा पुल निर्माण करने जा रहे हैं और उस पर ७० लाख रुपया खर्च होगा । सोचने की बात यह है कि यह समस्त जिले की सड़कों का निर्माण अधिक उपयोगी होगा, आम जनता के लिये या यह जमुना के पुल का निर्माण ? इस दृष्टि से हमें देखना चाहिये । आम जनता को तो सड़कों की अधिक आवश्यकता है, जिन बैलों का सहारा लेकर, बल्कि कागज के बैलों का सहारा लेकर हम दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच गये हैं उन बैलों के लिये इन सड़कों पर कितने गड्ढे हैं ? सिर्फ इन बैलों को आप एलेक्शन में ही याद न कीजिये उन्हें सुविधा देने का भी प्रयत्न कीजिये ।

सड़कों के बारे में बताया गया कि हमारे सूबे में कुल १२,१८५ मील सड़कें हैं । इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता क्योंकि यह तो लम्बाई चौड़ाई के आंकड़े हैं, शायद नई पुरानी सड़कें मिलाकर यह फिगर हो, लेकिन यदि हम इतिहास के कुछ पन्नों को उलटें और शेरशाह सूरी के शासन को याद करें तो उसने केवल ५ साल का शासन किया और उस ने अपने उस ५ साल में ही कलकत्ते से पेशावर तक १,८०० मील लम्बी ग्रान्ट ट्रंक रोड का निर्माण किया । उस ने युद्धरत होते हुये भी अपने इस ५ वर्ष के अल्पकाल में इतनी बड़ी सड़क का निर्माण उस युग में कराया था लेकिन मंत्री जी ने १२,१८५ मील पर ही सदन को आश्वासन दिलाया है । पता नहीं उन को कितनी पंच वर्षीय योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी । कठिनाई तो यह है कि आजकल तो माननीय मंत्री जी का और इंजीनियर्स का ध्यान अपने अमर स्मारकों की तरफ अधिक जाता है ताकि यह हमेशा के लिये बने रहें । जिस तरह से कि आजतक शाहजहां और मुमताज महल की याद की जाती है, उसी तरह से आप भी चाहते हैं कि आप की अवधि समाप्त होने के बाद भी शाहजहां की तरह आप को जनता याद करती रहे इसलिये आप बड़े बड़े पुलों, भवनों और अट्टालिकाओं को ही स्मारक का रूप देना चाहते हैं । वह रूप सड़कें तो नहीं ले सकतीं क्योंकि सड़कों पर मेमोरियल के पत्थर नहीं लगाये जा सकते, वह तो मीलों दूर तक चली जाती हैं, उन को कोई नहीं पूछेगा कि किस इंजीनियर ने निर्माण कराई थी जबकि पुलों पर और भवनों पर लिखा रहेगा कि फलां मंत्री महोदय के काल में फला इंजीनियर्स ने यह पुल बनवाये थे । इस तरह से आप तो अमर स्मारकों के बनाने में लगे हैं और इस नीति को मानते हुये आप कभी भी सड़कों की ओर ध्यान नहीं देंगे । मैं माननीय मंत्री जी से और निर्माण विभाग के इंजीनियर्स से निवेदन करूंगा कि वह जनता की ओर ध्यान दें जो उन से आकांक्षा रखती है और चाहती है कि यद्यपि आप को आज हवाई जहाज की सुविधा है लेकिन आम जनता हवाई जहाज में तो नहीं चल सकती । आम जनता को अपनी बैलगाड़ियों के लिये, अपने इक्के तांगे के लिये और यदि उसको किसी तरह से मोटर भी नसीब हो गई है तो उसके लिये, इन भवनों और पुलों से ज्यादा सड़कों की आवश्यकता है । आप पुलों का निर्माण छोड़कर, अमर स्मारक के लिये ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को छोड़कर, अगर इस प्रदेश में सड़कों के बनाने पर ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा हो । मुझे यह बात इसलिये कहनी पड़ी, श्रीमन्, कि

१५ करोड़ के बजट में १ करोड़ ७ लाख रुपया सड़कों के लिये आपने रखा है। बाकी सारा रुपया पुलों और भवनों के निर्माण में ही व्यय करने जा रहे हैं। श्रीमन्, एक निवेदन और भी करना चाहता हूं। पी० डब्लू० डी० विभाग को आम तौर पर लोग कहते हैं कि यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट है। लेकिन मैं उसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी राय में तो यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम लोग दारुलशफा में रहते थे, हम लोगों की आंख के सामने एक भवन खोद कर फेंक दिया गया है। आप कहते हैं कि उप मंत्रियों के लिये चार बंगलों की आवश्यकता है। एम० एल०एज० के रहने के लिये आपने बर्लिंगटन होटल को साढ़े अट्ठाइस सौ रुपये माहवार किराये पर ले रखा है और सेंट्रल होटल को ६८० रुपये माहवार किराये पर ले रखा है। एक वर्ष में हमारी सरकार ४२,३६० रुपया सिर्फ २० एम०एल०एज० के रहने के ऊपर बर्लिंग्टन होटल और सेंट्रल होटल को किराये के रूप में अदा कर चुकी है। तो जहां आप एम०एल०एज० के रहने के लिये इतना रुपया खर्च करते हों, वहां उन्हीं एम०एल०एज० की नाक के सामने इतनी मजबूत इमारत खोद खोद कर फेंक दी जाय, यह पब्लिक वेस्ट नहीं तो और क्या है? एक फर्लांग की सड़क को सीधी करने के लिये इतनी मजबूत इमारत को आप खोदकर फेंक सकते हैं जिसमें आपको ६ वर्ष लगे, यह पब्लिक वेस्ट के अलावा और क्या हो सकता है? और सुनिये, आप कारों में तो सफर करते हैं। जरा सड़कों के किनारों पर देखें। मील और फर्लांग के पत्थर लगे हुये थे। न मालूम किस इंजीनियर के दिमाग में आया, मील पर तो मील लिखा हुआ था कि लखनऊ से कानपुर कितने मील है, लेकिन फर्लांग पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ लिखे होते थे, पता नहीं किस इंजीनियर के दिमाग में आया कि शायद इससे लोगों को कुछ शंका हो, अब उस पर हो गया २६/७, २८/७, इस प्रकार अब उस पर लिख दिया गया है। करोड़ों रुपया आपने जनता का, बर्बाद कर दिया सिर्फ इस काम के लिये। वह जो पत्थर सड़कों के किनारे पर लगे हुये थे वह फेंकवा दिये गये और अब दूसरे फर्लांग के पत्थर लगाये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर छठवें और सातवें फर्लांग के पत्थर लगे हुये थे और सदियों से काम दे रहे रहे थे, उनसे कौन सी दुर्घटना हो गई, कौन सा ऐक्सीडेंट हो गया, या किसके दिमाग में उससे गलतफहमी पैदा हो गई जो यह पत्थर उखड़वाकर उनकी जगह दूसरे पत्थर लगवाये गये जिन पर २६/७, २८/७ इस प्रकार लिखा हुआ है। इस तरह से आपने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। इसे पब्लिक वेस्ट न कहा जायगा तो और क्या कहा जायगा? यह दो छोटे से उदाहरण मैंने आपके सामने रखे।

श्रीमन्, आज आपका विभाग बहुत सुन्दर काम कर रहा है, आपके आदमी दिन रात इस निर्माण कार्य में लगे हुये हैं, जिन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। गत वर्ष के बजट में २ करोड़ १० लाख रुपया इस बात के लिये रखा गया था कि अल्प वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी और लोकल बाडीज के कर्मचारी जिनको ९५ रुपया वेतन मिलता है उनमें से प्रत्येक को पांच रुपया मासिक अतिरिक्त मंहगाई का भत्ता दिया जायगा। यह मंहगाई और भत्ता लेखपालों, अध्यापकों, मेहतरों और भिश्तियों को, सभी को दिया गया लेकिन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय ने यह कृपा नहीं की कि उनके विभाग में काम करने वाले एक नहीं वह हजारों कर्मचारी हैं जो वर्क्स चार्ज और मस्टर रोल में रहते हैं। उनको भी जिन्हें आप सरकारी कर्मचारी कहते हैं। यह मंहगाई और भत्ता

[श्री जगन्नाथ लहरी]

दिलवा देते। वह इससे महरूम रह गये। यही नहीं, हम ऐक्ट बनाते हैं, छोटी छोटी दूकानों पर शाप्स ऐंड कर्मीशयल ऐस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट लागू है, उन पर काम करने वाले कर्मचारी ८ घंटा काम करेंगे, मासिक छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी, बीमारी की छुट्टी दी जायगी। फैक्टरी ऐक्ट भी लागू है। तो क्या कभी निर्माण मंत्री ने सोचा है कि उनके विभाग में इन सड़कों के निर्माण करने में जो ३०, ३० साल से लोग लगे हैं आज तक उन बेचारों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उनके लिये टाइम का कोई लिहाज नहीं, ओवरटाइम का कोई लिहाज नहीं, न छुट्टी का लिहाज, भले ही वह आपके निर्माण कार्य में लगा हो। लेकिन आपके यहां एक साधारण मजदूर से अधिक उनकी वकअत नहीं और यहां तक कि घायल हो जाने के बाद फर्स्ट एड तक का भी इंतजाम नहीं। विश्वकर्मा आप अपने लिये है, आलीशान कोठियां तो बनवा रहे हैं, आप जरा सा सड़कों का निरीक्षण करने जाते हैं, जो इंजीनियर हिन्दी शब्द कोष से ढूंढकर विश्वकर्मा का नाम लाया है वह चाहता है कि उसे विश्वकर्मा कहा जाय। लेकिन वह विश्वकर्मा हवाई जहाज में उड़ते हुये यह भूल गया जिन व्यक्तियों के द्वारा उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी जा रही है वे निरीह मजदूर आज ठुकराये जा रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं। मैं स्वयं एक डेपुटेशन लेकर इस सम्बन्ध में उप-मंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महावीर प्रसाद जी से मिला, निर्माण मंत्री जी के यहां पहुंचा लेकिन वह बाहर गये हुये थे, चीफ इंजीनियर से मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ रिप्रेजेन्टेशन पर रिप्रेजेन्टेशन चल रहा है लेकिन क्या कभी निर्माण मंत्री जी ने आज तक यह सोचा है कि हम इन सरकारी कर्मचारियों को भी कोई सुविधा दिलाने की कृपा करें? मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं यदि आप वास्तविक तौर पर इस देश का निर्माण करना चाहते हैं, समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो जब किसानों और मजदूरों की इस तरह से अवहेलना हो उस सरकार को कभी भी समाजवादी सरकार नहीं कहा जा सकता। यदि वास्तव में आप समाजवादी सरकार कहलाने के पात्र होना चाहते हैं तो आइये इन विश्वकर्माओं को छोड़ कर मजदूरों की तरफ ध्यान दीजिये।

अब मैं समय की कमी के कारण एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज जनता को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट से अनेक आशायें हैं। यह विभाग ही जनता को प्रत्यक्ष रूप से कुछ सुविधायें प्रदान करता है। लेकिन इस विभाग में आज हर व्यक्ति लखपती होने के स्वप्न देखता है। ठेकेदार और इंजीनियर यह कहते हैं कि युद्धकाल के बाद में यह सुनहरा मौका मिला है। सरकार की पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं यदि इनमें लोग लखपती नहीं हो सके तो उनसे ज्यादा फूटे भाग्य वाला कोई नहीं है। फिरोजाबाद में अस्पताल का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ और सीमेंट बाजार में बिकता रहा ब्लैक से। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने फिरोजाबाद तहसील में दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ किया? जब से कांग्रेसी शासन कायम हुआ आपने एक इंच भी सड़क बनवाई? वहां नेशनल हाई वे है, युद्ध काल में फिरोजाबाद में एक बाई पास बना। उसके अतिरिक्त आपने कौन सी सड़क बनाई? दो सड़कें फिरोजाबाद-कोटला रोड और फिरोजाबाद-चन्दवा रोड जो पहले की बनी हुई है जर्जर हो गयी हैं। वहां अगर स्त्रियां चलती हैं तो गर्भपात हो जाते हैं, इक्के तांगे टूट जाते हैं, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सैकड़ों बार प्रार्थना की गयी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रान्त में फिरोजाबाद-कोटला रोड की ही ऐसी हालत नहीं है, बल्कि प्रान्त के हर हिस्से में ऐसी सड़कें मिल जायंगी। मैं पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्मारकों को बनवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसान और मजदूर को लाभ पहुंचाने के लिये जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्न उत्पादन को प्राथमिकता दी गयी थी उसी तरह आज मैं निवेदन करूंगा कि इन अट्टालिकाओं और भवन निर्माण को प्राथमिकता न देकर जनता और जन जीवन को लाभ पहुंचाने के लिये सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाय तभी इस देश की जनता को लाभ पहुंच सकता है और जनता यह समझ सकती है कि यहां सरकार ने उसके लिये कुछ काम किया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने यातायात के साधनों पर जो बल दिया है और जो उन्होंने जिक्र किया कि ५ जनवरी, १९५८ को राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने भी अखिल भारतीय रोड कांग्रेस के २२ वें अधिवेशन में यातायात की समुचित उन्नति पर बल दिया, उस सम्बन्ध में मेरा भी यही निवेदन है कि इस में दो रायें नहीं हो सकतीं कि किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक व शैक्षिक उन्नति के लिये यातायात का समुचित प्रबंध नितांत आवश्यक है, इसको सब मानते हैं। लेकिन मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में सड़कों का निर्माण-कार्य जिस गतिविधि से चल रहा है वह उतना संतोषजनक नहीं है या वह हमारे उस टार्गेट को पूरा करने में बहुत हद तक हमारा साथ नहीं दे सका है जिस टार्गेट को हमने अपने दिमाग में रखा है और जो चतुर्मुख उन्नति प्रदेश की करने का इरादा है वह भी उससे हल नहीं हो सकेगा। जिस टार्गेट को लेकर हम चले हैं स्टार एंड ग्रिड फार्मूले के अनुसार ४० हजार मील सड़कें हमारे प्रदेश में होनी चाहिये, उसको पूरा करने में ४० साल आगे और लगेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के बाद आठ पंचसाला योजनायें और लगेंगी तब जा कर हम अपने प्रदेश के यातायात की समस्या को हल कर सकेंगे।

स्टार एंड ग्रिड फार्मूले का जिक्र बहुत कुछ आता है। नागपुर में उसको एडाप्ट किया गया था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्टार एंड ग्रिड फार्मूला सामने होते हुये भी प्रदेश में यातायात की उन्नति का जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें फार्मूले को फालो नहीं किया जाता है। क्या कठिनाई होती है उसे फालो करने में, यह मैं समझने में असमर्थ हूं। प्रदेश में बहुत से जिलों में, जहां स्टार एंड ग्रिड फार्मूले से भी ज्यादा सड़कें हैं वहां और ज्यादा सड़कें बनाई जा रही हैं और जहां फार्मूले के अनुसार बहुत कम सड़कें बैठती हैं उनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि दिया जाना चाहिये था। मिसाल है कि Richer is getting richer and the poorer is getting poorer हमारा देश देहातों में बसा है और जब तक देहातों का विकास नहीं होता देश का विकास भी असम्भव है। देहातों का विकास बिना सड़कों के नहीं हो सकता और जब तक कंट्रीसाइड में सड़कों का निर्माण नहीं किया जायगा, तब तक न तो हमारे देहात उन्नति कर सकेंगे और न उस समय तक हमारा देश ही प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकेगा।

अभी पिछली दफा ढाई करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से सड़कों के लिये प्राप्त हुआ। दुर्भाग्यवश मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में भी पिछले दो तीन सालों से फ्लड्स आये। वहां के खादर एरिया में अनाज का पहुंचाना भी दूभर था। कितने ही गांव दरिया में पहुंच गये और हवाई जहाज से अनाज वहां पहुंचाना पड़ा। कपड़ा पहुंचाने की व्यवस्था भी बहुत कठिनाई के साथ करनी पड़ी। सर्वसम्मति से हमने प्रार्थना की कि उस ढाई करोड़ रुपये में से पश्चिमी क्षेत्र के जिलों पर भी कुछ खर्च कर दिया जाय, विशेषकर हमने मुजफ्फरनगर जिले के लिये प्रार्थना की। वहां पर एक तरफ जमुना जी हैं और एक तरफ गंगाजी। एक साल जमुना जी में बाढ़ आती है तो दूसरी साल गंगा जी में, और हर साल बहुत से गांव दरिया में पहुंच जाते हैं। जमुना जी पर पहुंचने के लिये एक भी सड़क न प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपके द्वारा रखी गयी और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादर को फीड करने के लिये रखी गयी और न उस ढाई करोड़ रुपये में से एक पाई या एक नया पैसा भी खर्च करने की आपने कोई व्यवस्था की। इसलिये मुझे आप से निवेदन करना है कि मुजफ्फरनगर जिले में जहां फ्लड्स आते हैं

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और ला एंड आर्डर सिचुएशन इतनी खराब है उसके इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, मुजफ्फरनगर पंजाब से मिला हुआ है, ला एंड आर्डर की दृष्टि से देखा जाय तो सन् १९५५ में जब कि ७ डकैतियां हुई थीं तो सन् १९५६ में २७ हुईं और सन् १९५७ में भी इतनी ही डकैतियां हुईं। ला एंड आर्डर सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिये और दोनों ओर गंगा जमुना होने के कारण जो खादर में फ्लड्स आते हैं उनको ध्यान में रख कर यह अत्यन्त आवश्यक है कि आपका समुचित ध्यान उधर जाय। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस फार्मूले के अनुसार मुजफ्फरनगर जिला नीचे से तीसरे नम्बर पर आता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि इस ओर आप ध्यान देंगे और प्रदेश के विकास और चहुमुखी उन्नति को मद्देनजर रखते हुये-- जैसा कि आपका ध्यान है, मुजफ्फरनगर का भी ध्यान रखने की कृपा करेंगे।

मैं यह भी सुझाव देना मुनासिब समझता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल के पास हो जाने के बाद बहुत दिनों तक जिलों में उसकी सैंक्शन नहीं पहुंचती है। उसका नतीजा यह होता है कि ३१ मार्च की तारीख जिस समय पहुंचती है तो उस समय होड़ लगती है रुपये को जल्दी से जल्दी खर्च करने की-- चाहे आपका मुहकमा हो या दूसरे का। मैं आशा करता हूं कि ३१ मार्च की तारीख का लक्ष्य न रखा जाय, बल्कि लक्ष्य रखा जाय कि जल्दी से जल्दी जिलों में अप्रैल या उस से अगले महीने में ही आपकी सूचना पहुंच जाय ताकि उसके प्रयोग की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो सके।

साथ ही यह भी निवेदन करना है कि नेशनल हाई वे ऐक्ट की बाबत न जाने कितने दिनों से सुन रहे थे कि उसका निर्माण हो रहा है। नामालूम वह कौन सी अड़चनें हैं कि अभी तक उसे बिल के रूप में इस हाउस में लाने में आप असमर्थ हैं। जब तक यहां आपका वह ऐक्ट नहीं आता उस समय तक आपकी सड़कों पर एनक्रोचमेंट, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसे आप रोकने या दूर करने में असमर्थ रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि नेशनल हाई वे ऐक्ट यहां पर आप स्वयं या केन्द्रीय सरकार द्वारा लाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे।

तीसरी बात यह है कि जो आपके सी० सी० ट्रैक्स शुगर मिलों के चारों तरफ बनने जा रहे हैं उनकी चौड़ाई पहिले ४० फिट रखी जाती थी। आज न जाने किस लक्ष्य को सामने रखते हुये आप उसकी चौड़ाई सौ फिट रखना चाहते हैं। वह विलेज रोड्स हैं। जूलाजिकल गार्डन में जो आपकी प्रदर्शनी हुई थी उसमें आपने दिखाया था नेशनल हाई वे की चौड़ाई १२० फिट, प्रांविशियल हाई वे की सौ फिट के करीब है और ओ० डी० आर्स की ६६ फिट। विलेज रोड्स के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस जमाने में जब कि प्रदेश और देश में अन्न की कमी है, उत्पादन को बढ़ाने के नुक्ते नजर से भी हमें अपनी इन सड़कों की चौड़ाई किसी भी हालत में ६० फ़ीट से ज्यादा नहीं रखनी चाहिये।

एक सुझाव में और, जो करप्शन की बात कही जाती है, उस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। निर्माण के सिलसिले में इर्रीगेशन विभाग जो निर्माण करता है उसके मुकाबले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया हुआ निर्माण कार्य ज्यादा पायेदार है। जहां तक करप्शन का सम्बन्ध है, मैं यह कहे बगैर नहीं रुक सकता कि इसका जो लोअर स्ट्राटा है उसमें अभी तक काफी करप्शन है। ऊपर से काफी कोशिश भी की जाती है लेकिन नीचे का जो ५ फीसदी ओवरसीयर साहबान आदि का बंधा है उसका शायद मंत्री महोदय को भी ज्ञान होगा। चीफ़ इंजीनियर को भी ज्ञान होगा और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी उसका ज्ञान है। तो उस ओर आप ध्यान दें और इस करप्शन को खत्म करें। यह महकमा जितनी उन्नति के पथ पर इस प्रदेश को ले जाना चाहता है--मैं एक मिनट और चाहूंगा श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---वहां मेरा निवेदन आप से यह है कि आप कोशिश करें कि नीचे से भ्रष्टाचार निकल जाय ताकि जितना धन आपके विभाग को मिले उसका सदुपयोग हो सके और हमारा प्रदेश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके।

इसी सम्बन्ध में मैं एक और सुझाव करप्शन को दूर करने के लिये देना चाहता हूं। जिस समय चीफ़ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जिलो में पहुंचें तो जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य हो रहा हो वहां के सोशल वर्कर्स को बुला कर पूछें कि उनका कार्य संतोषपूर्ण हो रहा है और जिस समय मंत्री महोदय जिलों में पहुंचें तो वहां के एम० एल० एज़, एम० पीज़० और दूसरे वर्कर्स से भी पूछें कि कार्य ठीक हो रहा है या नहीं। ऐसा करने से करप्शन को बहुत हद तक रोका जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय जगन्नाथ लहरी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, किसी प्रदेश को उन्नतिशील बनाने के लिये और उसके औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि यातायात और आवागमन के साधन अच्छे उपलब्ध किये जांय, किन्तु मुझे दुख है कि गत वर्षों से सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो नीति रही है उस से हम सब लोगों को निराशा हुई और इसीलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो अनुदान उपस्थित किया गया है उसमें ८१ लाख ३५ हजार रुपया स्थानीय निकायों को सुधार निर्माण कार्य के लिये रखा गया है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में १२ हजार मील लम्बी पक्की सड़कें और २४ हजार मील कच्ची सड़कें हैं। पक्की सड़कों में लगभग ५० प्रतिशत् सड़कें और कच्ची सड़कें प्रायः सभी स्थानीय निकायों के हाथ में हैं। ऐसी स्थिति में केवल ८१ लाख ३५ हजार रुपये उनको देना बहुत कम प्रतीत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाय क्योंकि मेन्टीनेंस एक्सपेंडिचर में उनको बहुत ज्यादा व्यय करना पड़ता है। इसलिये आवश्यकता है कि इसके अन्तर्गत जो भी मेंटीनेंस एक्सपेंडिचर हैं उनका ५० प्रतिशत स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिये।

इस विभाग की ओर से जहां भी पुल बनाये जाते हैं तो एक नयी प्रथा चल पड़ी है टोल टैक्स लगाने की। इसको लगाने से जनता को कोई लाभ नहीं होता है बल्कि जो उसकी आशायें होती हैं वह निराशा में परिणित हो जाती हैं। इसलिये आवश्यकता है कि जो पुल बनाये जांय उनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स न लगाया जाय क्योंकि आमतौर पर साधारण जनता को ही इस टैक्स का बोझ उठाना पड़ता है।

मान्यवर, इसी अनुदान में पुलिस के रहने के लिये इमारतों के लिये ३५ लाख रुपये का एस्टीमेट रखा गया है। अगर इसी मद को आगे देखा जाय तो शिक्षा की इमारतों के लिये २३ लाख रुपया व्यय करने के लिये रखा गया है। यह अनुचित प्रतीत होता है। जब नई जेनरेशन बनायी जा रही है तो आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के ऊपर ज्यादा खर्चा न करके शिक्षा के लिये अधिक से अधिक व्यय करें और सरकारी स्कूलों में व्यय करने के लिये अगर गुंजायश न हो तो एडेड स्कूलों को सहायता प्रदान करें और २३ लाख रुपये का जो अनुदान स्कूल बिल्डिंग्स के लिये रखा गया है, उसको और बढ़ाया जाय।

मान्यवर, कलक्टरों के बंगलों के लिये सहारनपुर और गोरखपुर में पचास-पचास हजार रुपया रखा गया है। इन बंगलों के बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि कलक्टरों को किराये के बंगलों में रहने क लिये कहा जाय . . . . .

श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—प्वांइट आफ़ आर्डर, सर। बंगलों के बनाने का ताल्लुक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से है। यह महकमा तो सिर्फ बनाने वाला है। इसलिये इस चीज को उस मौके पर कहा जाय तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष—जहां तक आप कह रहे हैं वह सही है। लेकिन इस अनुदान में भी उनके खर्च का जिक्र है इसलिये माननीय सदस्य उनके बारे में कह सकते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, रुपये की मंजूरी इसी ग्रांट में दी जा रही है इसलिये मैं आज इस बहस को ले रहा हूं। यह जो बंगले बनवाये जा रहे हैं मेरा विचार है कि यह इन्वेस्टमेंट एक डेड कैपिटल एक्सपेंडीचर है। इस से कुछ नफा नहीं होगा। आज हमें विकास करने की जरूरत है, बंगलों की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रतिकूल आवश्यकता इस बात की है कि जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं मसलन इसी सेक्रेटेरियेट में करीब ६५३ ऐसे चपरासी हैं जिनको रहने के लिये मकान नहीं हैं और न उनको हाउस एलाउन्स ही मिलता है। ऐसे निम्न-श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो कलेक्टरों के बंगलों को बनवाने से रोकें और छोटे कर्मचारियों के रहने के लिये कोई व्यवस्था करें।

इसी प्रकार पी० ए० सी० और यू० पी० पुलिस के रेडियो स्टेशन के लिये पांच-पांच लाख रुपया व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। आज अंग्रेजी फौजें यहां से चली गयी हैं जिससे कैन्टोन्मेंट्स में तमाम बैरकें खाली पड़ी हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम अलग से पी० ए० सी० के लिये क्वार्टर बनवाकर खर्चा करें बल्कि जो पुरानी बैरकें हैं उनका सही उपयोग किया जाय। हम अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं इसलिये हमें खर्चे में कमी करनी चाहिये। इसलिये आवश्यकता है कि हम इस तरह से खर्चे को रोकें और पी० ए० सी० बटेलियन और पुलिस के रेडियो स्टेशन के लिये इन्हीं बैरकों का इस्तेमाल किया जाय।

मान्यवर, इसी प्रकार से छठी बटेलियन के लिये मेरठ में तीन लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। वहां पर भी इसी तरह से काम चलाया जा सकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि नैनीताल में हमारी प्रदेशीय सरकार की काफी इमारतें हैं। यह इसलिये ली गई थीं और इसीलिये अबतक कब्जे में हैं कि ग्रीष्मकाल में मंत्रीगण और सरकारी उच्च-कर्मचारी वहां जाया करें। लेकिन अब मैं समझता हूं और जनता की भी यही राय है कि हिल स्टेशन आने-जाने की अब आवश्यकता नहीं रह गयी है और यहीं रहकर हम लोगों को काम करना चाहिये। इसलिये जितनी इस तरह की इमारतें हैं उनको सरकार को बेच देना चाहिये और अगर सरकार यह समझती है कि इस प्रकार की इमारत नहीं बेचनी चाहिये तो फिर इनको सार्वजनिक कार्य के लिये उपयोग में लाना चाहिये। यह इमारतें वहां पर साल भर बन्द रहती हैं। महीने भर के लिये जब मंत्रीगण या दूसरे लोग वहां पर जाते हैं तो उनका उपयोग होता है। ११ महीने वह बन्द रहती है। तो मैं यह समझता हूं कि यह अच्छा है कि ११ महीने बन्द रहने की बजाय हम अपने प्रदेश की उन्नति के लिये इन इमारतों को दूसरे सार्वजनिक कार्यों में इस्तेमाल करना प्रारम्भ कर दें तभी हमारे देश तथा प्रदेश का कल्याण हो सकता है।

मान्यवर, इस प्रदेश में ५०० बेसिक स्कूलों के लिये १२ लाख ७० हजार रुपया गतवर्ष मन्जूर किया गया उसमें से केवल २ लाख रुपया खर्च किया गया है। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि बेसिक स्कूलों के बच्चों को बैठने के लिये इमारत बनाने के वास्ते १२ लाख ७० हजार रुपया मन्जूर करें और उसमें से केवल २ लाख रुपया व्यय करें। यह बच्चों के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ इस विभाग की और माननीय मंत्री जी की बड़ी जबरदस्त ज्यादती है। चाहिये तो यह था कि जो १२ लाख रुपया इस सदन ने मंजूर किया उसका पूरा उपयोग होता। जहां पर आज स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिये जगह नहीं है, वह आसमान की छाया या वृक्ष की छाया में बैठते हैं, वहां जरूरत इस बात की थी कि जितना रुपया बेसिक स्कूलों के लिये मंजूर हुआ है उस

तमाम रुपये को व्यय करते लेकिन उस रुपये में से केवल दो लाख रुपया व्यय किया गया है। मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष के लिये ३ लाख रुपये का एस्टीमेट रखा गया है। वह पूरी योजना २१ लाख की है। तो इस बात की आवश्यकता है कि बेसिक स्कूलों के निर्माण के लिये, प्रगति के लिये आगे बढ़ें और बेसिक स्कूलों का निर्माण करें।

मान्यवर, इसी प्रकार से बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० की बड़ी जिम्मेदारी बाढ़ के विषय में है। पानी तो कहीं पर बरसता है और बाढ़ दूसरे स्थान पर आती है। अभी सभी ने देखा कि बुलन्दशहर में पानी बरसा और उसकी बाढ़ अलीगढ़ में आयी। इसका कारण यह था कि वहां पर ड्रेनेज का प्रबन्ध ठीक नहीं था। इस सम्बन्ध में पी० डब्लू० डी० को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये।

मैं एक बात अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि बीघापुर नकिया स्टेशनों से १० मील तक गंगा की ओर जाने को कोई सड़क नहीं है। जो वहां पर सड़कें हैं वह कच्ची हैं। वहां पर आने जाने के लिये बड़ा कष्ट होता है। लखनऊ से दिल्ली जाने के लिये जितना समय और पैसा लगता है उस से ज्यादा वक्त और ज्यादा पैसा उस स्टेशन से वहां उन गांवों तक जाने में लगता है। मान्यवर, वे सड़कें पी० डब्लू० डी० के हाथ में थीं लेकिन उसने उनको वापस कर दिया है। मेरा निवेदन है कि इस पंचवर्षीय योजना में बिहार से बक्सर को जाने वाली और बीधापुर रुझई बक्सर वाली सड़कों को सरकार शामिल करे और इस प्रकार इसी पंचवर्षीय योजना में इन सड़कों को सरकार पक्की करावे। जो काम एक बार स्वीकार किया जाता है उसकी पूर्ति नहीं की जाती इस से जनता को कोई लाभ नहीं होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार से कार्यवाही को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ायें।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो अनुदान पेश किया गया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही मैं उन अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने देखा कि इस विभाग ने प्रान्त में काफी प्रगति की है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कई सौ मील सड़कें और काफी पुल बनाये गये और यातायात की सुविधा के लिये इस प्रान्त में तरक्की के लिये एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिये काफी सड़कें बनाई गईं। इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ यहां पर यह भी कहा गया कि टोल-टैक्स पुलों पर न लिया जाय, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं और छोटी-मोटी नदियों के कारण जो क्षेत्र बरसात के दिनों में हेड क्वार्टर्स से अलग हो जाते हैं वहां पर जनता यह चाहती है कि वहां पर पुल बना दिये जांय। जनता इसके लिये पैसा देने के लिये तैयार है। उनसे टैक्स के रूप में रुपया ले लिया जाय लेकिन उनके गांवों को पुल बना कर सड़कों से जोड़ दिया जाय। उनको उतनी सड़क की आवश्यकता नहीं है जितनी की पुल की आवश्यकता है। जहां पर गांवों में नदियां हैं या नाले हैं वहां पर बैलगाड़ी के द्वारा या छोटे-मोटे साधनों के द्वारा अपना माल शहरों तक वे ले जाते हैं। और जब पुल नहीं होते हैं तो उन नदियों पर ठेकेदार अपना मनमाना टैक्स वसूल करते हैं। इसके अलावा बैलगाड़ी से माल लाने वालों की बैलगाड़ी टूट

[श्री मुरलीधर कुरील]

जाती है और उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। पुल बन जाने से यह सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और ठेकेदार से उन लोगों को राहत मिल सकती है। अगर कुछ टोल-टैक्स देना होगा तो वह नामिनल होगा। इसलिये पुल की बड़ी सख्त जरूरत है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह खुशी की बात है कि पुलों पर टैक्स पैदल अथवा साइकिल से चलने वालों से नहीं लिया जायगा। टैक्स उन्हीं से लिया जायगा जो कि गाड़ियों पर अथवा मोटर पर माल लाते हैं और व्यापारिक दृष्टि से काम करते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि गांवों में श्रमदान से काफी सड़कें बनाई गयी हैं। बहुत से स्थानों पर गांववालों ने मिलकर कंकड़ अथवा इंटों से सड़कें या खड़ंजे बना लिये हैं। वह अच्छे हैं लेकिन जब एक बार सड़क बन जाती है तो उसके बाद उसका रख-रखाव नहीं हो पाता। उनके पास उसके साधन नहीं हैं, न उनकी इतनी शक्ति ही है। वह सड़कें एक फर्लांग, आध फर्लांग अथवा मील, दो मील की हैं। उनकी मरम्मत आदि की व्यवस्था इस विभाग को करनी चाहिये और इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि इस विभाग की ओर से ऐसी सड़कों के लिये एक सड़क फंड बनाया जाय जिस से इन सड़कों की मरम्मत हो सके।

इसके बाद मैं कानपुर के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कानपुर में चौबेपुर से बेला बिधूना एक सड़क जाती है जो कानपुर को इटावा से जोड़ती है फर्रुखाबाद की सरहद लेती हुई। इसकी हालत खराब हो रही है। इसका १० मील का एक हिस्सा तारकोल का बनने वाला था, लेकिन अभी नहीं बन पाया है। इसके साथ ही पांडू नदी पर एक पुल बनने वाला था वह भी नहीं बन पाया है। यदि यह काम हो जाय तो जनता को बहुत सुविधा हो जायगी।

एक सदस्य—टोल-टैक्स लेते हुये ?

श्री मुरलीधर कुरील—उसका मैं समर्थन करता हूं। जो अच्छी चीज है उसका समर्थन होना ही चाहिये और इसके अलावा जनता को उसमें कम परेशानी होती है और कम पैसा खर्च करना पड़ता है।

इसके अलावा ठेकेदारी के सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिये। कुछ ठेकों में देर से अदायगी होने के कारण ठेकेदार परेशान होते हैं और उससे नीचे के कर्मचारियों में थोड़ा-सा भ्रष्टाचार उठ खड़ा होता है। यह खुशी की बात है कि ऊपर के कर्मचारियों में इस विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसका अंत हो चुका है और इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधार अगर ठेकेदारी सिस्टम में हो जाय तो नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वह समाप्त हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इन सब अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी और उनके विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थोड़ी सी तवज्जह पहाड़ों की ओर भी की है, लेकिन वह काफी नहीं है और इसमें जो रुपया करीब ढाई करोड़ के लगता है, उसका अधिकतर भाग केन्द्रीय सरकार से आता है।

यहां पर भ्रष्टाचार की बातें भी कही गयीं लेकिन मैं उसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह बहुत पुरानी चीज हो गयी है, हर साल पुरानी बात को दुहराना भी ठीक नहीं है। दूसरे पी० डब्ल्यू० डी० और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। मैं यह मानता हूं कि बड़े-बड़े इंजीनियर्स ईमानदार आदमी हैं लेकिन नीचे के स्तर पर इतना ज्यादा करप्शन है जिसका अगर बखान किया जाय तो हाउस की हवा भी खराब होने का डर है। इसलिये श्रीमन्, मैं कुछ सिद्धान्तों की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

हमारी सरकार के द्वारा समाजवाद की स्थापना का नारा लगाया जाता है, समाजवादी समाज की स्थापना के मानी हैं पिछड़े हुये इलाकों को तरक्की वाले इलाकों के बराबर ले आना।

यह बात जरूर है कि इस बजट में इमारतों की कुछ ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जिसके लिये केवल निर्माण विभाग ही जिम्मेदार नहीं है, अन्य विभाग भी उसके लिये जिम्मेदार हैं । जैसे यहां एक लिफ्ट लगेगा, जिससे मंत्री महोदय सीधे ही केबिनेट रूम में चले जायेंगे । इसी प्रकार आवास-गृहों को बढ़ाया जा रहा है और कंधारी बाजार की सड़क चौड़ी की जायगी । इसमें कुछ भाग गिराया जायगा और कुछ नया बनाया जायगा । तो जिस समय कि एक-एक पाई के लिये हम तरस रहे हैं, ३२८ करोड़ का कर्जा यू०पी० की सरकार के ऊपर है और वह कर्जा हर साल भूत की तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में एक तरफ आप जिन इमारतों को मिस्मार करते हैं और दूसरी तरफ आप वैसी ही बनाते हैं, यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। यद्यपि आपकी राय में यह ठीक हो सकता है लेकिन मेरी नाकिस राय में ऐसी योजना में रुपया लगाया जाना ठीक नहीं है ।

हर साल हमारे प्रान्त में सैलाब आते हैं लेकिन अगर हम देखें तो वर्षा और सैलाब का दो तिहाई पानी पहाड़ों से ही आता है । क्यों नहीं पी० डब्ल्यू० डी० विभाग इर्रीगेशन आदि विभागों से मिल कर पहाड़ों में बड़े बड़े बांध रिहन्द बांध की तरह से बनाता है ? जहां पर बरसात में पानी को रोक लिया जाय और गरमी में जब पानी की हमें आवश्यकता हो, उस समय उसका सदुपयोग हम कर सकें ।

आज हम अंग्रेजी जमाने से कंपेरीजन करते हैं कि अंग्रेजी जमाने से अब सड़कें बहुत ज्यादा हैं । लेकिन अंग्रेज तो बाहर के थे, उनको हमारे मुल्क की तरक्की करने की क्या आवश्यकता थी ? अगर सफेद का कंपेरीजन काले से किया जाय, तो कहां तक उचित हो सकता है ? दूसरे देशों की ओर क्यों नहीं देखा जाता है ? वहां से कंपेरीजन क्यों नहीं किया जाता है ? क्या कारण है कि पैकिंग से ल्हासा व तकलाकोट तक सड़क बन सकती है लेकिन हिमालय से हमारे तरफ की सड़क अभी तक नहीं बनी है और हमारी मंडी की सड़क भी नहीं बन पायी ह । चीन तो आपके बाद ही आजाद हुआ है । मैं चीन का हिमायती नहीं हूं । उसकी पालिसी को गलत समझता हूं लेकिन जो चीज सही है उसको कहना ही पड़ता है । वहां तो १० हजार फीट ऊंचे पठार पर हजारों मील की सड़क बन सकती है लेकिन यहां, जहां तक अल्मोड़े जिले का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा कि हिमालय के इस पार सड़कें बनाने की रफ्तार तेज नहीं, बल्कि सुस्त रही है । मेहरबानी करके मंत्री जी ने जो अल्मोड़ा काकुला रोड को बनवाया, वह चीज नियामत की जगह अभिशाप सिद्ध हो रही है । कुछ लोगों के दिमाग में जो पुरानी आदत ब्यूरोक्रेसी की है, वही चली आती है और यह तो एक तरह से इंजीनियर्स की जिद्द है । यहां मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं कि यहां सड़क जानी चाहिये, यहां नहीं जानी चाहिये । बहरहाल, जिस जगह से सड़क ले जाई जा रही है, नदी के दायें किनारे से, उससे उधर की तमाम जमीन जो बहुत उपजाऊ है कट जायगी, नदी के बायें किनारे से भी सड़क ले जायी जा सकती है लेकिन इसके बावजूद भी उधर से सड़क को निकाला जा रहा है और उसमें ४० हजार रुपया ज्यादा खर्च होगा, माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में हाल ही में बतलाया था । यदि दूसरी तरफ से सड़क निकाली जाती तो यह ४० हजार रुपया बच सकता था । काफी जमीन भी कट जायगी फिर भी निर्माण विभाग के लोग इसको समझ नहीं पाते ।

श्री गिरधारीलाल––आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । यह जो बतलाया गया है कि मैंने प्रश्नों के उत्तर में कहा कि बजट में ४० हजार रुपये की कमी है, यह बात नहीं है । जो प्रपोजल पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से सड़कों के एलाइनमेंट के लिये था उसमें ४० हजार रुपया कम रखा गया है । इस वजह से यह ४० हजार रुपया ज्यादा हो गया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माफ करेंगे, सवालों का जो जवाब दिया गया था, उसके माने यही मालूम हुऐ । श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि सड़क इन्सान के लिये बनती है, इन्सान सड़क के लिये नहीं । यहां लिस्ट में हजारों, लाखों रुपया खर्च करने की बात भले ही की जाय लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है । माननीय मंत्री जी गरीबों की जमीन कटवाने के लिये तैयार हैं । एक तो ऐसे ही पहाड़ पर खेत कम होते हैं, जो थोड़ी बहुत जमीन होती है उसी में खेती करके वे अपनी गुजर बसर करते हैं लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि वे ऐसी जगह पैदा हुये हैं जिनके लिये न तो यहां कोई कहने वाला ही है और न कोई उनकी सुनने वाला ही है और न उनकी बात को कोई समझने वाला ही है । आज तो ऐसा मुझे मालूम होता है जैसे मैं पत्थरों के बीच में बैठा हुआ हूं, ये इन्सान नहीं हैं, बल्कि पत्थर हैं जो कभी पसीज नहीं सकते । ऐसे माननीय मंत्री जी तो बड़े सरल प्रकृति के हैं और उनके चीफ इंजीनियर का भी कसूर नहीं है । एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मैं स्वयं गया था, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इस चीज की जरूरत है लेकिन यहां पर दूसरी रिपोर्ट दे दी, तो इस तरह से दो तरफी बातें नहीं होनी चाहिये । इसलिये मैं कहता हूं कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिये।

कुछ छोटी-छोटी और आठ,आठ दस-दस मील की सड़कें हैं जिनको बनाने पर विचार करना जरूरी है । जैसे मल्ला लखनपुर की बमणस्वाल-कोल सड़क, सालम की थुआसीमल्ल-गुणादित्य सड़क, रीठागढ़ की कनाड़ीछीना-ठकुड़िया सड़क । कोई रेल की सड़क बनाने के लिये हम नहीं कह रहे हैं, महज, ६-६ मील , ८-८ मील की सड़कें हैं । तो माननीय मंत्री जी से मेरी बाअदब गुजारिश है कि अगले वर्ष जब वे सड़कों के बनाने पर विचार करें तो इस पर भी गौर करेंगे, इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है । प्लेन्स के लोग तो रेल से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के लिये सिवा सड़क से जाने के और कोई चारा नहीं है ।

इसके अलावा शीशा, लोहा , तांबा, चांदी आदि जो बहुत सी धातुएं पहाड़ों के अन्दर हैं, उनके प्रोसेस में भी कम खर्चा पड़ सकता है यदि यातायात के साधन अच्छे हो जाते हैं । श्रीमन्, टनकपुर से बागेश्वर तक की जो पुरानी रोड है और जिसका करीब-करीब एलाइनमेंट हो भी चुका है, कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है, इस सड़क का बनाया जाना बहुत जरूरी है ।

इसके अलावा एक बात मुझे यह भी कहनी है कि यहां टोकेन ग्रांट्स के नाम पर कुछ मांग मंजूर करा ली जाती है, जैसे १०० रु० की टोकेन ग्रांट हुई लेकिन होता यह है कि खर्च किसी दूसरी जगह कर लिया जाता है । कुछ आफिसर ऐसे हैं जो इस चीज को महसूस करते हैं लेकिन फिर भी जो आवश्यकता है उसकी तरफ डिपार्टमेंट वालों की तरफ से तवज्जह नहीं दी जाती है । अगर हमारी कम्युनिकेशन्स ठीक नहीं होंगी तो तिब्बत की फौजें आ जायंगी और हमारी फौजें नहीं पहुंच पायेंगी और फिर लाल झंडा फहरायेगा ।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि सैकड़ों बार की उठा-बैठी के बाद, एक वर्ष के बाद आपने मुझे फिर अवसर प्रदान किया । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । दुर्भाग्य से मैं उस जिले का रहने वाला हूं जो न पूरब में है और न पच्छिम में है, वह है जिला फतेहपुर जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में एक छोटा सा जिला है । इस जिले के बीच से जी० टी० रोड गई है और वही मार्ग यातायात का साधन और पक्का मार्ग है । इस का पूर्व इतिहास इस प्रकार है कि यह कलकत्ते से पेशावर तक का मार्ग था जो वर्त्तमान जी० टी० रोड के उत्तर होकर गया था जिसे पुरानी मुगल रोड कहते थे, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने रेल के समानान्तर नई जी० टी० रोड बनाई तो वह मार्ग फतेहपुर जिले से होकर बना और उसी मार्ग के किनारे सम्राट अशोक ने बड़े-बड़े कुयें, सराय की इमारतें और प्याऊ आदि बनवाई थीं और वह दूकानें सड़क के किनारे आज भी भग्नावशेष रूप में पड़ी हैं जो हमें पूर्व अतीत की याद दिलाती हैं । सम्राट अशोक के बाद शेरशाह सूरी व सम्राट अकबर तक उसकी देखभाल होती रही और वह शेरशाह के वक्त तक चालू रही लेकिन अंग्रेजी

शासन काल में वह खत्म हो गई। इधर ग्रोल्ड जी० टी० रोड फतेहपुर को छोड़कर और सब जगह पक्की हो गई है। जहानाबाद से जो मार्ग कानपुर को जाता है वही पुरानी मुगल रोड है जो बिलन्दा को मिलाती है और कड़ा तक कच्ची रह जाती है। उसी के बीच में कड़ा और कोंड़ा दो मुख्य स्थान थे जब फतेहपुर नहीं था और उसी के बीच में एक बड़ा कस्बा हथगाम पड़ता है, जो स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी के पूर्वजों की जन्म-भूमि है जो हमें अपने पुराने इतिहास की याद दिलाता है। हथगाम से फतेहपुर १८ मील की दूरी पर है लेकिन खागा से २२ मील दूर पड़ता है और कड़ा और फतेहपुर के बीच में वह कस्बा आज भी अपने जीर्णावशेषों को लिये वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दो पंचवर्षीय योजनायें तो देखते-देखते निकल गयीं परन्तु यदि वह आगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस पुराने राज्य मार्ग को ले लें तो वहां की जनता का बड़ा उपकार होगा, उस से एक बड़ा भूखंड जो बिलकुल कट आफ रहता है उसको यातायात का साधन सुलभ हो सकेगा।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि फतेहपुर के उत्तर डलमऊ रोड पर जो हसनगंज कस्बा है, वहां पर हथगाम से कड़ा को जानेवाला मार्ग बारिश को छोड़कर ८ मास तक लारी से संचालित रहता है, वहां पर रोडवेज की लारी न चलकर प्राइवेट लारियां चलती हैं और वह चार महीने बन्द रहता है। चार महीने बिल्कुल यातायात के साधन ठप हो जाते हैं। जनता को बहुत ही इससे कष्ट होता है। इसलिये यह मैं फिर याददिहानी के तौर पर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आप इसे भविष्य के प्लान में ले लें तो बहुत ही उस क्षेत्र का उपकार होगा जो कि आज पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे यह मालूम हुआ है कि चार मील का वह भाग जो एराथां हथगाम के नाम से प्रसिद्ध है उसे आप पक्का करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि सात मील के करीब हठगाम से कड़ा तक का कच्चा मार्ग रह जाता है। सिर्फ सात मील का वह खंड रह जाता है जो कि प्रयागराज जाने में डलमऊ-फतेहपुर मार्ग से पड़ता है, जो कि रात दिन चालू रहने वाला रास्ता है क्योंकि प्रयागराज एक बहुत बड़ा तीर्थ-स्थान है और मध्य में कड़ी में फिर शीतला जी का एक मन्दिर वहां पड़ता है जिसकी वजह से शीतला अष्टमी को वहां एक बड़ा मेला होता है और वैसे भी लोग देवी का दर्शन करके पुण्य लाभ करते हैं। तो, श्रीमान्जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि इस मार्ग को वह ले लें तो बड़ा सुन्दर होगा। वैसे तो सार्वजनिक निर्माण विभाग एक बहुत ही उपयोगी विभाग है क्योंकि बगैर सड़कों के, बगैर यातायात के साधनों के जनता को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। हमारे यहां किसानों को जहां सन और मूंज की पैदावार बहुत अधिक होती है अपना सामान खरीद फरोख्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। बनारस में शिवपुर में सन की बहुत बड़ी मील है। वहां से सीधे अमरीका को सन सप्लाई होता है। तो अगर किसान अपना कच्चा माल वहां पहुंचा सके तो थोड़े से पैसे उनको और मिल सकते हैं। इस प्रकार से वह क्षेत्र जो खागा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और जिसका कि एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसके लिये मैं मंत्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि उस क्षेत्र को सड़कों से सम्बन्धित कर दें।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज बहुत दिनों तक खड़े होने के बाद मुझे मौका दिया गया है बोलने के लिये, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके द्वारा निर्माण विभाग की प्रगति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। निर्माण विभाग

[श्री भूप किशोर]

की प्रगति बिलकुल नहीं के बराबर है। बेकारी दूर करने के लिये निर्माण विभाग की तरफ से जो सड़कों की स्कीम सन् १९५७ में बनाई गई थी १३ मील की उसमें से कुल ९ मील ही बन पायी। कच्ची सड़कें पहाड़ी १२१ मील बनाने के लिये जिक्र था लेकिन ३८ मील बनी। मरम्मत के लिये २१ मील सड़कें रखी गईं थीं, उसमें से एक भी मील का सुधार नहीं हुआ। इसी तरह से निर्माण के लिये ४०३ मील पक्की सड़कों की स्कीम थी जिसमें से २४४ मील का निर्माण हुआ। जहां ३३ मील सड़कों का निर्माण होना चाहिये था वहां केवल ७ मील का निर्माण हुआ। अब मैं अपने जिले की तरफ आता हूं। तहसील अलीगंज सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां सब से ज्यादा डाकू पैदा हुये हैं, होते आये हैं और होते रहेंगे। मानसिंह का भी जन्म हमारी तहसील के एक गांव में हुआ था। इसका कारण यह है कि हमारा क्षेत्र सब से पिछड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य काफी प्रोत्साहन भी देते चले जा रहे हैं, डकैती को बहुत जोरों से।

श्री भूपकिशोर---इसीलिये सड़कें बनवाना चाहता हूं, जिससे डकैतियां बन्द हो जायं। तहसील अलीगंज में सराय अगहत तक १४ मील का जो फासला है उस पर सरकारी अफसरों के आश्वासन के बाद श्रमदान कार्य हुआ, मिट्टी डाली गई, लेकिन वह अभी तक पक्का नहीं हुआ। इसी तरह से अलीगंज से बिलसर तक श्रमदान किया गया लेकिन यह ५ मील का टुकड़ा अभी तक पक्का नहीं हुआ। इसी तरह से जैथरा से पहरा तक १४ मील के टुकड़े पर श्रमदान हुआ लेकिन वह भी पक्का नहीं हुआ। सराय अगहत पुराना तीर्थ स्थान है। जिला फर्रुखाबाद से यहां तक पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है लेकिन अलीगंज तक पक्का होना आवश्यक था। सराय अगहत बुद्ध जी का जन्म स्थान है। पारसाल भी मैंने इस तरफ ध्यान दिलाया था लेकिन कोई खयाल नहीं किया गया। काली नदी पर पुल दो साल से बन रहा है। लेकिन काम इतना सुस्त हो रहा है जो अभी तक नहीं बन पाया है। अमरौली से फर्रुखाबाद तक पक्की सड़क का निर्माण होना बहुत जरूरी है। अमरौली से अलीगंज तक पक्की सड़क बन गयी है। अगर यह सड़क पूरी पक्की बन जाय तो हमारे जिले का व्यापार काफी बढ़ सकता है। फर्रुखाबाद से हमारे जिले का काफी व्यापार होता है, वहां की मंडियों में हमारे जिले से सब सामान जाता है। इसलिये अमरौली से फर्रुखाबाद तक सड़क का निर्माण कराया जाय। फर्रुखाबाद में कम्पिल तीर्थ-स्थान है। यहां भारत के कोने-कोने से यात्री आते हैं। रुदायन स्टेशन से कम्पिल तक जाने के लिये पक्की सड़क नहीं है। यह दूरी ६ मील की है। मेरा निवेदन है कि इस स्थान के महत्व को देखते हुये इस ६ मील की सड़क को पक्की बनवाया जाय। श्रीमन्, हमारे यहां इस कदर सड़कों की कमी है जिसकी वजह से डाकुओं का काफी जोर रहता है और पुलिस कोई कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि तहसील अलीगंज में ज्यादा से ज्यादा पक्की सड़कें बनवायी जायं।

हमारे जिले में ऐसी गलत सड़कों का जिक्र किया गया जो ऐसी हैं जिनसे दो एक आदमियों को ही फायदा है। कुछ एम० एल० ए० और एम० एल० सीज० के फार्मों तक ही वह सड़कें जायंगी। उनसे जनता को कोई फायदा नहीं होना है। थाना दरियावगंज से कासगंज तक सड़क की बहुत आवश्यकता थी। अगर यह सड़क बन जाती तो सारा जिला ग्रान्ड ट्रंक रोड से मिल जाता। ऐसी गलत सड़कें बनवाने से जनता का पैसा खराब जाता है।

श्रीमन्, रामपुर में एक ऐग्रीकल्चर स्कूल है जिसके बारे में सवाल किया था लेकिन उसका माकूल जवाब नहीं मिला। उस एग्रिकल्चर स्कूल की इमारत बननी है। उस स्कूल के पास १०० बीघे जमीन है, उसके पास मास्टर भी हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से इमारत नहीं बन पायी है। मेरा निवेदन है कि इस स्कूल को सहायता दी जाय। मैं अधिक न कहकर इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे जिले की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। सड़कें बहुत कम रखी गयी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां सड़कें बनायी जायं।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे डिबेट का प्रवाह देख कर कुछ थोड़ी सी निराशा हुई । जो स्पीचेज हो रही हैं वे ज्यादातर इसी बात पर हो रही हैं कि अमुक सड़क बननी चाहिये थी, हमारे जिले में यह कमी रह गयी है । लेकिन जो पी० डब्ल्यू० डी० की कार्य प्रणाली है, उसका स्ट्रकचर है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है । मैं इसलिए डिबेट के प्रवाह को थोड़ा बदलना चाहता हूं ।

मेरा खयाल है कि पी० डब्ल्यू० डी० एक काफी अच्छा काम करते हुए भी कुछ बदनाम सा विभाग है । काम अच्छा करता है । सड़कें और मकान बनाता है और अन्य जरूरी काम करता है । लेकिन इसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं बन पायी है और इसीलिये जैसा एक तरफ से कहा गया, यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट है और मुझे तो एक साहब ने बताया कि इसका नाम प्लंडर विद्आउट डेंजर डिपार्टमेंट होना चाहिये । मैं ऐसा नहीं मानता । मैं सिर्फ उसकी साख बतला रहा हूं ।

जिस तरह का इसका ढांचा है उसमें केवल यह कहना काफी नहीं है कि रिश्वत ली जाती है, भ्रष्टाचार होता है । वह तो इन्हेरेंट है उस ढांचे के अन्दर भ्रष्टाचार और देरी का होना । मामूली तरीके से जब सेक्रेटेरियट से बजट पास हो जाता है तो इसका ढांचा यह है कि प्रपोजल्स वहां बनते हैं, फिर सेक्रेटेरियट में वे आयेंगे और फिर फायनेन्स डिपार्टमेंट में वे जायंगे । ५–६ महीने फायनेलाइज होने में इस तरह लग जाते हैं । आखिर में ३–४ महीने में काम होता है और फिर ख्वाहिश यह होती है कि जल्दी से जल्दी किया जाय चाहे मिट्टी पड़ जाय । लिहाजा इस सिस्टम के अन्दर खामियां तो हैं ही और मैं यह तवक्को करता हूं कि उनको दूर करना चाहिये और कुछ ऐसा सादा सिस्टम बनना चाहिये जिससे कम से कम ८–९ महीने सड़कें व इमारतें बनने में लगें । जो आखिरी बक्त में काम शुरू किया जाता है उससे बहुत काफी पैसा जाया होता है । इसके साथ साथ जो और दुर्गुण पैदा होते हैं वे भी उसके अन्दर इनहेरेंट हैं । मैंने अपने पिछले साल के बजट में भी इस बात की चर्चा की थी और फिर मैं उसे आज दोहराना चाहता हूं । पी० डब्ल्यू० डी० का महकमा एक तरीके से पब्लिक सेक्टर का बड़ा काम करने वाला महकमा है । इसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है और इसके जरिये कुछ ऐसे कदम उठ सकते हैं कि जिस तरफ हम जाना चाहते हैं उस तरफ हम बढ़ सकें । जब करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिये कि वह हमें समाजवाद की तरफ ले जाय, वह हमें कोआपरेटिव फंक्शनिंग की तरफ ले जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये बड़े अदब से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक हमारे समाज के अन्दर यह व्यक्तिगत ठेकेदारी, निजी तौर पर मुनाफा कमाने और कल कारखाने चलाने की प्रथा रहेगी तब तक कोई भ्रष्टाचार दुनिया से रोक नहीं सकता । भ्रष्टाचार डबल वे ट्रैफिक है । महज सरकारी नौकर भ्रष्टाचारी होता है, ऐसी बात नहीं है । समाज के अन्दर ऐसे अनासिर हैं, जैसे ठेकेदार कि वह उसको भ्रष्टाचारी बना देते हैं । तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको हम खत्म करें और उसके अन्दर हम कोआपरेटिव के अनासिर बढ़ायें । दलील यह दी जाती है और समझदार लोगों की तरफ से दी जाती है जिसे सुन कर मुझे हैरत होती है कि कोआपरेटिव तो हम चाहते हैं मगर कोआपरेटिव का तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सहाय]

है । कोयले वगैरह के अन्दर कुछ कोआपरेटिव का काम किया था, उसमें गबन हो जाते हैं और चूंकि उसका तजुर्बा ठीक नहीं होता इसलिये उसको अपनाने में हम हिचकते हैं । लेकिन महज गबन वगैरह की वजह से हम उसको छोड़ दें तो हम उस मकसद से हट जायंगे, उस पालिसी और प्रोग्राम से हट जायंगे जिसके पूरा करने का तहैया हमने किया है । मैं उदाहरण के लिए मिसाल देता हूं कि देहली के अन्दर भारत सेवक समाज ने एक बांध बनाने की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और सकड़ों नागरिकों ने उसमें मदद की और श्रम दिया । इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट और उसके जो ओवरसिअर थे, ठेकेदार थे, सब ने कहा कि यह नामुमकिन है और यह तजुर्बा नहीं करना चाहिये । आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तजुर्बा करना चाहते हैं और मैं आपके जरिये यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जिस वक्त जमुना ने हमला बोला बांध के ऊपर तो देहली शहर के लाखों आदमियों की हमदर्दी थी कि यह हमारे श्रम से बना है और बान्ध जो बना था उसने मजबूती से मुकाबिला किया । नागरिक कहते थे कि यह जनता ने अपने श्रम से बनाया है, यह कोई ठेकेदारों का बनाया हुआ नहीं है कि ढह जायगा, इसमें जनता का श्रम लगा है और उसकी वजह से हमारा दिल लगा है । तो कोआपरेटिव से जो काम होता है उसमें श्रम और प्रेम होता है, जोड़ होता है, वह महज एक ढेर नहीं बनता है ईंट और गारे का, उसमें भावनाएं जोड़ी जाती हैं । हमको इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहिये । मुझे खुशी है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस बात से सहमत हैं । जितनी उनके बारे में जानकारी हुई है, उन्होंने बताया कि ओवर-सियर और इंजीनियर से उन्होंने कह दिया है कि यह काम भी करके देख लो । मैं बड़े अदब से कहूंगा कि ओवरसीयर और इंजीनियर जो इस सिस्टम की पैदावार हैं उनके दिमाग एक खास तरीके से ढल गये हैं और अगर उनसे कहा जाय कि एक काम मेरे पास आया था, जरा इसको भी देख लेना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । तो यह कोई पायस विश, शुभकामना नहीं है कि इसको ट्रांसफर कर दें कि इसको भी करके देख लेना । हमको तो तैयार रहना पड़ेगा कि जो हमारी मौजूदा सर्विसेज हैं, जो मौजूदा ढांचा है वह उसका विरोध करेगा । जिन लोगों को उसका फायदा होता है वह कैसे मंजूर करेंगे ? इसलिए उनके गले में से उतारना पड़ेगा कानूनी तरीके से, कुछ समझा करके, कुछ और तरीके से । तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बतौर एक्सपेरिमेंट २०–३० जगह ले लें और वहां के लिए ऐलान कर दें कि कौन-कौन कोआपरेटिव के लोग कितनी-कितनी सड़क इस बेसिस पर बनाना चाहते हैं । उसको कराने के लिए एक पब्लिक ओपिनियन पैदा करनी पड़ेगी, लोगों में कम्पटीशन की स्प्रिट पैदा करनी पड़ेगी कि कोआपरेटिव के तजुर्बे को कौन-कौन अपने यहां चालू करना चाहता है ।

बिल्डिंग्स के मुताल्लिक मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी खूबसूरत बनती हैं और डिजाइन्स भी बड़ी अप-टु-डेट होती हैं, मगर मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं ये बड़े आउट आफ डेट हैं । जब मैं यह बात कहता हूं तो यह समझ कर कहता हूं कि इंजीनियर दोस्तों को बड़ा ताज्जुब होगा और जिनकी शायद मेरे बारे में यह राय है कि यह बात माकूल करता है, वह ताज्जुब करेंगे कि यह क्या नामाकूल बात कर रहा है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जिस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हो रहा है वह हिन्दुस्तान के हालात और जरूरत के मुताबिक नहीं हो रहा है । मैं यकीन से यह कह सकता हूं कि और किसी मुल्क के अन्दर, खास कर किसी सोशलिस्ट मुल्क के अन्दर अगर दारुलशफा जैसी बिल्डिंग बनी होती तो इंजीनियर, ओवरसीयर, सारा स्टाफ डिमोट कर दिया गया होता । क्या आर्किटेक्चर हमने बनाकर दिया है ! कहां तो हमारे लिए आबोहवा खुली होनी चाहिए थी, वहां सब कमरे ही कमरे बनाकर दे दिये हैं और एक एक कमरे में २१–२१ हजार रुपया लगा दिया है । यह इन्तजाम स्विट्जरलैंड के लिए मौजूं हो सकता था, ठंडे मुल्क के लिए ये ऊंचे-ऊंचे ढांचे मौजूं हो सकते थे, इस मुल्क के लिए मौजूं नहीं हैं और यह बताता है कि हमारे इंजीनियर्स नक्ल करते हैं एक ऐसे आर्किटेक्ट की जो हमारे मुल्क की आबोहवा और स्थिति के अनुकूल नहीं है । इसलिये जरूरत है उनके दिल में यह तरबियत पैदा करने की । और जब मैं यह विचार व्यक्त कर रहा हूं तो एक दारुलशफा की ही बात नहीं है । दिल्ली के अन्दर लाल किले के

सामने जो बिल्डिंग बनी है उसको देख कर आखिर में प्राइम मिनिस्टर को ताव में आकर यह कहना पड़ा कि ऐसी बिल्डिंग को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए क्योंकि यह फिट इन नहीं करती है लाल किले से और न जामा मस्जिद से । तो आर्किटेक्ट महज पास करने से ही नहीं आता है, इसके लिये एक प्रोग्रेसिव आउटलुक की जरूरत है । तो एक तो मुझे इस आर्किटेक्ट के बारे में यह कहना है कि यह हमारी आबोहवा में फिट नहीं करता है । दूसरे यह कि वह बड़ी जल्दी टूटने फूटने लगता है । ओबवियस बात है, कौन जिम्मेदार है, यह पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर फाइल चले तो उसमें तो कभी भी ऊपर के लोग तो पकड़ में आते ही नहीं हैं । फाइल का तो मेरा अपना तजुर्बा यह है कि जितने सीनियर आफिसर्स एक जगह कहीं गिरफ्त में आते हैं वे कहीं दूसरी जगह तरक्की पा जाते हैं । इसका तजुर्बा ओरिजिनल होना चाहिये । अगर कोई बिल्डिंग दो साल के अन्दर चूने लगती है तो ऐसे स्ट्रिन्जेन्ट मेजर्स होने चाहिये कि जितने भी लोग उससे एसोशियेटेड हों वे सब डिमोट कर दिये जायं । यह पुराना तरीका हमको कहीं ले नहीं जाता कि पहले तो विभाग की खूब बुराई की कि बड़ा करप्शन है और बाद में कहा कि हमारे जिले की फलां सड़क बनवा दी जाय ।

तो मैंने दो, तीन बातें सुझाव के तौर पर मिनिस्टर महोदय से कहीं और मैं उनकी जानकारी के लिये बिजनौर जिले को पेश करता हूं । वह उस जिले की जांच करें क्योंकि यह उनके लिये भी आसान होगा और मेरे लिये भी आसान होगा । जब मैं यह सुनता हूं कि मेरे जिले में फलां ओवरसियर सीमेंट बेचता है, फलां यह चीज बेचता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है । अब मैं शिकायत क्या करूं ? खुशकिस्मती से मिनिस्टर महोदय और मैं दोनों एक ही जिले से आते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं, हमारे जिला बिजनौर में एक सड़क है बढ़ापुर .....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

माननीय बंशीधर शुक्ल अब बाद में अपना भाषण आरम्भ करेंगे ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में जो विरोधी पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उस संबंध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं । बात यह है कि आजकल जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार सब से पहले सरकारी नौकरों के लिये मकान बनवा देती है और उनके आने जाने के लिये सड़क बना देती है और बस निर्माण कार्य हो गया । बहुत हुआ तो एक आफिस खोल दिया जाता है और दफ्तर के बाबू लोग एक तो गांव में जाने से वैसे ही डरते हैं और जाते भी हैं तो कुछ सुझाव दे देते हैं । हमें निर्माण की आवश्यकता है, सरकारी आफिसरों की कोठियों की नहीं, इस तरह से व्यर्थ के अफसरों और व्यर्थ के महकमों की जरूरत नहीं है । आज सड़कों व पुलों की जरूरत है । नये-नये कारखानों की जरूरत है । क्या सरकार अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकती है कि जो निर्माण कार्य अंग्रेजों ने किया था उससे ज्यादा मजबूत कोई काम यह सरकार कर सकी है ?

हमारे यहां पलिया कालोनी में सरकार ने करोड़ों रुपया लगाया है । लेकिन हम पूछते हैं कि इस पर कितना रुपया खर्च हुआ तो सरकार बतलाती नहीं है । प्रश्न पूछते हैं लेकिन कोई

[श्री बंशीधर शुक्ल]

बात नहीं बताई जाती है। तीन ट्यूबवेल्स सरकार की ओर से बनाये गये हैं जिनमें १,४५,००० रुपया लगा है जब कि सरदार करतार सिंह ने ७०० रुपये में ही एक ट्यूबवैल बनवा दिया है। निर्माण को और भी बात देखिये। गोमती का पुल है, उसका एस्टीमेट एक लाख चालीस हजार का लगाया गया था। लेकिन वहीं के रहने वाले रोशन लाल जी हैं उन्होंने साढ़े तेरह हजार में ही पुल बनवा दिया। इसी तरह से वैल में सोड स्टोर के बनाने के लिये ८८ हजार रुपये की रूपरेखा बताई गई। लेकिन हमारे यहां के चेयरमैन रतनसिंह जी ने उसको बनवाया और १३,००० रूपये से भी कम उसमें लगा है और बहुत बढ़िया बना है। आज यह देश के पैसे की दुर्दशा हो रही है। आज निर्माण की आवश्यकता है, सरकारी नौकरों की नहीं। आज पलिया कालोनी में सरकार की ओर से जो क्वार्टर्स किसानों के लिये बनाये गये हैं वह ५२,००० में चार बनाये गये हैं। वह बरसात में चूते हैं और एक में दो चारपाई ही पड़ सकती हैं। सीमेंट वगैरा कुछ नहीं लगाया गया है और चार दरवाजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---पी० डब्लू० डी० ने बनवाये हैं या किस विभाग ने बनवाये हैं ?

श्री बंशीधर शुक्ल---यह पी० डब्लू० डी० द्वारा बनवाये गये हैं। एक मेहमान गृह भी बनवाया गया है जिसमें ५२,००० रुपया लगा है। जो निर्माण कार्य हुआ है वह सरकारी अफसरों की कोठियों और सरकारी क्वार्टरों का ही हुआ है और कोई निर्माण नहीं हुआ है जब कि हमारे जिले में ३० सड़कें हैं और एक सड़क केवल पक्की है। वहां पर कुदरत की कृपा से ३० छोटी बड़ी नदियाँ हैं। उनमें शारदा पर पुल है और २-३ और छोटे छोटे पुल हैं। ऐसे छोटी-छोटी नदियां बहुत हैं जिन पर कोई पुल ही नहीं है। जब सरकार से कहा जाता है कि वहां पर पुल बनाया जाय तो कहते हैं कि इतना लाख रुपया लगेगा इस वास्ते बनना बहुत मुश्किल है। इस पर कहना यह है कि हमारा जिला इतना लम्बा-चौड़ा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरा जिला इतना बड़ा नहीं है। १३५ मील लम्बा निघासन तहसील से लेकर शाहजहांपुर के किनारे तक चला गया है। शाहजहांपुर वहां से ४ मील रह जाता है। तो इतने बड़े जिले में केवल एक सड़क पक्की है जो अंग्रेजों के जमाने में निर्माण हुई। वहां पर ३ सड़कों में केवल एक सड़क इस तरह की है। दूसरी सड़कों को बनाने के लिए यह कहा जाता है कि इतना रुपया लगेगा। निर्माण के सम्बन्ध में आपके यहां आफिस में लिखा हुआ है कि लखीमपुर में ४ करोड़ रुपया लगेगा जब कि २ करोड़ रुपया जनता देगी। न २ करोड़ रुपया जनता दे पायेगी और न यह निर्माण का काम होगा। इसी प्रकार से चार और विभाग हैं जो इस निर्माण के काम को कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पी० डब्लू० डी०, प्लानिंग डिपार्टमेंट और पंचायतराज यह सब सड़क बना रहे हैं। जब सड़कों के बनाने की बात आती है तो उस बिना पढ़े-लिखे ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है जो जानते भी नहीं कि किस तरह से सड़क को बनाया जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि इन महकमों को ही तोड़ दिया जाय, इस पी० डब्लू० डी० की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता पर आपको विश्वास नहीं है। आपके गणतन्त्र में जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। सम्पूर्णनिगर जो लखीमपुर में बनाया गया है उसमें कितने ही सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर बनाये गये हैं। उन क्वार्टरों पर वाटर वर्क्स और बिजली लगी हुई है। उसके पड़ोस में ही गांव में किसानों के मकान हैं वहां कुछ नहीं लगाया गया है। इतना रुपया सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों पर तो खर्च कर दिया जाता है पर गांवों में कुछ नहीं किया जाता। सरकार से जब यह पूछा जाता है कि कितना रुपया इसमें खर्च हुआ तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इस तरह की बातें सरकार की ओर से हो रही हैं। तो सरकार से हमारा कहना यह है कि अगर सड़कें और पुल बनाना है तो इनका काम ठेकेदार को न दिया जाय। ईमानदार आदमियों को ढूंढ़कर यह काम दिया जाय। अभी थोड़े दिन तक ईमानदार आदमी मिल जायंगे फिर थोड़े दिनों के बाद नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने ईमानदार आदमियों की कदर करनी छोड़ दी है। जहां पर सड़क का काम शुरु किया जाय वहां पर आप पानी के लिये

इन्तजाम करें जिससे वह निकल जाय । ६ इंच की नाली खोदकर पानी का ढाल बनाया जाय जिससे पानी निकल जाय । निर्माणक को यह बात बतला दी जाय । अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो फिर यह १५ करोड़ रुपया जनता को दे दें वह अपने आप सड़कों का निर्माण कर लेगी । सरकारी इमारतों को और अधिक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है । नई इमारत बनाने की क्या जरूरत है जब कि इनका इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा है ? रियासतों के बने मकान बहुत से खड़े हैं उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है ? और जब थोड़े दिन बाद आपकी यह सरकार समाप्त हो जायगी तो आप के बनाये इन मकानों को कौन इस्तेमाल करेगा ? हमारी तो जब सरकार आयेगी तो वह आपके बनाये २८ महकमों को तोड़ देगी और फिर उनकी इमारतों, आफिसों और सामान का क्या होगा ? केवल इन अफसरों के लिए इमारतें बना कर देश कैसे आगे बढ़ेगा ? सड़कों का निर्माण जनहित में होना चाहिये । एक सड़क लखनऊ से टिकैतनगर हो कर महमुदाबाद ईसानगर पलिया तक चली गयी थी और वह पलिया से आगे चलकर पीलीभीत, टनकपुर तक चलती थी । लेकिन आज वह छिन्न-भिन्न पड़ी है । अगर आप पुरानी सड़कों की मरम्मत भी कर दीजिये तो अच्छा हो ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय शान्ति प्रपन्न जी माइक पर बात कर रहे हैं जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है और भाषण सुनाई नहीं पड़ रहा है । एक साथ दोनों आवाजें आ रही हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि वे शान्त रहें ।

श्री बंशीधर शुक्ल—मेरा लखीमपुर जिला तो कुदरत से भूला हुआ जिला है । उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । एक सड़क फूलबेंहड़ की तरफ बनायी गयी थी और पिछले ८–१० वर्ष में वह ६ बार बनायी गयी और प्रतिवर्ष उस पर कुछ न कुछ खर्च होता है । जो पैसा खर्च होता है वह ठेकेदार और इंजीनियर मिल कर खा जाते हैं और सड़क पर कहीं कंकड़ बिछा दिया जाता है और कहीं बालू और वह बैलगाड़ी चलने से इधर उधर उड़ जाता है । तो यह आपका सड़कें बनाने का ढंग है । तो मेरा कहना है कि पहले सड़कों और पुलों का निर्माण कीजिये । लखीमपुर में ही नहीं, जिन जिलों में सड़कों की खास जरूरत हो उनका निर्माण कीजिये ताकि जनता का कल्याण हो सके । जनता की ओर देखिये । यदि आप आकाश-आकाश उड़ कर या सरकारी नौकरों के कहने से उन के पोषण के लिये नये-नये विभाग खोलते रहेंगे तो यह सरकार ठीक से नहीं चल सकेगी । पलिया की . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार मैं किसी चीज को दोहराने नहीं दूंगा । इसी विषय में कुछ और कहिये, सारे प्रदेश का मसला पड़ा है ।

श्री बंशीधर शुक्ल—आप से कहना यही है कि एक तो ठेकेदारी सिस्टम समाप्त किया जाय और दूसरे यह कि आप अपने आप सड़कें बनवाइये और उसके लिये जनता से सलाह लीजिये । आप उसकी कुछ सुनिये । इस ढंग से जो सड़कें बनेंगी वह उसके लाभ के लिये होंगी और बन जायंगी । पुलों की जहां जरूरत हो वहां पुल बनवाइये । शारदा नदी का पुल बनाने की बहुत जरूरत है । अंग्रेज होते तो अब तक बन भी जाता, लेकिन आपकी सरकार हर साल उसका एस्टीमेट ही बनाती है । छोटी शारदा का पुल बनाने का विचार होता है लेकिन वह बनता नहीं । लखीमपुर जिला इस तरह का है कि आधा इधर आधा उधर बीच में नदी शारदा । बरसात में लोग इधर उधर आ जा नहीं सकते । इधर की दुनिया उधर दिखाई नहीं देती । उस जगह अगर पुल निर्माण का विचार हो, तो उसे करे कौन ? सरकार की ओर से

[श्री बंशीधर शुक्ल]

कोई विचार नहीं, हम लोगों को दरख्वास्त पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। निर्माण के लिये पहले जनता को लोहा, सीमेंट, लकड़ी आदि फ्री दीजिये। अंग्रेजों के राज्य में सीमेंट १ रु० ५ आने बिकती थी, आज ६ रुपये है। अंग्रेजी राज्य में १०-१५ रुपये में ईंट मिलती थी, आज ३० रुपये में बिक रही है। अंग्रेजों के जमाने में लकड़ी कितनी सस्ती थी, आज कितनी महंगी है और मिलती ही नहीं। तो जनता को निर्माण के लिये समय और साधन दिये जायं। जब देश का निर्माण होगा तब आपका निर्माण होगा और जनता का निर्माण न होने से आपकी सरकार बैठ जायगी और देश रसातल को चला जायगा।

श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। आज सदन में निर्माण विभाग की ओर से जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय शुक्ल जी अभी इसकी आलोचना करते हुये कहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा मिटा दी जाय, अधिक पुल तथा सड़कें बना दी जांय। ठीक है लेकिन इस सबके लिये धन की जरूरत है और उसके लिये उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इस विभाग को अधिक धन इस कार्य के लिये दिया जाय। वह कहते हैं कि पहले १ रुपये की जगह अब ६ और १० रुपये लिये जाते हैं लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिये कि पहले रुपये और चीजों के मूल्य में कितना फ़र्क था। जैसे ट्यूबवैल या सिंचाई विभाग की आलोचना की जाती है, वैसे ही इस विभाग के लिये कहा जाता है कि इसके इंजीनियर्स और ओवरसीयर्स ग़लत काम करते हैं। मेरा कहना है कि इस विभाग की ओर से आज तक बहुत ही अच्छे काम किये गये हैं। काम करने वालों की आलोचना ही हम करते रहें जो अपने ही देश के भाई हैं, तो उनका उत्साह हम नहीं बढ़ा सकते हैं।

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे सड़कें पहले ली जावें जो छोटी हैं, १० या ५ या २० मील की ही सड़क बनाने से २-३ जिलों को मिलाती हैं। जैसे एक सड़क फैजाबाद जिले में टांडा से अकबरपुर तक पक्की है। वह सड़क अकबरपुर से दोस्तपुर तक और उसके आगे पट्टी तक मिलाने की व्यवस्था की जाती है। यदि वह सड़क पहुंच जाय तो बस्ती के शोहरतगढ़ से इलाहाबाद तक का बड़ा अच्छा रास्ता तैयार हो जाता है। मालीपुर से जलालपुर की सड़क का सम्बन्ध प्रतापगढ़ व देरा बाजार से दोस्तपुर बाजार और बलिया तक मिलता है। यदि यह सड़क सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर कस्बे तक ८ मील और बढ़ा दी जाय तो इस से करीब ३-४ जिलों की यात्रा में बड़ी सुविधा होती है। इस से हमारे जिले सुल्तानपुर के दोस्तपुर क़स्बे की उन्नति हो सकती है।

जैसा मैंने इस बजट में देखा, कहीं-कहीं तो २,३ डिप्टी कमिश्नरों के बंगलों के लिये लाखों रुपया खर्च कर दिया गया और कहीं-कहीं प्रदेश के कीमती हिस्सों में कोई काम नहीं किया गया। गोमती नदी पर जौनपुर-सुल्तानपुर के बीच करीब ७०,७५ मील तक कोई पक्का पुल तो क्या, लकड़ी या नाव के पुल की भी व्यवस्था नहीं है। धन का अभाव है तो आप पीपे या नाव का पुल ही बना दें तो यातायात की सुविधा हो सकती है। परिवहन विभाग के बजट पर बोलते हुये दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने काफ़ी प्रशंसा की कि गांव वालों को हर जगह बस मिल जाती है। लेकिन यदि सड़कों की अच्छी हालत नहीं है तो बसें जल्दी खराब हो जाती हैं। इसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है और कहा जाता है कि ४ साल में ही बसें क्यों टूट गईं। इसलिये सड़कों का बनना और भी आवश्यक है। गन्ने को मिलों में पहुंचाने के लिये भी सड़कों की आवश्यकता है। टोलटैक्स की चर्चा करना उचित नहीं है। हमारे क्षेत्र के बहुत से लोगों ने पुल बनाने के लिये रुपया दान भी दिया। मालीपुर के दक्षिणी भाग पर पुल बनाने के लिये रुपया दिया गया लेकिन सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी सड़कों और पुलों के लिये वह अधिक रुपया दें।

चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे निर्माण विभाग हो या पुलिस का विभाग हो, वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी कर्मचारी अच्छे हैं लेकिन जहां हम खराबी पावें उसके लिये

हमें कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिये। लेकिन साथ ही हमें उन लोगों की कठिनाइयों को भी देखना है। छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें अच्छी नहीं हैं। उनको अन्य सुविधायें भी नहीं हैं। इसीलिये यह कहा जाता है कि उनमें भ्रष्टाचार ज्यादा है। उनको सुविधायें देने से उनका भ्रष्टाचार दूर होगा।

मेरा सुझाव है कि ठेकेदारों को पेमेंट के समय निरीक्षण किया जाय। जहां हर जिले में पी० डब्लू० डी० ऐडवाइजरी कमेटियां बनी हुई हैं, विधान सभा के सदस्य उनके सदस्य हैं, तो उन लोगों को उनके कामों को देखने का अवसर मिलना चाहिये। जिन म्युनिसिपिल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के क्षेत्र में काम होता है उनके चेयरमैनों को भी यह अवसर होना चाहिये। इससे अधिक सुविधा से कार्य हो सकता है।

एक बात और है। जो रुपया हम बजट में जिन कामों के लिये हर साल रखते हैं उस काम को कार्यान्वित करने की अधिक से अधिक चेष्टा सरकार को करनी चाहिये।

श्री रघुबीरराम (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज सदन के सम्मुख मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिये हैं।

अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे सूबे के क्षेत्रफल के अनुसार सड़कों और पुलों की संख्या में बहुत कमी है। और उसका खास कारण मंत्री महोदय यह बतलाते हैं कि धन का अभाव है। लेकिन इन बातों से मंत्री महोदय इस उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण और समाजवाद की स्थापना करना चाहेंगे तो १० क्या पचासों वर्षों में भी नहीं कर सकेंगे।

आज पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों के साथ ठीक तौर से कदम नहीं उठाया जाता है मजदूरों के श्रम का सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता है और बड़े-बड़े इंजीनियर और ओवरसीयर उस चीज को अपने पेट में हज्म कर जाते हैं। और वे गरीब मजदूर उस से फायदा नहीं उठा पाते। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पर जरा आप ध्यान दीजिये। मैंने अपने यहां देखा कि इंजीनियर और ओवरसियर को ठेकेदार लोग महीना दिया करते हैं और वह मजदूरों का गला काटते हैं। मजदूरों को पैमाइश के लिये ५ फिट का गज दे दिया जाता है और खुद तीन फिट का अपने लिये रखते हैं। इस तरह २ फिट यह अपने पेट में रखते हैं। इतनी बड़ी धांधली ये अपने डिपार्टमेंट में करते हैं। इसके अलावा २-४ इंच इधर उधर कर भी लेते हैं। इस प्रकार से इस विभाग में मजदूरों का बड़ा भारी हनन हो रहा है।

दूसरी बात आपके समक्ष मुझे यह रखनी है और आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं। बाढ़ के इलाकों में आपके ओवरसियर और इंजीनियर मनमानी करते हैं। जनता की बिलकुल राय नहीं ली जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये लोग जनता से भी राय ले लिया करें। आजमगढ़ जिले में जनता ने बार-बार कहा कि यहां पर जो सड़क है इसको ज्यादा ऊंचा न किया जाय लेकिन एक न सुनी। ऊंचा किया; इसका परिणाम यह हुआ कि सारा शहर और बहुत से गांव बरबाद हो गये। इसलिये जनता की राय भी लेली जाया करे तो बहुत अच्छा होगा।

पी० डब्लू० डी० के भ्रष्टाचार की बावत मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि ओवरसियर और इंजीनियर्स अपने बंगले के बाहर नहीं निकलते हैं और जनता का गला काटते हैं, तीन महीने की सर्विस में ही, न जाने कहां से सम्पत्ति इनके पास आ जाती है कि मोटर साइकिल ले लेते हैं। पैदल ये चलते नहीं हैं। उनकी तनख्वाह के ऊपर आप ध्यान दें कि कहां

[श्री रघुवीरराम]

से उनकी तनख्वाह में बचत होती है। ये जनता का ही गला तो काटते हैं। और इनकी कोठी पर ठेकेदार तमाम बकरी, बकरे, मुर्गी, मुर्गी के अंडे आदि पहुंचाते हैं जिनको खा-खाकर वे टोडरम ल जैसे हो रहे हैं और पेट फुलाये हुये बैठे रहते हैं। आप पता लगाइये कि ये अपने क्षेत्र में कितने दिन दौरे पर जाते हैं। आज इनके द्वारा जनता के हक का बहुत बड़ा हनन हो रहा है। मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी के सामने यह भी रखना चाहता हूं कि बाढ़-पीड़ित इलाकों में हमने बहुत जगह देखा है कि आपके इंजीनियर्स मनमानी करते हैं। जिस सड़क को या बांध को चाहते हैं, ऊंचा कर देते हैं नीचा कर देते हैं, वे अपने मन से ही सारा काम करते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि एक तरफ अगर सड़क या बांध को ऊंचा कर दिया जाता है तो जहां एक तरफ की जनता की रक्षा होती है वहां दूसरी तरफ की जनता उसकी वजह से तबाह हो जाती है। इस तरह से जहां वे सड़कें और बांध एक तरफ की जनता के लिये रक्षक रूप में होते हैं वही दूसरी तरफ की जनता के लिये भक्षक के रूप में काम करते हैं। मैंने बलिया जिले में देखा है कि टोंस नदी में बाढ़ के जमाने में पानी आता था तो वह ६ मील के एरिया में फैल जाता था लेकिन बिलकुल उसके किनारे ही बांध बनाया गया है। आज आजमगढ़, गाजीपुर जिले की हालत यह है कि वहां के हजारों गांवों की फसलें बर्बाद होती हैं, लेकिन क्या सरकार ने उनकी तरफ कभी ध्यान दिया है? क्या इंजीनियरों ने वहां कोई बांध बन्धवाया है? नहीं। वे मनमानी करते हैं। मान्यवर, आपके द्वारा एक चीज में और कहना चाहता हूं कि जितने नये-नये पुलों का निर्माण हो रहा है, सुनने में आया है कि आप उन पर टोल टैक्स लगाने जा रहे हैं। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि इस टोल टैक्स को न लगाइये वरना इस से जनता का बहुत बड़ा नुक्सान होगा। जितने ही आप नये पुलों और सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और उनको पैदल नहीं चलने देना चाहते हैं, उतना ही उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस टोल टैक्स से होने वाला है। इसलिये आप इस टोल टैक्स लगाने के विचार को समाप्त कीजिये। यह तो बिलकुल वही चीज हुई कि आप इन पुलों और सड़कों के जरिये एक रोजगार करने जा रहे हैं। मान्यवर, इस तरह का रोजगार मंहगा पड़ेगा।

गाजीपुर जिले की पी० डब्लू० डी० की सड़कों के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ के जिले इस सूबे के आखिरी हिस्से में पड़त हैं जिससे गवर्नमेंट का ध्यान उधर नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वे अपनी स्पीच के दौरान में बतलावें कि गाजीपुर जिले में १० वर्ष के अन्दर उन्होंने कितनी सड़कें बनवायी हैं और कितने पुलों का निर्माण करवाया है। आज भी टोंस नदी का पुल जो मऊ के पास है टूटा पड़ा है। आज महमूदाबाद से बलिया जाने वाली सड़क पर मगई नदी पर हाटा काजी पुल टूटा हुआ है उसके बनवाने की अत्यन्त आवश्यकता है लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आज हमारे यहां सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि अगर कोई खाना खाकर स्टेशन पर जाना चाहे तो उसके रास्ते इतने ऊंचे नीचे हैं कि मोटर पर जाने पर उसका खाना स्टेशन पहुंचते पहुंचते हजम हो जाता है।

एक सदस्य—यह तो अच्छा ही है।

श्री रघुवीरराम—अच्छा तो जरूर है लेकिन कितने लोगों को इससे टी० बी० भी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री सुल्तान आलम खां—डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि मुझे भी पी० डब्लू० डी० के बजट पर कुछ बातें कहने का मौका मिला। मैं सबसे पहले उस ग्रांट की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताईद करता हूं जो माननीय मंत्री की जानिब से पेश हुई है और उस कटमोशन की मुखालफत करता हूं जो उधर के मेरे दोस्तों ने पेश किया है। मैं कोई इस डिपार्टमेंट की तारीफ तो करना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बातें अभी इस हाउस के अन्दर कही गयी हैं, उन बातों में बहुत एग्जेजरेशन से काम लिया गया है। कुछ दोस्तों ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को पब्लिक वेस्टेज डिपार्टमेंट कहा, कुछ दोस्तों ने ट्यूबवैल्स की मरम्मत और उनके निर्माण के मुताल्लिक सारी जिम्मेदारी मंत्री महोदय के सिर पर डाल दी, कुछ ने जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक जो बातें थीं वह भी इसी महकमें के सिर पर डाल दीं, यह बात जरा चेरिटेबिल नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि जो कुछ यह डिपार्टमेंट कर रहा है वह बिलकुल सही है, उसके मुताल्लिक मुझे भी शिकायतें हैं और मैं समझता हूं कि वह ऐसी हैं कि जिन पर इस महकमें को खास गौर करना चाहिये।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा कि हमारे यहां पी० डब्लू० डी० में खराबियां हैं और उनकी जो शिकायत की जाती है उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वह यह कि उसमें पब्लिक ओपीनियन ज्यादा असोशियेट नहीं की जाती। अभी हाल ही में एक पब्लिक वर्क्स ऐडवाइजरी कमेटी बनवायी गई है और लेजिस्लेचर के मेम्बर्स ही उसके मेम्बर्स और चेयरमैन हैं लेकिन उसका काम सिवाय इसके कुछ नहीं है कि ३–४ मास बाद एक मीटिंग कर ली और अपनी कुछ राय और मशविरा दे दिया लेकिन उस मशविरे की क्या वकत है और उसका क्या असर लिया जाता है? वह सब नहीं के बराबर है। अगर हमें इन दिक्कतों और दुश्वारियों को रफा करना है तो हमें इस महकमें को पूरे तौर से डिसेन्ट्रेलाइज करना चाहिये और जैसा कि मुतालबा किया जाता है कि उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न की एक झलक आये तो उसके लिये जरूरत इस बात की है कि इसमें पब्लिक ओपीनियन को ज्यादा से ज्यादा असोशियेट किया जाय और यह तभी हो सकता है कि इन ऐडवाइजरी कमेटीज को काफी अख्तयारात दिय जांय।

एक दूसरा सुझाव जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां यह शिकायत रहती है कि जो रुपया किसी काम के लिये मंजूर होता है वह वक्त पर खर्च नहीं होता है और रेड-टेपिज्म की वजह से, रूल्स इतने टाइट हैं कि फाइलें आगे नहीं बढ़ पातीं जिस से बड़ी दिक्कत होती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो रुपया है वह कहीं अक्तूबर, नवम्बर तक यहां आता है, उसका अकाउन्टिंग होता है, उसके बाद ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होते-होते ३१ मार्च आजाती है और वह लैप्स हो जाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का रुपया जो आज हमें दिया गया है वह कल किसी और सूबे की जरूरत के मुताबिक दूसरों को दिया जा सकता है और इस तरह से सूबे का नुकसान होजाता है। इस मुताल्लिक मुझे भी जातीतौर पर इसका एक तल्ख तजुर्बा हुआ है और मैं अगर अपनी एक लोकल जरूरत की बात भी बता दूं तो बेजा न होगा। हमारे यहां फर्रुखाबाद जिले में एक सड़क है कायमगंज फर्रुखाबाद रोड जिसके बारे में मैं क्लेम कर सकता हूं कि उसके बराबर सूबे में बदतरीन सड़क और कोई नहीं है और मेरा यह दावा अब तक कायम है। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि और उस से भी बुरी हैं लेकिन मैं इतना तो फिर भी कहूंगा कि यह सड़क अगर सबसे बुरी नहीं है तो उन बुरी सड़कों में से एक जरूर है। इस सम्बन्ध में २ लाख रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से मंजूर हुआ था। वह रुपया दिसम्बर में आया और जनवरी तक इत्तला पहुंची और फरवरी मार्च तक उसमें से ८–९ हजार रुपया खर्च हो पाया और बाकी लैप्स हो गया और उसके बाद वहां से कोई सहायता नहीं मिल सकी। उसके बाद मैंने कई बार तवज्जह दिलाई,

[श्री सुल्तान आलम खां]

माननीय मंत्री जी की भी तवज्जह दिलाई, खुद भी लिखा, रिप्रेजेन्टेशन भी भेजा, अब कुछ काम इधर हो रहा है लेकिन फिर भी मैं मतालबा करूंगा कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह करे । मैं दावत दूंगा अपने माननीय मंत्री जी को यह उनके महकमे के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को और मैं बड़ा खुश होऊंगा कि महकमे के चीफ इंजीनियर और अफसर आला खुद जाकर देखें तो उनको अन्दाजा हो जायगा । इस सड़क के दुरुस्त होने में बड़ी देर हुई है और उसके लिये मैं ऐसे-ऐसे गवाह पेश कर सकता हूं जिनके मुताल्लिक कोई शक नहीं हो सकता जैसे पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, डाक्टर सम्पूर्णानन्द और हमारे होम मिनिस्टर साहब खुद गवाह हैं । मुझे पन्त जी के वह शब्द याद हैं । उन्होंने कहा था कि your road is in a most disgraceful condition.

श्री उपाध्यक्ष—वह लोग सही सलामत वापस आगये थे लौट के ?

श्री सुल्तान आलम खां—खुदा का शुक्र है कि वह लोग चले आये । मैं तो डरता था कि कहीं रास्ते में मोटर फेल न हो जाय । बहरहाल, मैं इस मामले को यहीं छोड़ता हूं । मुझे उम्मीद है कि इसके मुताल्लिक कार्यवाही की जायगी ।

एक सुझाव और पेश करना चाहता हूं । हमारे यहां इन कामों के लिये जो रुपया दिया जाता है वह वक्त के अन्दर ३१ मार्च तक अगर सर्फ नहीं हुआ तो फिर जो बाकी होगा वह रकम दुबारा लेजिस्लेचर के सामने आयेगी । दुबारा हम उसे मंजूर करें, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकले और इस तरह उसमें छः महीने की देरी हो जाती है । काम में इन्टरवल पैदा हो जाता है । तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिये कोई ब्लाक ग्रांट सिस्टम ईजाद किया जाय जिससे कि यह दुश्वारियां हल हो सकें । इस विषय पर सन् ४७ में एक कमेटी बैठी थी, मौजूदा माननीय मुख्य मंत्री जी जिसके सदर थे । मुझे भी उसमें काम करने का मौका मिला । उसने बड़े जोर से यह सिफारिश की थी कि हमें ब्लाक ग्रांट का सिस्टम अपने यहां ईजाद करना चाहिये ताकि उस से हमें अपने काम में सहूलियत हो और हमारी सड़कों की दशा बेहतर हो सके ।

जनाबआला, इसके साथ-साथ मैं एक चीज और भी अर्ज करूंगा स्टार ऐंड ग्रिड सिस्टम के मुताल्लिक । आजकल हमारा जो सड़कों को बनाने का प्रोग्राम है वह पंचवर्षीय योजना के मातहत है । स्टार ऐंड ग्रिड फारमूला के मातहात जो प्लान तैयार किया गया था वह बहुत पुराना हो गया । आजकल जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है कि साल भर के लिये किसी चीज को अगर हम रख दें तो फिर वह इस काबिल नहीं रहती कि उस पर अमल किया जाय । यह फारमूला जिस वक्त बनाया गया था उस वक्त प्लानिंग का काम नहीं था । इस वक्त प्लानिंग का काम हमारे यहां चल रहा है । इसमें और उसमें एक फर्क यह है कि वह बिलकुल आफिसर्स का बनाया हुआ था और आज हम पिपुल्स प्लान चाहते हैं । कोई चीज ऊपर से इम्पोज करना नहीं चाहते हैं । उसके लिये पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा की जाय, ऐडवाइजरी कमेटीज से राय ली जाय ताकि हम एक प्लान ऐसा बना सकें जो वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके ।

जनाबआला, मैं एक चीज इस सिलसिले में और अर्ज करूंगा । हमारे बजट में कुछ रुपया, जो हिस्टारिकल और कल्चरल साइट्स हैं, ऐसे मुकामात को डेवलप करने के लिये भी रखा गया है । मैं दरख्वात करूंगा कि प्लान तो पांच साल का बन गया है लेकिन जो रुपया इसके अन्दर रखा गया है उसके मातहत इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि जो खास-खास साइट्स हैं जो हिस्टारिकल इम्पार्टेंस रखते हैं, उनमें हमें सड़कों को जरूर पहुंचा देना चाहिये । मैं समझता हूं कि मैंने जो तजवीजें हाउस के सामने रखी हैं गवर्नमेंट उनके ऊपर गौर करेगी और मैं तो यह मतालबा कर रहा हूं कि आज वक्त आगया है एक कमेटी बिठालने का । जो कमेटी माननीय मुख्य मंत्री जी की सदारत में बैठी थी उसकी रिपोर्ट को उस कमेटी में दें और-और बातों के अलावा वह कमेटी इस बात की भी कोशिश करे कि ठेकेदारों के मामले में किस

तरह से सुधार किया जा सकता है। ठेकेदारों की जो सबसे बड़ी शिकायत है वह यह है कि उनके पेमेन्ट बहुत देर से होते हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी यह शिकायत कहां तक जायज है। हो सकता है कभी-कभी सही हो और कभी गलत भी हो। लेकिन बहरहाल इसकी तरफ तवज्जह करनी है। वह इस सूरत से हो सकती है कि एक एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें कुछ लेजिस्लेचर के मेम्बर शामिल हों और इस मुकदमे के स्पेशलिस्ट्स बठें और सोचें कि किस तरीक से ब्लाक ग्राण्ट सिस्टम आ सकता ह। हमारी जो रूल्स की दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है! इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक कि हमारी सड़कों का ताल्लुक है खासतौर पर यह हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का इंडेक्स है। अगर सड़कें अच्छी नहीं है तो इसमें मोबिलिटी नहीं हो सकती है, हमारी प्लान भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती ह। तो मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी एक कमेटी बैठायें और उसके सामने यह तमाम चीजें रखी जायं ताकि वह मश्विरा दे सके और उसके मुताबिक काम हो सके। रूल्स के जरिये से, रूल्स की तजवीज के जरिये से इस किस्म का इंतजाम कर सके कि जिससे आसानी से काम हो सके।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रान्ट पर जब मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उनकी वक्तृता को बड़े गौर के साथ सुन रहा था। उन्होंने सड़कों के बारे में एक उपमा दी, वह मुझे सुन्दर मालूम पड़ी। उन्होंने नसों से इसकी उपमा दी कि जैसे शरीर में नसें होती हैं इसी प्रकार से सड़कों का होना राज्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। बहुत सही उन्होंने कहा। मगर श्रीमन्, नसें दो प्रकार की होती हैं। एक तो मोटी वाली को धमनियां कहा जाता है, दूसरी को केसिका कहा जाता है जो पतली होती हैं। मगर अफसोस यह है कि हमारी सरकार केवल उन्हीं मोटी धमनियों पर ही ध्यान दे रही है केसिकाओं को बिलकुल छोड़ दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल––वह तो डिस्ट्रक्ट बोर्ड और पंचायतों के अधीन हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह––डिस्ट्रक्ट बोर्ड और पंचायतों के बारे में पहले ही अर्ज किया जा चुका ह कि यह केवल नाम मात्र की संस्थायें हैं उनसे कोई काम नहीं होता। आपने मोटी धमनियों की तरफ ही ध्यान दिया तो उसका नतीजा यह हुआ कि ब्लड प्रेशर हो जायगा और पतली धमनियां खत्म हो गईं। बड़ी-बड़ी सड़कों के लिये आपने कहा कि हाई वेज बनाये जा रहे हैं, पिच किये जायेंगे, कुछ सीमेंट की भी बनेंगी, कंकर वाली नहीं रहेंगी, उन पर रुपया ज्यादा खर्च होगा तो उनके बनाने का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय यह है कि जिसमें मोटरें तेज रफ्तार से चल सकें। मंत्री जी ने अपनी स्पीच में यह भी कहा था। मगर तेज चलने वाली मोटरें हैं किसके पास? या तो वह मंत्रियों के पास हैं या जो फारेनर्स आते हैं उनके पास हैं।

श्री गिरधारीलाल––आपके पास भी हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह––हमारे पास हुआ करती थीं। अब तो टुटही शेवरलेट है एक। तो तेज चलने वाली मोटरों के लिये सड़कें जो बन रही हैं वह आपके लिये बन रही हैं। हम तो अब बैलगाड़ी पर चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं। हमें उनके लिये सड़कों की जरूरत है, पिच की जरूरत नहीं है। ८०–९० मील की स्पीड से चलने वाली क्राइसलर, डॉज, प्लीमथ, स्टुडबेकर, हम्बर वगैरह यह मोटरें हैं, जो यहां बाहर खड़ी हुई देखने को मिलती हैं वही गाड़ियां इतनी तेज जा सकती हैं। जो मोटरें मध्यम श्रेणी के आदमियों के पास हैं

[कुंवर श्रीपालसिंह]

उनके लिये पहले ही सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है । जैसे फियेट, हिन्दुस्तान, स्टैन्डर्ड यह मोटरें चाहे जिस पर चलें लेकिन इनको ३०,४० मील के ऊपर ले जाइये तो जान का खतरा है, इनके लिये जैसी सीमेंट वाली सड़क वैसी ही कंकड़ वाली । रहा यह कि जो विदेशी आते हैं और जिनको दिखाने के लिये ही हमारे यहां हर काम किया जाता ह और कहा जाता है मुल्क बड़ी उन्नति कर रहा है, केवल विदेशियों को दिखलाने के लिये ।

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां पीठासीन हुए ।).

बिजली के लिये कहा गया । ये बिजली के खम्भे इसलिये लगाये गये और सड़कें अच्छी इसलिये बनायी गयीं जिससे फारेनर्स आ कर देख सकें । असलियत में तो गांवों की सड़कों की जरूरत है । वे सड़कें गांवों में बनाई जातीं जिन पर ईख के मौसम में ईख लाद कर किसान ले जा सकते और गल्ले के मौसम में गल्ला ले जाकर बाजारों में बेच सकते । लेकिन उस पर कतई ध्यान नहीं दिया गया और यह कह कर टाल दिया गया कि इनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर छोड़ दिया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत क्या है यह सभी को विदित है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उन सड़कों को कागज पर दिखला देते हैं कि इनकी मरम्मत हो चुकी है लेकिन वास्तव में एक झलिया मिट्टी भी उन पर नहीं पड़ती । कहने को तो सड़क होती है लेकिन बनी हुई हैं नालियां । बरसात के महीनों में उनमें पानी बहता है और बहुत सी सड़कें तो ऐसी मिलेंगी जिन पर नावों पर जाया जा सकता है । यह हालत है गांव की सड़कों की ।

आम तौर से यह रवैया अपनाया गया है- --चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों--कि गवर्नमेन्ट के मुलाजिमों की शिकायत जरूर की जाती है । उनके लिये जरूर कहा जाता है कि उनमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है । लेकिन जितना कहा जाता है उतना नहीं है । असल में गवर्नमेन्ट की पालिसी जहां निर्धारित होती है वहां गलती होती है । उस गलती के नतीजे जब सामने आते हैं तो लोग सोचते हैं कि गलती हो कहां रही है । तो बेचारा आफिसर सामने आता है और उसी पर लाद दिया जाता है कि उसी की गलती है । जब गवर्नमेन्ट पहले ही तय कर लेती है कि हम खाली हाईवेज देखेंगे तो गांवों में वह रुपया पहुंच ही नहीं सकता । गांवों से आये हुये लोग यही कहेंगे कि शहरों के लिये यह सारे काम हो रहे हैं । तो गवर्नमेन्ट को चाहिये कि वह खाली दिखावा न करे बल्कि अन्दर से ठोस बनाने की कोशिश करे और इसके लिये गांवों की सड़कों को पक्का करने की जरूरत है ।

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि जो बहुत ही इम्पार्टेन्ट सड़कें गांव की हैं उन पर भी सरकार की नजर नहीं पड़ती । मैं अपने जिले की एक सड़क बतलाना चाहता हूं जो तीन जिलों को जोड़ती है । इलाहाबाद, जौनपुर और फैजाबाद, इन तीन जिलों को जोड़ती है । बादशाहपुर से शुरू होती है और बिलवाई पर जा कर खत्म होती है । वहीं से फैजाबाद शुरू हो जाता है । श्रीमन्, अगर इस सड़क को पक्का कर दिया जाय तो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, तक से इलाहाबाद के लिये ट्रैफिक कनेक्टेड हो जाता है । उसमें खाली एक जिले की तीन तहसीलें पड़ जाती हैं और इतनी इम्पार्टेन्ट सड़क होते हुये भी देखा जाय तो उसमें ऐसे-ऐसे गड्ढे और नालियां हैं जिससे शायद साइकिल चलाना भी मुश्किल है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बैलगाड़ी या ट्रक की वजह से सीमेंटेड बनाने की जरूरत है तो थोड़े दिनों के लिये सीमेंट पर से ध्यान हटा दिया जाय, और उसी रुपये से इन कच्ची सड़कों को इस काबिल बना दिया जाय कि मोटर न सही, ट्रक न सही लोग कम से कम साइकिल पर तो चल सकें, इस काबिल ये सड़कें हो जाय । गांवों के अन्दर पहले थोड़ा हो जाय, फिर सीमेंट की सड़क बनाइये, चाहे सोने की ढलवा दीजिये । आप तो राजा हैं ही, चाहे कुछ कीजिये । लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले गांवों की तरफ ध्यान दें । अगर हाईवेज की तरफ ही ध्यान

बैंगे तो छोटी धमनियों में अधिक रक्त का संचार हो जायगा और केशियायें फट जायंगी और लकवे का रोग हो जायगा और तब हम लोगों को ही इस राज्य की लाश भी ढोनी पड़ जायगी।

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मन्त्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करती हूं और इसके बाद मैं यह कहूंगी कि मेरे जिले में सड़कों की जो समस्या है उस सम्बन्ध में दस सालों से कुछ हो नहीं पाया है और जो कुछ हो पाया है वह श्रमदान से हुआ है। मेरा तो मंत्री जी से यह कहना है कि हमारे यहां पुलों की भी बड़ी समस्या है। मोटर के पुल के लिये हमें पता लगा था कि आपने दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा था कि वह बनाया जायगा लेकिन अब जो हमने देखा है तो कहीं उसका पता नहीं है। तो हमारा माननीय मंत्री जी से यह नम्र निवेदन है कि हमारे यहां की जो सबसे बड़ी समस्या है वह टिहरी भागीरथी नदी के ऊपर मोटर के पुल की है। आपके पास हम वैसे भी आये थे और आपने कहा कि लोहे की कमी है, इस कारण से पुल बनाया नहीं जा सकता है और कीर्तिनगर का जो पुल बना है, वह हम मानते हैं कि वह पुल बड़ा अच्छा बना है और उससे हमें बड़ी सुविधा है, लेकिन जो आश्वासन टिहरी पुल का दिया था वह भी तो पूरा होना ही चाहिये। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगी कि जिला टेहरी गढ़वाल सब चीजों में पिछड़ा हुआ है और सभी चीजों की वहां कमी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य चीज है वह सड़क है। वैसे तो सड़क हर एक जगह के लिये मुख्य है, क्योंकि जब तक सड़कें नहीं होंगी तब तक आयात-निर्यात कैसे हो सकेगा? हमारे जिले में लोग बड़ी मुश्किल से आलू पैदा करते हैं और जब इधर आने के लिये "बेचने के लिये" लाना चाहते हैं तो मोटर सड़क की सुविधा नहीं है। इसीलिये उनको क्षति उठानी पड़ती है, आलू सारे के सारे गल जाते हैं। तो मेरा तो यह कहना है कि वहां के लिये सड़कों की तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान दें। आपको धन्यवाद देती हूं कि मैंने पहले बजट में (१९५६-५७ का बजट भी देखा है), उसमें हमारे टेहरी गढ़वाल का कहीं भी कोई मद का अनुदान नहीं था, लेकिन इस साल मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस साल हमारे मंत्री महोदय ने पी०डब्लू०डी० से बहुत अच्छा अनुदान रखा गया है। और इस अनुदान के अनुसार हमारे यहां काम होगा तो मैं आपकी आभारी रहूंगी।

मैं यहां पर कोई व्याख्यान देने के लिये नहीं खड़ी हुई हूं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि हमारे यहां टेहरी गढ़वाल में देवप्रयाग क्षेत्र में और उत्तर काशी में सड़कों की समस्या मुख्य है। और आयात-निर्यात के ये साधन उपलब्ध हो जायेंगे तो आलू आदि चीजें भी इधर आ सकेंगी और वहां उन्नति भी हो सकेगी। इस १९५८-५९ के बजट में जो हमारी सड़कों के निर्माण और समाज कल्याण के लिये प्रोजेक्ट वगैरह रखे गये हैं, जिस प्रकार उनको दिखाया गया है, यदि उसी प्रकार से उनके अनसार कार्य होगा तो हमको उसमें संतुष्टि होगी और हमारी जनता को उससे खुशी होगी।

हमारे यहां पानी की समस्या भी बड़ी मुख्य है और उसका हल भी तभी हो सकता है जब हमारी रोड अच्छी बनेंगी। तो ज्यादा न कह कर मैं केवल इतना कहूंगी कि हमारा टेहरी जिला वैसे तो हर चीज के लिये पिछड़ा हुआ है, उसका उत्थान कराना आप ही लोगों के हाथ में है और तभी उसका उत्थान हो सकता है कि आप अपनी ओर से कोई कोर, कसर बाकी न रखें वहां के लिये, वहां के मनुष्यों के लिये। वहां की भुखमरी की समस्या भी तभी हल हो सकती है जब आप उस ओर विशेष रूप से निगाह रखेंगे। श्रीमान् मंत्री जी, समय-समय

[श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन]

पर जाकर जनता को उत्साहित करिये और जो कार्य करते हैं उनके उत्साह को बढ़ाइये तभी वहां के लोग आगे बढ़ सकेंगे क्योंकि वहां के लोगों को अभी तक इतना भी मालूम नहीं है कि उन लोगों को क्या करना है और किस कार्य के करने में उनकी भलाई है। यह सब प्रकाश आप ही लोग वहां जा कर दिला सकते हैं।

अन्त में, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने आज यहां प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं और इस बात के लिये धन्यवाद देती हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में (सन् १९५८-५९ के बजट में) वहां के सार्वजनिक कार्यों के लिये जो अनुदान रखा गया है, अगर उसके अनुसार सरकार कार्य करेगी तो वहां की जनता का बड़ा भला होगा और उन्हें बहुत सुविधा होगी। अन्त में मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान के बारे में सब से पहले तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम लोग कुछ विरोध करने के लिये खड़े होते हैं और जब हमारी नजर उधर जाती है तो जितने मंत्री महोदय होते हैं सब की नाक और भौंहें कुछ सिकुड़ी सी मालूम होने लगती हैं। मगर हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिये, उन्हें हमारा मशकूर होना चाहिये, क्योंकि जब हम उनका विरोध करते हैं तो वह विरोध नहीं होता है बल्कि ऐसा समझिये कि जो कुछ भी ये गन्दगी इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम अपनी छाती पर ले कर के छननी की तरह फिल्टर करके, छान करके उनको बतलाते हैं और जो ये पांच विरोधी दल हैं उनके पांच फिल्टरों से छन कर वह चीज आगे बढ़ती है। कहने की बात यह है कि अभी हमारे मंत्री महोदय ने बहुत से पुलों का जिक्र किया, बहुत सी सड़कों का जिक्र किया और जब मैंने अनुदान संख्या ४७ को पढ़ा तो उसमें एक बड़ी लम्बी फेहरिस्त भी मुझको मिली जिसमें यह दिखाई पड़ा कि कुछ ऐसे भी पुल हैं जिनके लिये बहुत लम्बी-लम्बी रकमें इस अनुदान में रखी गयी हैं और उनकी बड़ी तारीफ की गयी है। किसी पुल के लिये १,८०,००० रुपये का अनुदान है, किसी पुल के लिये ४५,००० रुपये का अनुदान है, बहुत से पुलों का जिक्र इसमें है। मेरा खयाल है फिर भी हमारे मंत्री महोदय एक पुल भूल गये। उन्हें एक तारीफ का पुल इस सदन में भी बनवाना चाहिये था, उस तारीफ वाले पुल के लिये भी कुछ अनुदान रखने की आवश्यकता थी। तो वह मिस कर गये। इसमें छोटे से छोटे, १० फीट से लेकर मील भर तक लम्बे पुल बनवाने की योजना है, मगर हमारा भी एक बहुत छोटा सा जिला खीरी है उसकी एक तहसील १२८ मील लम्बी है, उसमें १२८ मील लम्बी शारदा नदी पर एक भी पुल आपने नहीं बनवाया। सेंट्रल गवर्नमेन्ट के रेलवे डिपार्टमेन्ट ने किसी जमाने में उस पर एक पुल बनवाया था। उसके अलावा कोई दूसरा पुल उस पर आज तक नहीं बना। जिस पुल का जिक्र इसमें आया है वह रेलवे पुल के साथ-साथ आदमियों और गाड़ियों के निकलने के लिये रखा गया था। उसका आजतक पता नहीं है कि वह कब बनेगा और बनेगा भी या नहीं। न मालूम कब मुंह फैलाया और कब डकार आयी।

एक सदस्य---इसी सूबे में है ?

श्री शिवप्रसाद नागर---आप नक्शा देख लीजिये।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, बातचीत तो वे कर रहे हैं, मैं नहीं।

श्री अधिष्ठाता---आप मेरी तरफ देखते रहें।

श्री शिवप्रसाद नागर---बहुत अच्छा । तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अभी दोनों तरफ के सदस्य बोले, इधर के भी और उधर के भी । उन्होंने भी वही बात कही और हमने भी वही बात कही । अभी एक सदस्य इसी सामने वाले माइक्रोफोन पर बोल रहे थे, हमारे माननीय सुल्तान आलम खां साहब, और वे यह कह रहे थे कि एक ऐसी सड़क थी जिसके ऊपर से मोटर गुजरी तो हार्ट फेल हो जाने का डर था और बड़े-बड़े नेता उस पर से गुजरे और आपने गवाह भी पेश किये और बड़े बड़े आदमी गवाह पेश किये । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जहां सुल्तान आलम खां साहब ने यह कहा है कि इस सड़क के बारे में सरकार ने नेगलेक्ट किया है और एक और सदस्य ने भी यही कहा था, श्रीमन् १९२९-३० का जमाना था । हम लोग जमींदारी नाश होने का नारा लगाते हुये निकले एक ताल्लुकेदार के दरवाजे से तो उनके यहां कुछ तमाशा हो रहा था और तवायफ गा रही थी कि "बात दोनों एक ही हैं हम कहें या तुम कहो" उधर से जो बात कहते हैं कि यह खराबी है, वह खराबी है, उन्होंने अपने जिले की बात कही और हमारे सुल्तान आलम खां साहब ने भी वही बात कही और बंशीधर जी ने भी वही बात कही, मगर सिर्फ कहने में कुछ तब्दीली हो जाती है । हम लोग कटमोशन लाते हैं और वह उसका विरोध करते हैं लेकिन वह भी वही कहते हैं जो हम कहते हैं ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं इसमें.....

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मैं शंका समाधान करना चाहता हूं कि तवायफ कौन हुई ?

श्री अधिष्ठाता---वह तो उन्होंने नजीर दी है, तकरीर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, सामान्य प्रशासन में एक ग्रान्ट नम्बर ४७/२३ है जिसमें १,२१,१०० रुपये का अनुदान है जो विधान भवन के किसी निर्माण कार्य के लिये रखा गया था । लेकिन उसका पता नहीं है कि वह कौन सा कार्य था । इतना पता जरूर लगता है कि उसमें से कुछ रुपया एडवांस जरूर दिया जा चुका है और जो काम दिया गया था उसमें ठेकेदार से १५,००० रुपये की सिक्योरिटी जमा कराई गई । लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और ९३,००० रुपये का एडवांस ठेकेदार को दे दिया गया । लेकिन यह नहीं मालूम कि इस रकम से दिया गया है या अलग से दिया गया है । पिछले अनुदान में से दिया गया है या अगले अनुदान में से दिया गया है । मगर पता नहीं है कि ठेकेदार कहां है ? क्या काम होगा और कब वह शुरू करेगा ? ऐसा मालूम हुआ है कि उसने और भी सरकारों से इसी तरह के सरकारी एडवांस ले रखे हैं । पता नहीं वहां भी काम शुरू किया या नहीं । इस काम के लिये एडवांस लिये हुये एक साल हो गया है । लेकिन उसका पता नहीं कि वह वहां है । ऐसा तो नहीं है कि नटवर लाल जी की तरह से कोई ठेकेदार हो और जिसने लाख दो लाख रुपया इसी तरह और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले रखा होगा । पता नहीं वह कहां है ? अगर ऐसे ऐसे ठेकेदारों को काम दिया जायगा तब तो आपका निर्माण कार्य हो चुका । वह कभी पूरा नहीं हो सकेगा ।

एक बात और कह देना चाहता हूं कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि छोटे-छोटे कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं और उन्हीं पर इल्जाम लगाये जाते हैं । मैं कहता हूं कि यह गलत है । शायद वह उल्टा कह गये हैं । मैं कहता हूं कि छोटे कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं, सब

[श्री शिवप्रसाद नागर]
बड़े कर्मचारी ही भ्रष्टाचार किया करते हैं। वह जितनी लम्बी रकम लेते हैं, उतना ही बड़ा उनका मुंह और पेट होता है।

एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जहां यह कहा गया है कि धन की कमी की वजह से निर्माण कार्य शिथिल है, इसी लिये फलां जगह नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन हम यह कहते हैं कि इससे पहले जब अंग्रेजी सरकार थी और हमें चार्ज दिया तो उस समय २७ करोड़ की आमदनी थी। लेकिन अब ९७ करोड़ की आमदनी है। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहां की आमदनी बढ़ती गई हमारे निर्माण कार्य पिछड़ते गये। जैसे कि शुक्ल जी ने कहा कि जो काम अंग्रेज कर गये थे और जैसा वह बना गये थे वही हम नहीं कर पाते हैं। नई नई चीजें आती हैं। एक पुल के लिये जब एस्टीमेट मांगा गया तो कहा गया कि ४५ लाख रुपया लगेगा। लेकिन जब ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर ने बनवाया तो १८,००० रुपये में ही बन गया। श्रीमन्, हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई एस्टीमेट आ रहा है और आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कम से कम इतना तो करें कि किसी फारेन कंट्री के इंजीनियर से उसे रिवाइज करा लें। और यह तो मालूम करें कि यह जो २ १/२ आने की चीज बनी जिसको ओवरसियर और इंजीनियर २ १/२ का बता रहे हैं यह वाकई उतने की है या नहीं। यह किसी फारेन इंजीनियर से मालूम करिये कि वाकई यह चीज २, १/२ आने २ १/२ हजार या २ १/२ लाख की बनी है या नहीं। मगर मैं कुछ ठेकों के सम्बन्ध में यह बताता हूं और हमारे पास इसके सम्बन्ध में सबूत भी हैं कि जहां पर १०० रुपये किसी काम में लगने हैं तो उसके लिये १ हजार रुपया निर्माण के लिये मांगा जाता है और वह काम जो १०० रुपये में होना था वह अन्त में ५० रुपये का काम ही रह जाता है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, इस अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव रखते हुये लहरी साहब ने जो भाषण दिया था उसको सुनकर मुझे बचपन की बात याद आई जब कि मैंने संस्कृत की एक कहावत पढ़ी थी। उन्होंने यह कहा कि मीलों के फलांग लगाने पर सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। तो बचपन में मैंने एक वैद्य की बात सुनी थी और वह यह कि वैद्य ने एक लड़के से पूछा कि हरड़ कितनी बड़ी होती है। उस लड़के ने कहा कि हरड़ १० हाथ लम्बी होती है। "मुखमस्तीति वक्तव्यम् दशहस्ता हरीतकी"। इसके बाद आपने करोड़ों रुपये की बात कह दी लेकिन चलते-चलते अन्त में उन्होंने यह कह दिया कि करोड़ों नहीं लाखों उसमें खर्च हुआ। मुझे आश्चर्य यह मालूम होता है कि विरोधी दल के लोग आपस में जो बात कहते हैं वह एक दूसरे की विरोधी बात कहते हैं। लहरी जी ने यह कहा कि अब पुलों की जरूरत नहीं है, सड़कों की जरूरत है। शुक्ल जी ने कहा कि सड़कों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पुलों की जरूरत है। हमारी सरकार यह समझती है कि सड़कों और पुलों दोनों की जरूरत है। इसीलिये आज के अनुदान में सड़कें भी रखी गई हैं और पुल भी रखे गये हैं क्योंकि यह दोनों जरूरी हैं। सड़कों के बनाने में खर्चा थोड़ा होता है इसलिये उसके लिये रकम थोड़ी रखनी पड़ती है। पुलों के बनाने में रकम ज्यादा खर्च होती है इसलिए पुलों के लिये रकम ज्यादा हो जाती है। अगर लहरी जी को यह सन्देह है कि आगरा में यमुना पर जो पुल है वह पुल वहां नहीं होना चाहिये तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आगरा के उस पुल को वहां से उठाकर गंगा पर ले आयें। यमुना नदी पर और भी कई पुल हैं। दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में और कई जगह पुल हैं लेकिन गंगा पर कानपुर से ऊपर कोई पुल नहीं है। एक पुल बनाने की योजना कुछ वर्षों से है जो गढ़मुक्तेश्वर में बनेगा लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक वह पुल नहीं बना है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि यदि आगरे के पुल को आगरे वाले बेकार समझते हों तो उसको वहां से उठाकर गंगा पर ले आयें और मैं उनको यह योजना दूंगा कि सहारनपुर, देहरादून, गढ़वाल, टिहरी और बिजनौर को मिलाने के लिये हरद्वार में उस पुल को बना दें। अगर यह पुल हरद्वार में बनेगा तो गढ़वाल, बिजनौर और कई जिलों की जंगल की सामग्री ६०, ७० लाख रुपयों की जो अभी भी हरद्वार के स्टेशन पर आती है, उस पुल के बन जाने से वह सुभीते से आयेगी।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसी पंचवर्षीय योजना में एक सड़क रखी हुई है जो हरद्वार से लक्सर तक की है लेकिन शायद उनको पता नहीं कि उनके विभाग ने अपनी ओर से उसको काट दिया है । वह सड़क ज्वालापुर या हरद्वार से शुरू न करके फेरुपुर से लक्सर तक की बन रही है । मैं नहीं समझता कि जिस उद्देश्य के लिये यह सड़क बनाई जा रही है कि यात्रियों को रेलगाड़ी से यात्रा न करनी पड़े और वे सुविधापूर्वक इस सड़क से हरद्वार आ जांय तो इस सड़क से कैसे सुविधा उनको हासिल हो सकती है ? जब यह सड़क पूरी बनेगी नहीं तो फिर उसका क्या फायदा हो सकता है । इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह अपने विभाग से यह कहें कि फेरुपुर से लक्सर तक इस सड़क को बनाते समय ज्वालापुर को भी इस सड़क से जोड़ दें क्यों कि ज्वालापुर उस सड़क से ४ मील के फासले पर ही है ।

इसी प्रसंग में माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं और अपनी बहन जी के विचारों से सहमत हूं कि जब तक हिमालय के उन सारे रास्तों को, जो दुर्गम हैं, उनको सड़कों द्वारा नहीं मिलाया जाता है तब तक न तो हम हिमालय की बनस्पतियों का लाभ उठा सकते हैं और न ही उन तीर्थ-यात्रियों को सुविधा दे सकते हैं जो लाखों की संख्या में वहां आते जाते हैं और न सीमान्त की ही रक्षा कर सकते हैं । इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि जो सड़क उन्होंने हरद्वार ऋषिकेश से घरासू तक बनाई है उसको उत्तर काशी तक ले जाकर गंगोत्री तक ले जाया जाय और उसकी दूसरी शाख जमुनोत्री तक अवश्य ले जाई जाय । इससे यह होगा कि टेहरी के कुछ लोग जो टेहरी के आसपास या टहरी के पच्छिम क इलाके में रहत ह वहां पर ध्यान दिया जा सकता है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि एक सड़क जो बहुत आवश्यक है वह चकराता से बन और जमुनोत्री तक उस सड़क को ले जाया जाय जिससे जमुनोत्री और चकराता को मिलाया जा सके । इससे यह लाभ होगा कि टेहरी के उस हिस्से में जहां पर आदिम जातियां रहती हैं वहां तक आवागमन की सुविधा हो सकेगी । एक बात मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं । मेरा निर्वाचन क्षेत्र रुड़की नाम से मशहूर है । नाम से ऐसा लगता है कि वह बड़ा शहर है, यूनिवर्सिटी टाउन है लेकिन उस सारे क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है कि जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से निकल सके । रुड़की शहर से लेकर शिवालिक की पहाड़ी के बीच के हिस्से तक कोई सड़क नहीं है और उसका कारण यह है कि वहीं पर एक नदी है सैलानी जो कि बरसात में चलती है और उस पर कोई पुल नहीं है । उस इलाके की आबादी दो, ढाई लाख है जिसमें साल में ६ महीने तक कोई आवागमन नहीं होता । तो मैं चाहूंगा कि उस नदी पर कोई ऐसा पुल बनाया जाय जिससे वहां आने जाने की सुविधा हो सके ।

इसके अलावा जब हम सड़कें बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उन के बनाने में जितना खर्च होना चाहिए उससे अधिक न हो । मैं समझता हूं कि सड़कों के निर्माण में आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाता है । माननीय मंत्री जी बिजनौर के रहने वाले हैं और देहरादून से उनका संबंध है और इसलिये उनको इन दोनों जिलों के बीच स्थित जिला सहारनपुर की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । वह पहले सहारनपुर ही से इस असेम्बली के सदस्य थे और उनका निर्वाचन क्षेत्र हरद्वार के करीब पड़ता है । मैं उनका ध्यान हरद्वार से नजीबाबाद वाली सड़क की ओर भी दिलाना चाहूंगा । उसको बनाकर वह अपने जिले का भी उपकार कर सकते हैं और साथ ही टेहरी, गढ़वाल, सहारनपुर, और देहारादून जिलों का भी उपकार कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम अभिलाख (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री लहरी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो हमारी सरकार के अंतर्गत जितने विभाग हैं उनमें पी०डब्लू०डी० बहुत महत्व का विभाग है लेकिन जैसी धांधली इस विभाग में चल रही हैं उसको देखते हुए अगर इसको प्रामीनेंटली वर्स्ट डिपार्टमेंट कहा जाय तो अनुचित न होगा। हमारे सदन के सभी सदस्य इस बात से परिचित हैं कि ठेकेदार लोग करीब १० से १५ परसेंट तक रिश्वत के रूप में जब देते हैं तब उनको ठेका मिलता है और अगर वह यह रूपया न दें तो यह ठेके का काम चल नहीं सकता है। टेन्डर के साथ यह परसेंटेज जोड़ कर ठेकेदार अपने टेन्डर दाखिल करता है और इस प्रकार सरकार की और जनता का गाढ़ी कमाई का यह रुपया बरबाद होता है। और जैसी रिशवत है उसको देखते हुये अगर इसको पेन ड्रापिंग वंडरफुल डिपार्टमेंट कहा जाय तो बुरा न होगा। अहलकारों ने इधर कलम रखी नहीं कि पैसा एक जेब से दूसरी जेब में गया नहीं। पुलिस विभाग में तो पुलिस कर्मचारी जब डाकुओं कातिलों का मुकाबला करते हैं तब उनकी जेब गर्म होती है लेकिन इस विभाग में तो अजीब सा करिशमा है, कलम की निब रोक दी जाय और पैसा किसी की जेब से अपनी जेब में आ गया। तो सरकार को चाहिये कि वह इस तरह की धांधली को रोके, लेकिन वह कुछ कर नहीं रही है। जब आजादी मिली थी तो मैंने सोचा था कि हमारे प्रदेश में सड़कों का माइलेज काफी बढ़ जायगा, लेकिन जब मैं, बढ़ोत्तरी क्या हुई है, देखता हूं तो वह नामिनल ही दिखायी देती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ये सड़कें हमारे प्रदेश की नसें हैं, उस हिसाब से सड़कों की मात्रा बढ़नी चाहिये। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि और डिपार्टमेंट से रुपया काटकर इस डिपार्टमेंट में कर दिया जाय बशर्ते कि भ्रष्टाचार न हो और रुपये का अपव्यय न हो। नई सड़कों का मइलेज काफी कम है और जो पुरानी सड़कें हैं उनका इन्तजाम खराब है। सड़कों में बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। मैं भी एक सड़क का जिक्र कर देना चाहता हूं। हमारे यहां गोंडा से बलरामपुर को एक सड़क जाती है, रास्ते में इटियाखान एक स्थान है वहां से ६ मील सरजूपुर बाजार एक बहुत बड़ी मंडी है। वहां की सड़क कई बार बन चुकी है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। गवर्नमेंट के अहलकार, ब्रान्च रोड होने के कारण बहुत कम पहुंचते हैं। इसलिये कंकड़ की जगह मजबूत मिट्टी की बना दी जाती है। बरसात में जहां पर कीचड़ हो जाती है और कोई भी सड़क पर चल नहीं पाता है। ब्रान्च सड़कों की हालत सब जगह ऐसी ही है। हमारे गोंडा जिले का न तो एक भी मिनिस्टर है, न डिप्टी मिनिस्टर है और न कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ही है, इसलिए हमारे जिले की हालत बहुत ही खराब है। यहां पक्षपात होता है और सब अपने-अपने घर की ओर काम कराते हैं। राप्ती के उत्तर में हमारे यहां कोई सड़क नही है। राप्ती के पार जाने में बड़ी कठिनाई होती है। बाढ़ के दिनों में बाढ़ पीड़ितों को सामान पहुंचाने में बड़ी कठिनाई होती है। चीन और भारत के बीच में नैपाल ही एक राज्य है जो बीच में पड़ता है। इसलिये गोंडा से नैपाल को मिलाने वाली एक सड़क का होना अत्यन्त आवश्यक है। तो डिफेंस के दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि बलरामपुर से नैपाल की सीमा तक सड़कें बनायी जायं और राप्ती नदी पर पुल बनाया जाय जिससे अगर कोई आपत्ति आये तो अपने आदमियों और रसद को वहां भेज सकें। लेकिन इसकी ओर प्रादेशिक सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

मैंने सुना है कि सरकार राप्ती नदी पर पुल बांधने के लिये विचार कर रही है। सुना है कि रेलवे मोटर ब्रिज बनाने पर विचार हो रहा है। एक पत्र इसके बारे में हमारे जिले से आया है कि डकन सिस्टम का पुल न बनाया जाय। सुना है कि ३ लाख रुपये की सड़क के पुल में कमी पड़ती है। इसमें से एक लाख रुपया जिला बोर्ड देने को तैयार है, एक लाख रुपया प्लानिंग डिपार्टमेंट दे रहा है और एक लाख रुपया बलरामपुर स्टेट देने को तैयार है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप डकन सिस्टम का पुल न बनायें बल्कि अपना स्वतंत्र सड़क का पुल बनायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा मकान बनाये जाते हैं और अधिकतर रुपया मकानों पर ही खर्च किया जाता है तथा सड़कों पर कम खर्च किया जाता है । वहां पर बजरी की जगह सेकेंड और थर्ड क्लास ईंट की सुर्खी का इस्तेमाल किया जाता है । देहातों के अन्दर जो छप्पर बनते हैं, यदि रस्सी के बंधन अच्छी तरह से लगाये जांय तो वे भी कम से कम १० साल तक चल जाते हैं । अगर मंत्री महोदय अपने बंगले में एकाध छप्पर इस तरह का डलवा लिये होते तो इसका अनुभव उनको हो जाता लेकिन उन्होंने ऐसा छप्पर डलवाया नहीं है । अगर एक लाख, दो लाख और तीन-तीन लाख रुपये लगा कर मकान बनाये जायं और वे इतने कमजोर हों कि साल भर के बाद ही ५० हजार रुपये मरम्मत में ही लग जाय, उससे कोई फायदा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---मालूम होता है कि बहुत से माननीय सदस्य इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं । तो आगे से भाषण देने वालों के लिये समय १० मिनट के बजाय ५ मिनट रहेगा ।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

कई सदस्य---यह तो बहुत कम समय है ।

श्री अधिष्ठाता---अच्छा तो अब आइन्दा भाषण का समय ७ मिनट होगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---वह बाद में लिया जायेगा ।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी देर के बाद आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी । यह अनुदान जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, बड़े महत्व का अनुदान है, क्योंकि इससे प्रदेश की जनता को सुन्दर और सुदृढ़ मार्ग मिलता है । इस अनुदान के प्रस्तुत करने के उपलक्ष में मैं माननीय मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं । यों तो यह अनुदान बड़ा लोकप्रिय मालूम होता है क्योंकि जिस चीज की आलोचना अधिक होती है और सराहना भी होती है, उसकी चाहना भी अधिक होती है । सभी लोग यह चाहते हैं चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, कि सड़कें बननी चाहिए और हमारे क्षेत्र के हर गांव में बननी चाहिए । इसलिये मैं देखता हूं कि इस अनुदान की लोकप्रियता अधिक है और वास्तव में है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । इस विभाग ने इस समय बड़ी क्रान्ति की है । इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन जगहों पर भी सड़कों का निर्माण हो रहा है या होगा, जहां सदियों से आवागमन का कोई साधन नहीं था । इसके माने यह नहीं हैं कि अब सड़कों की आवश्यकता नहीं है, अभी भी इसकी बड़ी आवश्यकता है ।

मैं मिर्जापुर की बात बतलाऊं, जहां से मैं आया हुआ हूं । मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि मिर्जापुर शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है जो ध्वस्त होता चला जा रहा है । गंगा के कटाव से सारे के सारे उसके घाट ध्वस्त होते जा रहे हैं । अगर सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र ही २, ४ या १० साल के बाद आपको मालूम होगा कि यहां कोई शहर बसा हुआ ही नहीं था । सरकार का ध्यान अब उस तरफ गया है और उसकी जांच वगैरह हुई है, फिर भी आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र उन घाटों की मरम्मत और उस पानी के बहाव का इन्तजाम होना चाहिये जिससे शहर का कटाव न हो । साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल की बड़ी मांग है और वह बहुत दिनों से मांग है । चुर्क सीमेंट फैक्टरी के हो जाने से और रिहन्द डाम के हो

[श्री राजकुमार शर्मा]

जाने से उस पुल की अत्यन्त आवश्यकता हो गयी है ताकि उस से जौनपुर, वाराणसी और मिर्जापुर का सम्बन्ध जोड़ा जाय । इस पुल के सिलसिले में मुझे एक बात याद आ गयी है और वह यह कि बनारस के राजघाट पर जो पीपे का पुल बनता था, उस पीपे के पुल की अब वहां कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है । मैं चाहता हूं कि उस पीपे के पुल को चुनार गंगा घाट के पास लगा दिया जाय जिससे चुनार से कछवा तक और बनारस से मिर्जापुर तक ही नहीं बल्कि बिहार के चैनपुर तक एक सीधा सम्बन्ध हो जाय । चुनार नगर की हालत आज बहुत खराब है उसके सुधार की आवश्यकता है, यह वहां की जनता की एक आवश्यक मांग है कि वहां गंगा घाट पर एक पीपे का पुल बनाया जाय ।

सड़कों के बारे में मैं बताऊंगा कि वह हमारे यहां बनी तो हैं लेकिन अभी भी वहां काफी कमी सड़कों की है ।

१—जमालपुर-कंचनपुर रोड जो रामनगर से चकिया को जाती है बनारस से रामनगर तक पक्की हो गई है और चकिया से सिकन्दरपुर तक पक्की हो गयी है, उस पर पुल भी बन गया है लेकिन वह मिर्जापुर में अभी तक कच्ची है जिससे रामनगर और चकिया के बीच का रास्ता बड़ा दुर्गम हो गया है । उसका बनाया जाना बहुत आवश्यक है ।

२—इसी तरह से केलहट, देवरिया-कोलवा, रस्तोगी सड़क है जिस की हालत बहुत खराब है, वह पक्की बननी चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां पधारे थे और बनारस से चुनार को जो सड़क जाती है उसके लिये वहां के लोगों ने उनसे बहुत कहा था । कुछ ऐसे भी स्थान हैं कि जहां आवागमन के साधन बिलकुल नहीं हैं ।

३—इसी तरह से चुनार घाट-अदलपुरा-बनारस जाने वाली सड़क का बनना भी नितांत आवश्यक है ।

४—और चुनार—जलालपुर—माझी—गांगपुर घाट तक की एक छोटी सड़क का निर्माण जरूरी है । संयोग से हमारे क्षेत्र में पहाड़ी और मैदानी दोनों तरह के इलाके हैं, बाढ़ का भी इलाका है परन्तु वहां आवागमन के साधन बहुत ही कम हैं । मैं दो-एक सड़कें जो बनी हैं उनके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि उन के बन जाने से वहां के लोगों को भी मालूम हुआ है कि वास्तव में "स्वराज्य" हुआ है ।

इसके अलावा कुछ और भी बातें मुझे कहनी हैं । एक बात यह है कि चुनार का किला बहुत पुराना ऐतिहासिक किला है । हमारे कुछ साथी जो मूवमेंट में जेल गये होंगे तो उस किले में रहे भी होंगे । उसकी मरम्मत के लिये हर साल रुपया रखा जाता है लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो पाती, इस साल भी रुपया रखा गया है इसलिये इस बार उसकी मरम्मत अवश्य करा दी जाय ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक चुनार—अहरौरा सड़क है जो इमलिया तक बन गई है और थोड़ी सी बाकी रह गई है । अगर ५० हजार रुपया बजट में इसके लिये अब की बार रख दिया जाय तो यह भी बन जाय यही मेरी प्रार्थना है । इस को पूरा करने से जनता का बहुत कष्ट दूर हो सकता है । जो थोड़ा काम बाकी है वह इस साल कृपा करके पूरा करा दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस विभाग में सड़कों पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं । आप जानते होंगे कि सड़कों पर काम करने वाले.....

श्री अधिष्ठाता—पहले आप यह तो बता दें कि आप कटमोशन की ताईद कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं कटमोशन की ताईद कर रहा हूं। सड़कों पर काम करने वाले जो गैंग कहे जाते हैं उन की जिन्दगी की तरफ सरकार की कोई तवज्जह नहीं है। हमें उनके विषय में जानकारी है कि उन को मास में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। वह २४ घंटे के नौकर हैं और उनका वेतन है २६ रुपया और ३० रुपया माहवार और मुझे यह भी जानकारी है कि उस कम वेतन में से भी अगर वह कुछ ओवरसियर को निकाल कर न दें तो उन की जिन्दगी का ठिकाना नहीं कि वह कब निकाल दिये जायं और आजमगढ़ व बलिया का मेरे पास सबूत है कि कितने ही मेट और मजदूर इसी कारण से निकाले गये हैं। सड़कों के किनारे की लकड़ी काट कर ओवरसियर के सुपुर्द करना भी उन का काम है। अगर ठेकेदार से ओवरसियर की नाराजगी हो गई तो अपना जो उसका एक छोटा-सा कागज उसे मिलता है उस कागज में उसे भरना पड़ता है कि हम फलां आदमी के काम में इतने दिन अपने गैंग को लेकर काम किये हैं और उतने पैसे उस ठेकेदार के पैसे में से कट जाते हैं। जो गैंग का मेट और उसमें रहने वाले इस तरह का काम नहीं करते हैं, वह निकाल दिये जाते हैं। मुझे जानकारी है। सरकार की ओर से कोई हिफाजत उनकी नहीं है और ऐसे-ऐसे गैंग के मेट जो १०-१० साल से, २०-२० साल से काम करते हैं, निकाल दिये जाते हैं। यदि ओवरसियर के खिलाफ कोई अप्लीकेशन दे दे श्रीमन्, तो फिर उसके लिये सबूत हाईकोर्ट की तरह देना पड़ता है। हमारे पास शिकायत आयी कुछ गैंग वालों की, कुछ ठेकेदारों की एक ओवरसियर के सम्बन्ध में। हमने चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखी कि यह आदमी १० साल से यहां पर है, आजमगढ़ जिले में इसको किसी दूसरी जगह तबादला तो करो। तो तबादला करने के पहिले श्रीमन्, हमसे सबूत मांगा गया। लेकिन वह सबूत भी ऐसा श्रीमन्, कि ६०-६० मील से दो-दो मर्तबे गवाह आये, लेकिन इंजीनियर साहब को फुरसत नहीं मिली। बार-बार बुलाने का मतलब हम तो यही समझते हैं कि इंजीनियर साहब ओवरसियर की मदद करना चाहते हैं क्योंकि वह सबूत लेना नहीं चाहते हैं।

माननीय गिरधारी लाल जी ने कुछ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की भी चर्चा की है। कुछ उनके अन्दर दर्द मालूम हुआ। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि बाढ़पीड़ित क्षेत्रों को संबंधित करने के लिये आपने अपने कार्यकाल में किन-किन बाढ़पीड़ित जिलों में सड़कें बनवायीं? हम तो बजट देखते हैं। सातवां साल बीत भी रहा है। बारहों या चौदहों बाढ़पीड़ित जिलों का ज्ञान भले ही मुझे न हो लेकिन आजमगढ़ जिले का मुझे ज्ञान है। वहां के चेयरमैन ने हमारे साथ माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि यह बाढ़पीड़ित क्षेत्र की सड़कें हैं। अगर आप आधी मदद दें तो आधा रुपया बोर्ड से लगाकर हम इन सड़कों को बनवा लेंगे। लेकिन आजमगढ़ जिले की एक भी सड़क नहीं बनी और जिलों में बलिया, देवरिया वगैरह में कुछ बनीं लेकिन हमारे जिले में और गोरखपुर, बस्ती वगैरह में बाढ़पीड़ित क्षेत्र की सड़कों को जिले से संबंधित करने के लिये सरकार ने और इस विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर सरकार बाढ़पीड़ित क्षेत्र की हालत को ठीक करना चाहती है तो उसे पहले उन क्षेत्रों की सड़कों को जिले के सदर मुकाम से संबंधित कर देना चाहिये। एक सड़क है माननीय मुक्तिनाथ राय के क्षेत्र में बिलरियागंज से रौनापार तक। रौनापार थाना है, एक मुख्य स्थान है लेकिन वह सड़क पी० डब्लू० डी० नहीं बनवा सका। मधुबन से दुबारी एक सड़क जाती है। उसकी हालत बहुत खराब है। एक सड़क है कप्तानगंज से अहरौरा तक, वह अब

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तक नहीं बन सकी है। निजामाबाद का पुल नहीं बना और श्रीमन्, मऊ इस सूबे का एक बहुत बड़ा स्थान है। तीन साल उस पुल को टूटे हुए हो चुके हैं लेकिन आज तक उस पुल के निर्माण की ओर कदम नहीं उठ सका। दोहरीघाट का पुल जिसका सम्बन्ध कई प्रमुख स्थानों से है, आज तक तैयार नहीं हो सका। तीन-चार साल से उसका आकलन केन्द्रीय सरकार के पास जा रहा है, वहां से यहां आता है, पता नहीं चलता है कि बनेगा या नहीं बनेगा। मोहम्मदाबाद श्रीमन्, तहसील है, घोसी से मुहम्मदाबाद सड़क जाती है। टोंस नदी बीच में है, पुल नहीं बना। श्रीमन्, हंसी आती है सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर पर, आपको कभी आजमगढ़ जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे एक पुल पारसाल बनकर तैयार हुआ है। पहले पुल की मरम्मत हुई है। सिथरी का पुल अलग है बीच में एक पुल और बनाया जा रहा है। यह तुगलकी नीति पी० डब्ल्यू० डी० से हटनी चाहिये। ऐसे पुल बनें, ऐसी सड़कें बनें, जो हर साल तोड़ी न जायं। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियरों का क्या तरीका है, क्या काम करने की पद्धति है? श्रीमन्, इसके अलावा आप देखेंगे कि जहां से माननीय उपाध्यक्ष महोदय आते हैं उस क्षेत्र को हमने देखा है कितनी सड़कें हैं, क्या सम्बन्ध है? कोई सम्बन्ध नहीं। मेरी जानकारी है, बलिया में एक स्थान है, गांव का नाम मैं भूल गया हूं वहां पर किसी बड़े मंत्री के कोई गुरु रहते हैं उस गुरु को खुश करने के लिये ६ मील की सड़क बनायी जा रही है जबकि दो मील के फासले पर सड़क पहले से मौजूद है। सारे किसान वहां के उसका विरोध करते हैं। वहां तो सड़क बनेगी लेकिन जहां आवश्यकता है वहां हजार बार कहिये, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के बारे में कहिये सड़कें नहीं बनतीं।

मजदूरों के सम्बन्ध में मैं फिर कहना चाहता हूं। उनके सम्बन्ध में आपकी सहानुभूति होनी चाहिये। उनकी नौकरी मुस्तकिल होनी चाहिये। २६ रुपये माहवार जो तनख्वाह देते हैं उसको बढ़ावें और हफ्ते में एक दिन मुस्तकिल छुट्टी दीजिये। और ऐसे ओवरसियर और इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर की जानकारी में भी हैं, जो वर्षों से एक जिले में रहते हैं, काफी पैसा कमाये हैं, उनके सम्बन्ध में, जैसे और विभागों में सरकार करती है, यह जरूर कर दें कि उनके तबादले तीन-चार साल बाद जरूर कर दिये जाया करें। मैं फिर दोबारा निवेदन करूंगा कि जैसे और विभागों में इसकी पाबन्दी है कि तीन, चार साल के बाद कोई उस जिले में नहीं रहने पाता है, वैसे ही पी० डब्ल्यू० डी० में भी हो जाय। अगर ऐसा हो जाय तो मेरा खयाल है कि माननीय गोविंद सहाय जी का जो तर्क है कुछ आगे बढ़ कर शायद कामयाब हो सके। मैं उम्मीद करता हूं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य इस विभाग के जरिये बड़ी तेजी से कुछ जिलों के अन्दर होना चाहिये।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय निर्माण मंत्री जी ने अनुदान पेश करते हुए जो यह कहा था कि किसी देश की प्रगति वहां की सड़कों के ऊपर निर्भर होती है, मैं उससे सहमत हूं। किसी देश में अगर यातायात के साधन सुगम और आवश्यकता के अनुसार हैं तो वह देश चतुर्मुखी उन्नति कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज देश में जितने और निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सड़कों की बहुत आवश्यकता है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा था कि जिस जगह पर पहले से सड़कें बनी हुई हैं और जहां ज्यादा सड़कें हैं वहीं पर सड़कें और भी बनायी जाती हैं और जहां सड़कों की कमी है वहां का ज्यादा खयाल नहीं किया जाता है। यह श्रीमन्, करीब-करीब कुछ सही-सा मालूम होता है। अगर मुझे मुगालता नहीं है तो मैं तो यह समझता हूं कि हमारी सरकार के जो मंत्रिगण हैं या सरकार में जो और विशेष असर वाले व्यक्ति हैं वह जिस जिले के हैं हमारे अधिकारीगण उन्हें खुश करने के लिये ऐसे फारमूला बनाते हैं कि जो मजबूर होकर सरकार को उनको मन्जूर करना पड़ता है और वहां कुछ सड़कें अधिक बनती हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जब सरकार समाजवादी व्यवस्था चाहती है तो अभी तक जिन लोगों का निरादर किया गया,

जिनको कोई सुविधा नहीं दी गयी, उनको सुविधा देने की सरकार कोशिश करे। मैं अपने मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम हर जिले को, जहां को विशेष जरूरत है वहां के किसानों को, सुविधा हो, वहां पर काश्तकारों के लिये कुछ न कुछ काम अवश्य करायें। मेरे जिले इटावा में सड़कें बहुत ज्यादा तो नहीं हैं, वहां सड़कों की कमी है और कमी के होते हुए सरकार ने एक फारमूला बनाया कि जिन जिलों में ज्यादा सड़कें हैं वहां सड़कें नहीं बनाई जायंगी और जहां कमी है वहां दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कच्ची सड़कें पक्की की जायंगी। जब मुझे उसका नक्शा प्राप्त हुआ तो पता नहीं अधिकारियों ने किस तरह से यह फारमूला बनाया, जिन सड़कों के लिये मुझे ख्वाब भी नहीं था, जिनके सम्बन्ध में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वे सड़कें पक्की होंगी उनके तो नाम दिये हुए थे और जिनकी जरूरत थी उनका नाम गायब था। हुआ क्या कि जिन सड़कों पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कभी दो चार मील में कंकड़ बिछा दिये थे और उन कंकड़ों का आज नामोनिशान भी नहीं रहा और कच्ची से भी बदतर वे सड़कें हैं, उनको पक्की सड़कों में आज लिखा हुआ है।

मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे थोड़ा-थोड़ा काम हर जिले के गांवों में करें ताकि देहात वाले भी समझ सकें कि वाकई वे आजाद हैं और उनके यहां भी कुछ काम हुआ है। मैं मंत्री महोदय को अपने जिले की बात बतलाना चाहता हूं कि वहां उसराहार से सिन्दौस एक ३०-३२ मील की सड़क है। जिस समय मैं पढ़ रहा था और ८, ९ वर्ष का हूंगा उस वक्त १९१२ की बात है उस सड़क पर कुछ काम हुआ। यह उस जिले के लिये बहुत जरूरी सड़क समझी जाती थी। उस पर कुछ पुलियां भी बनायी गयीं और मिट्टी की भराई की गयी। सन् १३ में लड़ाई का जमाना आ गया और पहला महायुद्ध छिड़ गया और वह काम ठप्प हो गया। इसके बाद दोबारा सन् २८ में फिर कोशिश की गयी और भराई की गयी और भराई खत्म होने पर पुलिया बनायी गयी। कुछ ऐसा महसूस होता था कि इस सड़क को पक्का बना दिया जायगा लेकिन उस वक्त भी वह फिर पक्की न बन सकी। फिर ३८-३९ में जब कांग्रेस सरकार आई तो उस पर फिर काम शुरू हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश वह सड़क आज तक नहीं बन पाई। माननीय मंत्री जी उस तरफ ध्यान देने की कृपा करेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जिले की जनता की राय ले कर वे सड़कों को लें न कि अधिकारियों की बात मानकर, जो यहां बैठे-बैठे फारमूले बनाते हैं। जिले के हित के लिये और किसानों के हित के लिये जो जिले को आवश्यक सड़कें हों उनमें थोड़ी बहुत हर जिले में स्थानीय जनता से राय ले कर वे सड़कें बनायें ताकि जनता समझ सके कि हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है और उसमें उसको भी कुछ हिस्सा मिल रहा है।

मैं अपने यहां की एक मिसाल और देता हूं। एक ५ फर्लांग सड़क वहां बनायी गयी। दो वर्ष हुए मिट्टी डाल कर उसे कूटा गया। २५-३० हजार रुपया इसमें खर्च हो गया। १४ हजार रुपया पेन्ट के लिये मंजूर था।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बलदेवसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री लहरी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा जिला गोंडा बड़ा बदकिस्मत है, न तो पूर्वी जिलों में गिना जाता है और न पश्चिमी जिलों में गिना जाता है। बीच में, अधर में त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है। उसके डेवलपमेंट के सिलसले में तो क्या बतलाऊं, लेकिन मैं मंत्री जी को विशेष रूप से यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस महकमे में जितना अपव्यय

[श्री बलदेव सिंह]

हुआ होगा उतना शायद किसी दूसरे महकमे में नहीं हुआ होगा। मैं यह नहीं कहता कि इसमें सब के सब भ्रष्ट आदमी हैं और ईमानदार नहीं हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जितना अपव्यय हुआ वह शायद कहीं न मिले और उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यहां इस विभाग के संचालक, सब से उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। हमारे जिले गोंडा में एक सड़क मंजूर हुई कि नवाबगंज की सड़क बनेगी। पत्थर पड़ गया, कालपी से सैंड आया, गाड़ी से उतरा, किनारे लगाया गया और फिर साल भर के बाद मालूम हुआ कि यह सड़क नहीं मंजूर हुई। वह मैटिरियल उठ कर दूसरी सड़क के लिये जायगा। तो उसका इतना कार्टेज लोडिंग अलग पड़ा और मौरंग आज तक पड़ी है।

एक खारी बावली पार्वती रोड बनने को थी। ४–५ मील का सी० सी० ट्रैक्ट था, उसके लिये सारा मैटिरियल इकट्ठा हुआ, अब बालू और मैटिरियल उठाये जा रहे हैं। दूसरे मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि एक पुल लकड़ी का गोंडा से ७ मील दूर टेरी नदी पर बना था, पी० डब्ल्यू० डी० ने बनाया सन् ४७ में और वह डेढ़ लाख रुपये में बना और सन् १९४९ में ढह गया। जी हां, दो साल के अन्दर वह पुल बह गया। फिर उसके ऊपर मंजूरी हुई है, ४ लाख रुपया खर्च होने जा रहा है। तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आखिर जो इतना अपव्यय होता है इसकी जांच भी होगी, इसकी तहकीकात भी होगी कि यह क्यों हुआ है और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इन चीजों की ओर ध्यान दें और इसमें जांच करायी जाय।

एक सड़क बनती है बरसपुर से नवाबगंज को, उस पर हमारे एक माननीय सदस्य ने लिखा भी है और हमने स्वयं देखा कि दूसरे और तीसरे नम्बर की ईंट लगाई जा रही है। लिखा भी उन्होंने, क्वेश्चन भी किया था, मालूम नहीं कि आपका ध्यान उस ओर गया या नहीं। यह मैं इस मतलब से कहता हूं कि इस विभाग के सारे संचालक मौजूद हैं, वह शायद गौर करें और ध्यान दें कि यह जो अपव्यय हो रहा है अगर खाली इसी को रोका जाय तो मैं समझता हूं कि महान् कार्य हो सकता है। एक निश्चित कदम होना चाहिये कि हम क्या बनाना चाहते हैं और क्या चीज हम बनायेंगे। यह नहीं कि मैटिरियल यहां रखा, वहां उठाया।

एक सड़क मनकापुर से मिसकनवा को २ मील की मंजूर हुई। लोगों ने ईंटा इकट्ठा किया, रोड़ा भी टूट गया और पत्थर की बजरी भी टूट गयी है। अब एक साहब ने बताया है कि यह सड़क मंजूर नहीं हुई है, तारकोल नहीं पड़ेगा और यह बजरी यहां से उठायी जायगी। मैंने वहां से हटाने को रोक दिया है और मैंने कहा कि मैं मंत्री जी से कहूंगा और शायद मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इसको समझने की कोशिश करें। मनकापुर से मिसकनवा जाने वाले उस रास्ते में..... क्या टाइम हो गया?

श्री उपाध्यक्ष—आप एक सांस में सब सड़कों का नाम गिनवा दीजिये कि यह बनवा दी जायं (हंसी)।

श्री बलदेव सिंह—तो उस सड़क पर एक ऐसी सड़क बनी है जो पी०डब्ल्यू०डी० की सड़क है। उसमें छोटा-सा नाला पड़ता है, वह बरसात में भर आता है, तब लोग रेलवे के पुल से क्रास करते हैं और हर साल दो, एक मौतें हो जाती हैं। बार-बार लिखा-पढ़ी की गयी और कोशिश की गयी, लेकिन मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया।

तीसरी बात यह कि राप्ती के पुल के बारे में अभी रामअभिलाख जी ने बताया कि डेंकिंग होने जा रही है और अगर डेंकिंग होगी तो ६ लाख रुपया लगेगा और अगर इंडिपेंडेंट पुल बनेगा तो ९ लाख रुपया लगेगा। वहां की प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक चिट्ठी भी लिखी है, वह शायद माननीय मंत्री जी के पास आ भी गयी होगी कि ३ लाख रुपये का इन्तजाम गोंडा जिले में हो रहा है। एक लाख डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देगा, एक लाख प्लानिंग कमेटी देगी और एक लाख बलरामपुर स्टेट देगी। तो ३ लाख रुपया यह और ६ लाख

और मिला के एक इंडिपेंडेंट पुल बनवा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिन चीजों को मैंने बताया है, उनकी जांच कराने की कृपा करेंगे।

*श्री रामलाल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ये दो साधन ऐसे हैं पुल और सड़क कि जिनसे पूरे देश के लोगों को फायदा होता है। चाहे अमीर हों या गरीब, मोटर पर चलने वाले हों, चाहे इक्का, तांगा या पैदल के चलने वाले हों, इन दोनों साधनों से मुल्क के पूरे निवासियों का सम्बन्ध है और उनको फायदा पहुंचता है।

श्रीमन्, समय थोड़ा है इसलिये मैं अपने जिले बस्ती की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे जिले में चार चीनी मिलें हैं और वहां की अधिकांश पैदावार गन्ने की है। किसान बैल गाड़ी से अपना गन्ना मिलों में ले जाता है। सड़क खराब होने के कारण जो दिक्कत किसानों और बैलों को होती है वह बड़ी दर्दनाक होती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तो महुली-महसो रोड की हालत बहुत खराब है। वह सड़क सन् १९५७-५८ के बजट में रखी गयी थी लेकिन दुर्भाग्यवश सन् १९५८-५९ के बजट में वह नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी से निवेदन करने पर उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि यह सड़क इस वर्ष बनेगी। इसी प्रकार से एक सड़क है जो छावनी-जनकरोड कहलाती है और हैंसर बाजार तक गयी है। उसका भी बनना बहुत जरूरी है। इसी तरह एक सड़क लालगंज से मुंडेरवा मिल को जाती है, उसका भी बनना बहुत जरूरी है। अभी मैं ४ तारीख को मेंहदावल-बस्ती रोड पर एक सिंदिरयावा स्थान है वहां एक मीटिंग में गया था। ८ हजार की संख्या में लोग उस सम्मेलन में आये। उनकी पहली मांग यह थी कि हमारे यहां की यह सड़क बहुत खराब है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको भी बनवाने की कृपा करें। कभी वह बड़ी अच्छी पक्की सड़क थी लेकिन आज वह कच्ची से भी गयी गुजरी है और बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी है। मेरे क्षेत्र में एक स्थान लालगंज बाजार है। उसी के करीब से एक कुआनो नदी बहती है। इसी जगह एक मनवर नदी मिली हुई है जिससे उस नदी का नाम मुहानी पड़ गया है। चैत की पूर्णिमा को यहां एक नहान लगता है और लाखों नर-नारी नहाते हैं। एक बार नाव दुर्घटना हुई और बहुत से आदमी डूबे तथा मरे। पुल के लिये सम्मेलन द्वारा तथा दरख्वास्त द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया और मैंने भी उनसे कहा। लेकिन अभी तक वहां पुल नहीं बन सका है। अब मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान दें। श्रीमन्, एक तरफ घाघरा नदी है, कुआनो और मनवर है और पूर्वी जिलों में खासकर बस्ती में बाढ़ अक्सर आया करती है। इस साल राहत मिली तो सूखा से बरबाद हुए। जब बाढ़ आती है तो घाघरा, कुआनो और मनवर के बीच में जो दोआबा है वहां के लोगों का आना जाना बिलकुल बंद हो जाता है। अगर कोई गरीब आदमी चाहे कि बरसात में नाव हो जाय तो उसको काफी मल्लाही देनी पड़ती है। मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि इस पुल के लिये अवश्य ध्यान दिया जाय जिससे दोआबा के लोगों को राहत मिल सके। श्रीमन्, मुझे यही कहना था और माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुये, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाशकुमार सिंह (जिला बदायूं)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कपा हुई आपकी जो थोड़ा सा समय दिया और इसके लिये काफी परिश्रम भी करना पड़ा। मैं माननीय मंत्री जी को सूबे के कार्यों के लिये ऐसी सुन्दर व्यवस्था रखने के लिये धन्यवाद देता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में कहा, किसी ने और भी बातें कहीं। लेकिन जैसा लोग इस विभाग के बारे में सोचते हैं उसको यदि मैं स्पष्ट कहूंगा तो सम्भव है कि कुछ ऐसी बात हो जाय कि वह माननीय मंत्री जी को रुचिकर न हो। लेकिन फिर भी आम जनता की जो इस विभाग के सम्बन्ध में धारणा है, वह कुछ अच्छी नहीं है। इसके विषय में यह कहा जाता है कि जो काम मकानों तथा सड़कों आदि का पी० डब्ल्यू० डी० से कराया जाता है वह यदि दूसरे जरिये से कराये जायं तो लागत कम आयेगी। ऐसा विचार एक आम है। इसका कारण समझ में नहीं आता है कि क्या बात है? लेकिन यह भी कहा जा सकता है, जैसा कि श्री गोविंद सहाय ने कहा कि एजेंसी जो प्राइवेट ठेकेदार की है, उसके जरिये काम कराने में कुछ ज्यादा व्यय होता ही है। सब लोग जानते हैं कि उनके जरिये काम कराने में खर्चा ज्यादा होना स्वाभाविक है।

अभी रायल होटल में विधायकों के लिये कुछ नये कमरे बन रहे हैं। उनका नक्शा दारुलशफा से भी खराब है। इसके विषय में मैंने पत्र भी भेजा था जिसका उत्तर भी प्राप्त हुआ और मैंने सुझाव भी दिये हैं। लेकिन मैं यह नहीं जानता हूं कि उन पर अमल होगा या नहीं। लेकिन मैं अपने विचार सदन के सामने रख देना चाहता हूं। जिस समय दारुलशफा का नक्शा बनाया गया था, शायद यह १९४३-४४ की बात हो या इसके नजदीक की ही रही होगी तो उस समय इस नक्शे की नकल पश्चिमी देशों से की गयी थी। लेकिन हम लोग जो चुनकर आते हैं, वह किसानों के प्रतिनिधि हैं और हमारा उन्हीं के परिवारों से सम्बन्ध है तो हमारे रहने के लिये जो व्यवस्था हो तो उसमें कम से कम चौका, कपड़े इत्यादि सुखाने के लिये जगह तथा पीछे बरामदा होना अति आवश्यक है जिससे कि हम जिस वातावरण के आदी हैं, जिसमें रहते हैं उसके अनुसार हमें सुविधा मिल सके। मैंने यही सुझाव इंजीनियर महोदय को दिया है और आशा है कि मंत्री जी भी इस पर विचार करेंगे और उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगे।

दूसरे मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी किया था, जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ कि जो इमारत बन रही है उसमें सहन ८ फुट का है उसके नक्शे के हिसाब से। विधायकों के लिये जो इमारत बने उसमें ८ फुट का सहन, कुछ उचित नहीं प्रतीत होता।

अब अपने कुछ स्वार्थ की बात कहूं अपनी कास्टीट्युएन्सी के बारे में। बदायूं में सड़क जरूर बनी है लेकिन वह सरकार की निगाह में ज्यादा युटिलिटी की है, वहां की जनता की नहीं। जनता की निगाह में उनकी यूटिलिटी कम है। इस्लाम नगर की सड़क पिछली पंचवर्षीय योजना में ली गयी थी लेकिन वह काट दी गयी और समझ में नहीं आया कि क्यों, जब कि उसको प्रायरिटी दी गयी थी। उस सड़क पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। इस का दूसरा आल्टरनेटिव मैं बतलाना चाहता हूं कि इस्लामनगर का ज्यादा सम्पर्क मुरादाबाद के दो कस्बों चंदौसी और बहजोई से रहता है, तो अगर उधर बदायूं जिले की हद में दो मील सड़क बना दी जाय तो लोगों को चन्दौसी और बहजोई जाने की सुविधा हो जायगी। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लहरी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं लहरी जी को इसलिये बधाई देता हूं कि उनका प्रस्ताव इतना समोचीन, इतना उपयुक्त और इतना प्रभावशाली और इतने सार्वजनिक हित का था कि इस अनुदान पर जितने सदस्य बोले हैं उनमें से अधिकांश ने ही नहीं, वरन् प्रायः सभी ने उनकी बातों का समर्थन किया है।

श्रीमन्, मैं इस थोड़े समय में कोई विशेष रचनात्मक सुझाव यहां नहीं प्रस्तुत कर सकूंगा और समालोचना करना मात्र मेरा उद्देश्य नहीं है। इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं जैसा मंत्री जी ने भी कहा और सभी इससे अवगत हैं कि अपने प्रदेश में यदि सब से बड़ी आवश्यकता किसी काम को करने की है तो वह सड़कों के निर्माण की है, विशेषकर जब कि हमें अपनी पंचवर्षीय योजना को चलाना है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि हम सारे प्रान्त में, जहां-जहां आवश्यकता हो, सड़कें बना सकें तो मैं समझता हूं कि वह सारे प्रान्त के पुनर्निर्माण के लिये ही नहीं वरन् इस साढ़े ६ करोड़ जनता के भाग्य निर्माण की वह सड़कें होंगी। उदाहरण के लिये मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहूं। अमरोहा कांठ कच्चा मार्ग जो १४ मील का है दोनों नगरों को मिलाता है। यह एक ही जिले तथा तहसील के नगर हैं। श्रीमन्, यह स्थान अमरोहा से १४ मील दूर है लेकिन आज कांठ के लोगों को अपने काम से ३८ मील चल कर आना पड़ता है। इसमें साढ़े तीन मील सी० सी० ट्रैक बन चुका है। बीच में तीन नदियां पड़ती हैं। नदी के किनारे आ कर काम समाप्त हो गया है। मंत्री जी कह सकते हैं कि यदि वहां के लोग सहयोग करें। उनको सहयोग करना चाहिये। मैं आप को बताऊं कि वहां के गरीब रहने वालों ने करीब साढ़े ७ हजार रुपया जमा कर लिया है जो पंचायतों के पास जमा है और भी कुछ वहां से प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी तक वह सड़क नहीं बनी और वहां की स्थिति आज तक जैसी की तैसी है। मेरा समय समाप्त हो गया है इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है और आपकी पैनी निगाह पहले मुझ पर पड़ती तो रही लेकिन अवसर न मिलने से आपके द्वारा आज्ञा नहीं मिली। इस अवसर के लिये आज आपको कोटिशः धन्यवाद है।

मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया था कि घोरावल -पन्नूगंज की सड़क बहुत दिनों से पुरानी पड़ी हुई है। पत्र भी इस बारे में लिखा गया था कि वहां पर रबी १९५७, खरीफ १९५७ और रबी ५८, तीनों फसलें खराब हो गयी हैं। यहां बतलाया गया था कि वहां सस्ते गल्ले की दूकानें बन्द हो गयीं। हम सरकार को बतलाना चाहते हैं कि वहां कोई काम-धंधा नहीं है। अगर घोरावल-पन्नूगंज की सड़क बना दी जाय तो जनता अपना काम धंधा कर ले और गैर सरकारी मोटरों की जगह सरकारी मोटरें चलें तो सरकार को भी आमदनी हो। कर्मनाशा नदी राबर्ट्सगंज तहसील को दो हिस्सों में तकसीम करती है। वहां की दस फीसदी जनता हमेशा पानी में डूबकर मर जाती है। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार का इस क्षेत्र की ओर जरा भी ध्यान नहीं है। उस क्षेत्र से सरकार को काफी आमदनी है। सीमेंट फैक्ट्री से भी सरकार को काफी आमदनी की वर्षा होती है। हर प्रकार की आमदनी होते हुए भी सरकार उस पहाड़ी क्षेत्र पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। वहां जनता के हित की एक भी सड़क नहीं बनायी जाती है। ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की कृपा करें नहीं तो उनको इस तरह के काम के लिये भगवान के घर जवाब देना पड़ेगा। हमारे यहां से घोरावल-पन्नूगंज सड़क की मांग की गयी है लेकिन हम देखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में भी वह काम शुरू नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह सड़क अवश्य बनवा दी जाय।

नई बाजार टुकमांव सड़क पर बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाती है और बड़ी तकलीफ होती है। सरकार इस पर भी ध्यान दे तो बड़े उपकार का काम होगा।

[श्री शोभनाथ]

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस पंचवर्षीय योजना में इन सड़कों को अवश्य बनवा दें ।

*श्री जगन्नाथ लहरी—परम श्रद्धा योग्य उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों में जो मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था, मैं एक बार पुनः उस पर बल दे रहा हूं । इससे पूर्व कि मैं अपने कुछ और विचार प्रकट करूं, मैं अपने परम आदरणीय और श्रद्धा योग्य दीनदयालु जी शास्त्री से दो शब्द कहना चाहता हूं । गुरुदेव, आपने फिर मुझे राह दिखायी लेकिन आप भूल गये कि हम और आप पश्चिमी यू० पी० के ही रहने वाले हैं, जिनको मुंह खोलने की भी इजाजत नहीं है, मांग करने का कोई हक नहीं है, केवल काम करने की इजाजत है और केवल पूर्वी यू० पी० का ही निर्माण हो रहा है । आगरे के पुल की जो मांग आपने की उसमें अगर आप अपने यहां के लिये न कह कर अगर थोड़ी उदारता और दिखाते और कहते कि पूर्वी यू० पी० में उसको भेज दिया जाय, तो अच्छा होता । गुरुदेव, आप याद रखें कि आगरे वाले पुल का निर्माण यू० पी० की सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है ।

श्री गौरीराम गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर । यह पूर्वी और पश्चिमी य० पी० की बात कही जाती है, यह शोभा नहीं देती है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप उनसे अपील कर सकते हैं । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बन सकता ।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, जिस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने अन्न उत्पादन पर विशेष बल दिया था । इसी प्रकार से आज इस बात की आवश्यकता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन निर्माण आदि कामों को बन्द करके सड़कों को प्राथमिकता दी जाय । पक्ष और विपक्ष, दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये उनमें हर एक ने सड़कों की मांग की , केवल एक माननीय सदस्य ने पुल की मांग की । आप इस वादविवाद को ध्यान में रखकर निर्माण विभाग के काम पर पुनः विचार करें कि क्या वास्तव में हमारे प्रदेश में इनकी आवश्यकता है या ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि इस विभाग के इंजीनियर्स और हमारे मंत्री महोदय, इस बार फिर इस पर ठंडे दिल से विचार करेंगे ।

माननीय मुरलीधर जी कुरील ने कहा कि जनता पुलों की मांग करती है, इसलिये पुलों की आवश्यकता है । हम कब कहते हैं कि पुलों की आवश्यकता नहीं है । लेकिन जो आदमी भूख से मर रहा हो वह तो पहले भूख की ज्वाला मिटाने की ही मांग करेगा, इसी आधार पर हमने सड़कों की मांग की है । आपने भी माननीय निर्माण मंत्री जी के पीछे खड़े होकर तारीफ का पुल बांधा । मुझे दुःख है कि जो पुल बन रहे हैं उनको जनता का पुल कभी भी नहीं कहा जा सकता । यह कोई बनिये की दूकान नहीं है । जनता की गाढ़ी कमाई से पुल का निर्माण किया जाता है और आप कहते हैं कि जनता को जाने की इजाजत नहीं है । उस पर से जाने का जनता से पैसा लिया जाता है । दूकानदार कभी भी अपनी दूकान चलाने के लिये कोई टैक्स नहीं मांगता है । तो जो एक बनिये की दूकान बन चुकी है कि जनता की कमाई द्वारा निर्मित पुल जनता के लिये नहीं है बल्कि सरकार की आमदनी के लिये है तो उसे मैं जनता का पुल कहने के लिये किसी भी हालत में तैयार नहीं हूं ।

इस विभाग द्वारा ५-५ लाख रुपये की इमारतें बनाने की बात है । मैं माननीय निर्माण मंत्री का ध्यान एक बार पुनः दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों से पूर्व मुगल शासक और दूसरे शासकों के जमाने में हमारे प्रान्त में जगह-जगह किले और इसी तरह की बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं और जो खाली पड़ी हैं, वे काफी मजबूत इमारतें हैं । एक कांग्रेसी सदस्य ने चुनार के किले की मरम्मत की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया कि उस किले की हालत खराब होती जा रही है । सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को चाहिये कि वह उन भवनों और इमारतों का प्रयोग अपने दफ्तरों के रूप में करे । फतेहपुर सीकरी का जो किला है उसमें सारे मिनिस्टरों के रहने का इन्तजाम हो सकता है, उसमें सारी फौजों के रहने का स्थान है, वहां इतना स्थान है जिसके अन्दर पूरा सचिवालय आ सकता है । सरकार चाहे तो उनकी मरम्मत करके उनका प्रयोग अपने कार्यालयों के लिये बिना और कोई इमारत बनाये हुए ही कर सकती है । लेकिन आज सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है । आज तो लोग अपने अमर स्मारक बनाने में लगे हुए हैं । अमर स्मारक बनाने की चाह छोड़िये ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गिरधारी लाल---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे पहले तो सदन के हर सदस्य को इस बात के लिये धन्यवाद देना है कि उन्होंने बहुत खुले दिमाग के साथ अपने विचार द्वारा इस विभाग के तमाम मसले पर रोशनी डाल कर मेरी मदद की । यह ठीक है कि मैंने कुछ पुलों का वर्णन किया है जिसका रूपक बना कर उन्होंने एक खुद पुल बनाया है जिसके जरिये बहुत मुमकिन है मैं किसी दूसरे कोने तक पहुंच सकूं । जो कुछ भी उन्होंने किया हो, लेकिन उससे मुझे काफी सहारा मिला और मैं और विभाग के जितने कर्मचारी हैं, जितने हमारे साथी हैं, मैं बहुत खुले दिमाग के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां भी हमने अपने विभाग के अन्दर कोई कमी पायी है उसको हमेशा दूर करने की कोशिश की है । एक बात मैं इस वक्त खासतौर से कहना चाहता हूं कि करप्शन के सिलसिले में कई बातें यहां कही गयी हैं । मैं समझता हूं कि मेरे स्थान पर कोई भी दूसरा व्यक्ति होगा, जो भी समझदार व्यक्ति होगा, हर एक को यह महसूस होगा कि हमारे समाज के अन्दर, हमारे विभाग के अन्दर, हमारे अन्दर और हमारे देश के अन्दर कतई यह कहना मुश्किल है कि करप्शन न हो । हमारे ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश हम करते हैं और इस तरह की कोशिश हर कांग्रेसी सरकार, जो देश और प्रान्तों में है, इस करप्शन को दूर करने की हर तरह से कोशिश कर रही है । कुछ सदस्यों ने कहा कि आखिर वे भी इंसान हैं, इंसान भी गलती करता है, इस बात को सभी मानते हैं । हमारे विभाग के अन्दर जितने भी कर्मचारी हैं वे बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कुछ लैक वशीप भी हो सकते हैं लेकिन जिस परिश्रम के साथ, जिस दयानतदारी के साथ वे काम करते हैं और प्रान्त के निर्माण के काम में जिस तरह की मदद करते हैं उसके लिये वे मुबारकबाद के पात्र हैं । फिर नीचे की जितनी बातें हैं, और जितने साधन हैं, उन तमाम साधनों को अख्तियार करने की हमने कोशिश की है और उसको सुधारने की कोशिश की है । करप्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने और देने की बात जो कही गयी है, इन सब बातों पर हम विचार करते हैं और हमारे दोस्तों ने जो सुझाव दिये हैं उनमें कुछ सुझाव ऐसे हैं, जिनके ऊपर हम अवश्य विचार करेंगे और उनके अनुसार काम भी करेंगे । मैंने जो दो एक सुझाव मुनासिब समझे उनको माना और मेरा विचार है कि बहुत से स्थानों पर जहां भी जरूरी होगा हम वहां पर इस प्रकार के रजिस्टर रखा देंगे जिन पर अगर माननीय सदस्यों को किसी तरह की शिकायत हो तो उस को वह दर्ज कर सकें ।

इस के अलावा बहुत सी बातें प्रणाली आदि के विषय में भी की गयी । इस के सम्बन्ध में मैं एक बात यह अवश्य कहूंगा कि हमारे प्रदेश में दो कमेटियां हैं, एक वर्क्स कमेटी और दूसरी रेट्स कमेटी । इन दोनों कमेटियों ने इस बात को देखा कि हमारे यहां जितने भी काम हो रहे हैं वह किफायतशारी के साथ हो रहे हैं या नहीं और उनमें वेस्ट तो नहीं हो रहा है । यहां पर बहुत कुछ कहा गया कि यह प्लन्डरिंग विभाग है, वेस्ट डिपार्टमेंट है । मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, मैं जिस वक्त इस विभाग से अलग था उस वक्त मेरी भी कुछ ऐसी भावना थी लेकिन जितना

[श्री गिरधारी लाल]

ही में इसके नजदीक आया मैंने उन बातों को देखा और एक कम्पेरेटिव दृष्टि से भी देखा और यह भी देखा कि हमारे प्रदेश में जितने भी लोकल बाडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, टाउन एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं या और दूसरी स्टेट्स हैं उनके यहां जो काम होता है, उन के मुकाबले में हमारे यहां काम अच्छा और सस्ता होता है या नहीं, हमारे पैसे में काफी काम मिकदार में और क्वालिटी में होता है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे यहां खामियां हैं। थोड़ी देर के लिये म पूछूंगा--हमारे बहुत से भाई हैं जो बहुत से काम करते हैं, कुछ भाई फार्म्स आदि करते हैं बड़े-बड़े फार्म, मैं उन से पूछूंगा कि उनको उनमें कितनी कामयाबी हो रही है, वह सब यही कहते हैं कि काम ठीक नहीं चलता, नौकरों के द्वारा काम चलता है इसलिये सफलता कम है, खुद नहीं देख पाते। मैं या मेरे स्थान पर कोई भी व्यक्ति सूबे भर के कामों को स्वंय नहीं देख सकता। मैं तो आप की और सदन के एक-एक सदस्य की आंख से हर चीज को देखता हूं और आप की सलाह से ही आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं।

जहां तक करप्शन या भ्रष्टाचार की बात है उस को हर तरह से दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि यह केवल वेस्ट डिपार्टमेंट है और काफी बरबादी होती है यह कहना एक प्रकार की ज्यादती है और कम से कम ऐसी बात कहना मुनासिब नहीं है।

ठेकेदारी प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक-दो स्थान पर हमने खुद तजुर्बे के तौर पर कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा काम कराना चाहा है और अलमोड़ा और मेरठ में इसका प्रयोग हो रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में अपने मुख्य अभियन्ता को आदेश दिया है कि वह जितने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स हैं वह अपने यहां कुछ काम ऐसे निकालें कि जो सोसाइटियों के द्वारा कराये जा सकें। उसकी एक डिटेल्ड स्कीम जैसे-जैसे हमें कामयाबी होगी, हम इस विषय में बनायेंगे और बाद में इस दिशा में कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत से साथियों ने यह भी कहा कि यह जो ठेकेदारी सिस्टम है, यह जो व्यक्तिगत एन्टरप्राइज है इसको खत्म कर दिया जाय। मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस चीज का स्वागत करूंगा। लेकिन केवल एक विभाग से ही उनका निकालना पर्याप्त नहीं है जब तक कि पूरे समाज के ढांचे को हम नहीं बदलते, जब तक सभी जनता उस ओर कदम नहीं बढाती, तब तक हमारे ऐसे कदम क्लेश में आयेंगे और हम पर प्रेसर पड़ेगा और कुछ न कुछ खामियां हमारे सामने आयेंगी। जहां तक होता है हर काम के लिये हम ठेकेदारों के भरोसे नहीं रहते, बहुत से काम ऐसे हैं जिनको सरकारी कर्मचारी स्वयं करते हैं। लेकिन तमाम काम हम सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं छोड़ सकते, मुमकिन है उस हालत में और भी अधिक शिकायतें हों।

पेमेंट के विषय में भी और दूसरी बहुत सी बातें कही गयीं। इन सब बातों को मैं देखूंगा और जो कुछ भी सुधार हो सकेगा, वह सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ पुलों और कुछ सड़कों की बात कही गयी। वह तो मैं समझता हूं कि आगरे से एक बात उठी है। पता नहीं उस बात में कहां तक तत्व है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आगरे की बात नहीं मानी जानी चाहिये। कौन कहता है कि पुलों की जरूरत नहीं है सूबे के अन्दर? आज स्थान-स्थान पर पुलों की जरूरत है। कोई नहीं पसन्द करता कि जमीन के दो टुकड़े हो जांय, नदी के जरिये या किसी तरह से दो हिस्से अलग हो गये हों तो वह सम्बन्धित न किये जायं। इस तरीके से जहां भी पुलों की जरूरत हो वहां पुल तो बनाना ही पड़ेगा। श्री दीनदयालु शास्त्री जी ने कुछ कहा कि वहां का पुल वहां दे दिया जाय। तो खैर, ऐसा तो नहीं हो सकता, वह तो पुल वहीं रहेगा। लेकिन दीनदयालु जी ने जो कुछ सड़कों की बात कही है तो उन सड़कों की तरफ हम ध्यान देंगे।

एक सदस्य--चुनाव क्षेत्र की बात बतलायी थी, आपके ?

श्री गिरधारी लाल--हां, वह चुनाव क्षेत्र की बात बतलायी जो मेरा पहला चुनाव क्षेत्र था। अब वह मेरा चुनाव क्षेत्र नहीं है..... (व्यवधान) हां, इस वक्त पूरा सूबा मेरा

चुनाव क्षेत्र है। सी० सी० ट्रैक्स के लिये कुछ बातें कही गयी कि सौ फुट चौड़ी ट्रैक्स बनाई जा रही हैं। मैंने अभी मालूम भी किया था और खुद मेरी यह राय थी कि अगर १००-१०० फुट की ऐसी ट्रैक्स हैं तो वह गांव के अन्दर विलेज रोड्स में मुनासिब नहीं होंगी। आजकल जब जमीनों की इतनी कमी है तो अगर वह इससे कुछ छोटी भी बनें तो कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे पता लगा कि ४० फुट और ६० फुट के अन्दर ही अन्दर हम वह ट्रैक्स बना रहे हैं। सबको पता है कि वैसे सड़कें हमारी १२ फुट, १४ फुट या १५ फुट की होती हैं लेकिन दोनों तरफ कुछ जगह छोड़नी भी पड़ती है और फिर कुछ मिट्टी निकालने के लिये भी जमीन छोड़ी जाती है। तो इस तरह ४० फुट तक हमें हर हालत में छोड़ना पड़ेगा। ४० फुट और ६० फुट के बीच में वह होंगी। यह भी हो सकता है कि कल को वह प्राविंशियल हाई वे बन जांय, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर वह ६० फुट तक बनायी जांय तो कोई हर्ज नहीं मालूम पड़ता।

स्टार ऐंड ग्रिड, फारमूले के बारे में कुछ कहा गया। मैं खुद इस बात से सहमत हूं और अब तो हमारे यहां के जो मुख्य अभियन्ता हैं और जितने हिन्दुस्तान के और चीफ इंजीनियर्स हैं सब ने मिल करके यह तय किया है कि नये सिरे से इस स्टार एंड ग्रिड फारमूले को योजना के आधार पर बदलना होगा, वह ठीक है। जब कि हम इतनी सड़कें बना चुके तो हमको और सड़कें बढ़ानी चाहियें। तो और सड़कें बढ़ेंगी। अभी तो पांच मील के दायरे में एक आध पक्की सड़क मिलती है और बाद में यह होगा कि दो मील के दायरे में कोई न कोई पक्की सड़क मिल जायगी। यह भी कहा गया कि कहीं सड़कें कम हैं, कहीं ज्यादा हैं। यानी स्टार ऐंड ग्रिड फारमूला पूरे तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो उस फारमूले को एक आयरन राड की तरह से तो नहीं माना जा रहा है। हो सकता है कि लखनऊ में या कुछ और ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां कि कम सड़कों की जरूरत हो और कहीं ज्यादा सड़कों की जरूरत हो सकती है। तो उसके मुताबिक कोशिश की जायगी। दो-चार जिले पूरे राज्य के अन्दर इस प्रकार के होंगे जहां कि दस-बीस मील सरप्लस सड़कें हों और कुछ जिले ऐसे भी हैं जैसे मुजफ्फरनगर वगैरह हैं जहां कि डेफिसिट है। मुझे खुद इस बात का खयाल है और जब भी धन उपलब्ध होता है उस वक्त हम उसके लिये कोशिश करते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल---लखीमपुर-खीरी भी ऐसा ही है।

श्री गिरधारी लाल---उसके बारे में तो कहा जाता है कि वह प्रदेश से बाहर है।

एक बात और मैं कहना चाहता था। कुछ थोड़ी-सी गलतफहमी हो जाती है। बलिया या किसी जगह के सिलसिले में कहा गया कि वहां पर सड़कों का निर्माण बाद में होता है और मकान पहले बन जाता है। उपाध्यक्ष महोदय के कालोनी शब्द से मुझे वह बात याद आयी। लेकिन मुझे पता नहीं, इस विभाग की तरफ से ऐसा नहीं हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा जहां पर बड़े पुल इस वक्त बन रहे हैं वहां तो इस किस्म की बात है एक आध क्वार्टर हम बनाते हैं जिसमें ओवरसियर, गैंग वगैरह मौके पर रहते हैं और बाद को जब टोल वगैरह वसूल करना होगा तो लोगों को वहां रहना होगा उस वक्त वह काम में आयेंगे। लेकिन निर्माण विभाग की कोई ऐसी कालोनी या यह कि उनके लिये सरकारी धन से कोई विशेष बिल्डिंग इस प्रकार की बनायी जाती हो, ऐसा कहीं नहीं है। मैं समझता हूं कुछ गलतफहमी हो गयी है जिसकी वजह से यह ख्याल हुआ है।

[श्री गिरधारी लाल]

कुछ भवनों के निर्माण के बारे में कहा गया। मैं उस बात से सहमत हूं और मैं समझता हूं मेरी जिम्मेदारी कैबिनेट का मेम्बर होने की हैसियत से है। लेकिन जहां तक भवनों का सम्बन्ध है यह अलग-अलग विभाग के हैं। कुछ मेडिकल विभाग के हैं, हेल्थ डिपार्टमेंन्ट के हैं, ऐजूकेशन डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस विभाग के हैं। तो वह लोग अपनी-अपनी जरूरतें खुद महसूस करते हैं और जानते हैं। लेकिन वह काम पी० डब्ल्यू० डी० के सुपुर्द करते हैं जिसको यह विभाग करता है। इस तरीके से वह सब काम हो जाते हैं। यह ठीक है कि आज जितना भी ज्यादा से ज्यादा धन हमारा इन कामों में लग जाय तो अच्छा है। पिछले वर्ष तो कुछ इस प्रकार का रुपया कैबिनेट ने बचाया था और वह बचा था सामान वगैरह न मिलने के ख्याल से। और जैसा मैंने अभी बताया कि १ करोड़ ३५ या ३६ लाख रुपये की एक अतिरिक्त योजना और बनायी गयी थी। तो वह जो रुपया आया था वह उसी दिशा से उस रुपये की बचत हुई थी जो कि सड़कों के निर्माण में खर्च हुआ। मैं समझता हूं हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको जो गलत-फहमियां थीं वह साफ हो गयी होंगी और अब वे बगैर किसी हुज्जत के इन अनुदानों को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, लेखा शीर्षक ५० के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों की स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ५,७०,९८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक-निर्माण कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि के वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १३,०४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ७६,९१,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी-लेखा के अन्तर्गत ८,४३,६५,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५३ मिनट पर सोमवार, १७ मार्च, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ;
१५ मार्च, १९५८ ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० ए स० यू० बी०, ए० पी०--२ एल० ए०--१९५८-८३५ ।